हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

1 मार्च 1979

खण्ड 1 अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 1 मार्च 1979

पृ0 सं0

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2) 23

अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2) 31
ध्यानाकर्शण सूचना – रावी व्यास के पानी का मुनासिब ढंग से इस्तेमाल करने और एस0वाई0एल0 नहर को फौरन बनाने सम्बंधी	(2) 39
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(2) 41
गैर सरकारी संकल्प– (1) स्वर्गीय चोधरी छोटू राम की जन्म भाताब्दी मनाने के लिये एक समिति गठित करने सम्बंधी	(2) 45
(2) राज्य में रहने वाले ि ाक्षित हरियाणा अधिवासी व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने सम्बंधी	(2) 54
(3) पंजाब तथा हरियाणा के मध्य रावी–व्यास के अतिरेक पानी के विभाजन तथा पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक नहर के भाग को कम से कम समय में निर्मित करने सम्बंधी।	(2) 72

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 1 मार्च 1979

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Sponsoring of name for new employment by Employemnt Exchanges.

***866. Chaudhri Peer Chand:** Will the Ministor for Cooperation and Dairy Development be please to state-

(a) whether it is essentioan that the names of those persons who are employed in the Government Service be sponsored by Employment Exchanges;

(b) whether it is also a fact that a person can be employed for less than three months without getting his name sponsored from an Employemnt Exchange;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative whether the departments at first generally make recruitment

for three months and later on call the perosn from the Employment Exchanges and reject them after taking interview and employment is given to those persons who are already employed by them; and

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative whether there is any proposal to stop this irregularity so that the unemployed persons could be saved from inconvenience, harassment and from incurring travelling expenses ?

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) तथा (घ) उपरोक्त (ख) के कारण किसी उत्तर की आव यकता नहीं।

चौधरी पीर चन्द: अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में हर जगर पर 'न' ही कहा है। आज हर विभाग में तीन महीनों के लिये लगाये गये व्यक्तियों को रेगुलर किया जा रहा है। मैं आपके द्वार मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को हटकार एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा रेगुलर अप्वायंटमैंटस की जाएगी ताकि बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सके ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, तीन महीने के लिये नौकरी पर लगाने के लिये नोटीफिके ान हुआ है इसलिये एम्पलायमैंट एक्सचेन्ज द्वारा नाम आने की आव यकता नहीं है,

लेकिन फिर भी हमने विभागों को हिदायतें दे रखी हैं कि तीन महीने के लिये भी अगर किसी को लगाना हो तो एम्पलायमैंट एक्सचैंज के द्वारा नाम मंगवा कर नियुक्त किया जाए।

श्री फतेह चन्द विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके नोटिस में यह बात है कि उनके जितने भी विभाग हैं, अदायरे हैं, उन में बिना एक्पलामैंट एक्सचेंज से नाम लिये लोगों को लगाया जा रहा है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले एप्लीके ान्ज मांगी जाती है फिर बाद में इंटरव्यू लेकर आदमी लगाये जाते हैं।

चौधरी खुर ाी अहमदः स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये मिनिस्टर साहब से यह मालूम करना चाहूंगा कि (सी) और (डी) कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इनके तहत 1976–77 और 1977–78 में कितने कितने आदमी अप्वायंट किये गये थे, क्या इस बारे में साल वाईज बता सकेंगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं साल वाईज सूचना दे देता हूं। 1976 में मैट्रिक, ग्रेजुएटस और बी0काम0 के 21339 लड़के लगाये गये हैं। सन 1977 में 24630 और 1978 में 27119 लड़कों को सर्विस में लिया गया है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, सरकारी विभागों में कई ऐसे लोग हैं जिनको तीन तीन महीनों के लिये एडहाक बेसिक पर रखा हुआ है और एक दिन की ब्रेक देकर फिर लगा लिया जाता है। इस प्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दो दो साल की नौकरी हो चुकी है। क्या मन्त्री महोदय बतांएगे कि ऐसे लोगों को रेगुलर करने के लिये कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में भारत सरकार का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि जिसको 240 दिन सर्विस करते हुए हो जाएं उस आदमी को रेगुलर कर दिया जाये। इस आधार को हमने लागू किया हुआ है।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो लोग नौकरी न मिलने के कारण से ओवरएज हो गये हैं और उनके नाम भी एम्पलायमेंट एक्सचैंज में दर्ज हैं, क्या उनके बारे में भी सरकार कोई पग उठाने का विचार रखती है ताकि उन लोगों को सर्विस मुहैया की जा सके ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ओवर एज तो ओवर एज ही समझा जाएगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहत हूं कि कोआपरेटिव बैंक,

कुरूक्षत्र में जो गलत अप्वायंटमैंटस की गई है, उसके बारे कोई इंक्वायरी करवाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री अध्यक्षः यह सवाल मूल सवाल से संबंधित नहीं है। पोहलू साहब आप इसके लिये अलग से नोटिस दें।

श्री लहरी सिंह मेहराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार जितनी भी रिकरूटमैंटस कर रही है, क्या उसमें हरिजनों की रिजर्वे ान का भी ख्याल किया जा रहा है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सप्लीमेंट्री का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आनरेबल मैम्बर साहेबान, की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी सर्विस देने का सवाल आता है, हरिजनों की रिजर्वे ान का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है।

चौधरी पीर चन्दः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब मेरे प्र न के उत्तर में दिये हैं, मुझे उससे बिल्कुल तसल्ली नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा उन से यह जानना चाहत हूं कि सरकार जिन लोगों को तीन तीन महीनों के लिये सर्विस में रख लेती है और बाद में उनको रेगुलर कर दिया जाता है, क्या इस बारे में मन्त्री महोदय कोई वि वास दिलायेंगें कि तीन तीन महीनों के लिये रखने की बजाये एम्पलायमैंट एक्सचैंज से नाम

लेकर लोगों को नौकरी में रखा जाये ताकि अनएम्पलामैंट की समस्या हल हो सके ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया कि तीन महीने के बाद रेगुलर होने की कोई प्रोवीजन नहीं है। जिस को सर्विस में लगे 8 महीने या 240 दिन हो जाएं उन्ही लोगों को रेगुलर कर दिया जाता है।

स्वामी अग्निवे Iः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से स्पश्ट रूप में यह जानना चाहता हूं कि सरकार के बहुत से विभागों में बहुत से बोर्डों में, बिना एम्पलायमैंट एक्सचैंज से नाम लिये सीधी भर्ती की जा रही है। क्या ऐसे आदमियों को इररैगुलर करार देकर आगे से यह भर्ती नियम बनाकर एम्पलायमैंट एक्सचैंज द्वारा नाम मंगवा कर की जाएगी ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इसका वास्तविक सवाल से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, आपको इसके लिये अलग नोटिस देना चाहिये।

Losses suffered by Haryana Matches Ltd.

***869. Shri Sumer Chand Bhatt:** Will the Minister for Industrial be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Haryana Matches Ltd., a State Government Undertaking has been running into losses since its inception in 1971;

(b) if so, the total amount of loss suffered since it started funding to date; and

(c) if reply to part(a) above be in the affirmative, whether the Government have enquired into the reason for the continuous losses, if so, the details thereof and action taken, if any, thereon ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन):

(क) जी हां।

(ख) 31—12—78 तक लगभग 9.85 लाख रुपये की हानि।

(ग) जी हां। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा कम्पनी ने इस बारे में अध्ययन किया है। मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं :—

1. ईकाई का अनार्थिक आकार को होना।

2. आव यक कच्चे माल की कमी।

3. निपुण श्रमिकों का उपलब्ध न होना।

4. ऊंची केन्द्रीय एक्साईज डयूटी का होना।

कम्पनी के सुधार के लिये आव यक पग उठाये गये हैं।

श्री सुमेर चन्द भट्टः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अपने जववब में यह माना है कि जब से यह फैक्टरी लगी है, अब तक 10 लाख रुपये का नुक्सान हो चुका है और साथ ही उन्होंने अपने उत्तर के पार्ट (बी) में यह कहा है कि उन्होंने इस बारे में अध्ययन भी किया है और अब इस फैक्टरी की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिये सरकार ने कई प्रकार के कदम भी उठाये हैं मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि नुक्सान के अध्ययन का जो उनका प्रोसेस है, वह कब भुरू किया गया, कितने अर्सा तक चला है और कब सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि फैक्टरी नुक्सान में जा रही है और इसकी इम्प्रूवमैंट के लिये जल्दी कोई कदम क्यों नहीं उठाये गये ?

डाक्टर मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय,यह सारी बातें पहली सरकार के वक्त की थी लेकिन फिर भी मैं आनरेबल मैम्बर साहेबान, की जानकारी के लिये बता देता हूं कि यह कम्पनी 1970 में बजद में आई थी और इसकी प्रोडक ान 1973 में भुरू हुई, तब से बीन करवाई और पहले हाकिमों ने जिस बेरहमी के साथ पैसे को बरबाद किया, उसको रोकने का बन्दोबस्त किया। माचिसों की तीलियां तो जमनानगर में बनती थी और उन पर दवाई बूरिया में लगती थी। फिर लौट कर आती थी तब कहीं जाकर पैकिटस तैयार होते थे लेकिन अब हमने यह सारा सिस्टम बदल कर सारा

काम एक ही जगह भुरू कर दिया है। पहले वाला प्रोसेस खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं,हमने बाकायदा मैनेजिंग डायरैक्टर को यह हिदायत भी जारी कर दी है कि इस काम में जितनी फियत ाारी की जा सकी है, की जाए। हमारे पास जो जमनानगर में भौड था, वह हमने भाड़े पर दे दिया है, ताकि सरकार की आमदनी बढ़ सके। हमने खादी ग्राम उद्योग से भी इस बारे में बात की है ताकि हमें सस्ते दर से कर्जा मिल जाए। इसके इलावा हमने यह भी किया है कि इस उद्योग की गणना छोटे उद्योगों में की जाये। इससे पहले इस पर सेल्ज टैक्स की भारह लगती थी, इब वह भी एग्जम्पट करा दी है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कदम सरकार उठाने जा रही है ताकि हमारा यह यूनिट वायेबल हो जाए।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस फैक्टरी में गवर्नमैंट की टोटल इनवैस्टमैंट कितनी है ?

डाक्टर मंगल सैनः इस पर टोटल इनवैस्टमैंट साढ़े बारह लाख रुपये की है। स्पीकर साहब, इमसें जो घाटा है उसके लिये गुनाह तो कोई कर गया लेकिन भुगतना हमें पड़ रहा है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः इस फैक्टरी के घाटे में चलने के चार कारण मन्त्री महोदय ने जो बताएं हैं इनमें से तीन तो ऐसे हैं जो कि फैक्टरी लगाने से पहले देखे जाने चाहिये थे। मैं यह

जानना चाहती हूं कि बूरिया में यह फैक्टरी लगाने से पहले क्या यह नहीं देखा गया था कि यहां पर यह यूनिट वायेबल भी रहेगी या नहीं ?

डाक्टर मंगल सैनः मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उस समय की हकूमत ने ये बातें कन्सिडर नहीं की थी, बड़ी गलती का काम किया था।

श्रीमती सुशमा स्वराजः क्या उद्योग मंत्री यह मानते हैं कि यदि इस यूनिट को बूरिया से बदल कर कहीं और ले जाया जाये तो इसकी वायेबिलिटी बढ़ जायेगी ?

डाक्टर मंगल सैनः सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें गरीब आदमी रोजगार पर लगे हुए हैं। इसमें 25 परसैंट एम्पलाई हैं और दो अढ़ाई सौ कैजुअल लेबरर्ज हैं। हमारा ऐसा विचार है कि हम इसको वहीं पर रख कर वायेबल बना देंगे।

श्री जगन नाथः जब से यह फैक्टरी लगी है इसमें घाटा बढ़ता ही गया है। अब इस समय इसमें 9 लाख 85 हजार का घाटा है। इसके बावजूद अबअ इसमें चेयरमैन के रूप में एक आदमी लगा हुआ है जिस पर पांच सात हजार रुपये महीना खर्च होता है तो इससे इसमें और घाटा पड़ेगा। क्या इस चीज को देखते हुए इसको बन्द करने की कोई स्कीम है ?

डाक्टर मंगल सैनः इसको बन्द करने की कोई स्कीम नहीं है।

चौधरी संत कंवरः किसी भी कारखाने को फायदे में चलाने के लिये यह जरूरी है कि उसका सबसे बड़ा प्र ाासनिक अधिकारी या मैनेजिंग डायरैक्टर टैक्नीकल हैड होना चाहिये। क्या इस माचिस फैक्टरी का एम0डी0 टैक्नीकल हैड है या कोई आई0ए0एस0 अफसर है ?

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, इसमें टैक्नीकल मामले की कोई बात नहीं है लेकिन यह बात ठीक है कि पीछे हमारा एडमिनिस्ट्रे ान खर्चीला रहा है। अब हम कोि ा ा कर रहे हैं कि कम से कम खर्चे में काम चलाया जाये।

श्री मूल चन्द मंगलाः इस फैक्टरी की जो बिल्डिंग है वह टूटी हुई है और इस वजह से वहां का रा मैटिरियल भी खराब हो जाता है। क्या इस बिल्डिंग को बदल दिया जाएगा या इसकी मुरम्मत करवाई जाएगी ?

डाक्टर मंगल सैनः माननीय सदस्य ने जो बात मेरे नोटिस में लाई है, मैं उसकी इन्क्वायरी करवा लूंगा और जो आव यक कार्यवाही करनी होगी वह की जाएगी।

चौधरी हरस्वरूप बूराः उद्योग मंत्री जी ने अभी बताया कि यह फैक्टरी बन्द नहीं की जाऐगी। क्या मंत्री जी कोई ऐसा स्टैप उठाने जा रहे हैं जिसिसे इसमें घाटा न हो ?

श्री अध्यक्षः इस बारे में मन्त्री महोदय जवाब दे चुके हैं।

Introduction of Home Science Subject in Schools

***872. Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce the subject of Home Science in the Schools also in the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialise ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य)

(ए) जी नहीं, फिर भी गृह विज्ञान का विशय राज्य के कुछ कन्या उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक स्वैच्छिक विशय के रूप में पढ़ाया जाता है।

(बी) प्र न नहीं उठता।

चौधरी संत कंवरः पिछली सरकार के द्वारा जो ट्रेनिंग स्कूल खोले गये हैं उनमें हजारों लड़कियों ने चन्दे देकर ट्रेनिंग प्राप्त की और वे आज कई सालों से बेरोजगार बैठी हुई हैं। ि ाक्षा मंत्री जी उन लड़कियों को रोजगार देने का प्रबन्ध कब तक करेंगे ?

श्री हीरा नन्द आर्यः इस प्र न का मेन प्र न से कोई संबंध नहीं है। माननीय सदस्य अलग से नोटिस दें, जवाब दे दिया जाएगा।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का इससे पूरा संबंध है। मेरा सवाल यह है कि होम साइंस की जो लड़कियां ट्रेनिंग लेकर घर बैठी हुई हैं, उनको कब तक रोजगार दे दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्षः मेरा ख्याल है इसके लिये अलग नोटिस चाहिये।

श्रीमती भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदय, जब ि ाक्षा मंत्री जी को पता है कि जे0बी0टी0 और होम साईंस की ट्रेनिंग लेकर हजारों लड़कियां बेकार अपने घरों में बैठी हैं तो इन्होंन इतना नकारा उत्तर क्यों दिया ? मैं यह जानना चाहती हूं कि उनके रोजगार का प्रबंध क्या ि ाक्षा मंत्री जी करेंगें और कोई और करेगा ? ि ाक्षा मंत्री जी यह बोझ अपने ऊपर लेने को तैयार क्यों नहीं हैं ?

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नहीं है।

श्रीमती भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ठीक सवाल है, आपको इसका जवाब दिलवाना चाहिये।

चौधरी गंगा रामः अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि होम साईंस का सबजैक्ट स्कूलों में आप ानल पढ़ाया जाता है और आप ानल का मतलब यह है कि अगर दो चार विद्यार्थी पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हरियाणा के स्कूलों में होम साईंस का सबजैक्ट कम्पलसरी नहीं है तो इस सबजैक्ट की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है और पब्लिब का लाखों रुपया खर्च क्यों करवाया जाता है ? पिछले साल भी मैंने कहा था कि यह पैसा मिस यूज हो रहा है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का इससे कोई संबंध नहीं। आई0टी0आई0 उद्योग मंत्री जी के अंडर है, अगर ये अलग से नोटिस देंगे तो जवाब अव य दिया जाएगा।

चौधरी संत कंवरः मंत्री जी ने कहा कि आई0टी0आई0 उद्योग मंत्री जी के अंडर है। उद्योग मंत्री जी लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी ि ाक्षा मंत्री जी की नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी ि ाक्षा विभाग पर आ जाती है। उधर उद्योग मंत्री जी तो ट्रेनिंग दिये जा रहे हैं और ि ाक्षा मंद्यी जी उनकी जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं हैं तो यह सिलसिला कब तक चलता रहैगा ? दोनों मंत्रियों में से कोई भी मंत्री इस बात का जवाब दें।

श्री अध्यक्षः होम साईंस की ट्रेनिंग गृहस्थी का काम चलाने के लिये होती है। अगर मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह दें।

श्री हीरा नन्द आर्य: जब अलग से नोटिस दिया जाएगा तो इसका जवाब दिया जाएगा।

Special Facilities to the unanimously constituted Panchayats

***883. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Development and Pandhayats be please state-

(a) whether there is any village in Block Jind where the Panchayat elections were never held and the Panchayat has always been constituted unanimously; and

(b) if reply to part(a) above the in the affirmative, whether the Government propose to give some special facilities to that village or to declare it a Model Town ?

विकास मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(ए) खण्ड जीन्द में ग्राम पंचायत दरियावाला, जीवनपुर तथा श्री रागखेड़ा ऐसी पंचायतें हैं जिनमें चुनाव सर्वसम्मपति से भूतकाल में होता रहा है।

(बी) हां। इन ग्राम पंचायतों को पुरसकार के तौर पर 5000/—रुपये की नकद रा ि ा प्रति पंचातय को दी जा रही है। इन ग्राम पंचायतों को मॉडल टाउन का आद र्ा गांव घोशित करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री मांगेराम गुप्ताः मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि वह पिछली पंचायतो ंके इलैक ान कें संबंध में दिया है। मेरा सवाल यह था कि जो पंचायतें पहले से ही यूनैनीमसली इलैक्ट होती आई हैं क्या उनको कोई स्पै ाल फैस्टिलटीज देने का विचार है। इसके उत्त में मंत्री जी ने कहा है कि सरकार उनको 5 हजार रुपया दे रही है। लेकिन इसमें भेदभाव बरता जा रहा है। मेरे ख्याल से जब से नये चुनाव हुए हैं तब से उनको कोई रुपया नहीं मिला। स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय से मेरी दरखास्त है कि उनको रुपया दिलाया जाये।

श्री अध्यक्षः यह सवाल नहीं है, सुझाव है।

कंवर राम पाल सिंहः मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 5 हजार रुपया देने की बात है, क्या किसी पंचायत को अब तक यह पैसा दिया भी गया है या सिर्फ फैसला ही है ?

ठाकुर बीर सिंहः अभी तक किसी पंचायत को इसके मुताबिक पैसा नहीं दिया गया है। इसकी वजह यह है कि पहले सिर्फ 750 रुपये दिये गये थे अब साढ़े साल सौ से बढ़ाकर 5

हजार रुपये कर दिया गया है। यह जो बढ़ाकर 5 हजार किया गया है इसका बजट में कोई प्रोवीजन नहीं था। इसके लिये प्रोसीडिंग चलाई गई, फाईनैंस डिपार्टमैंट की मंजूरी के लिये केसी भेजा। जब यह फाईल भेजी तो उन्होंने तय किया कि यह रा ि चार इन्सटालमैंटस में दी जाये। इस हिसाब से यह पैसा चार साल में पूरा हो जायेगा। लेकिन इसके बारे में मैंने आबजैक ान उठाया है कि पांच हजार रुपये की रकम अगर चार साल में दी जायेगी तो इससे पंचायतों का डिवैल्पमैंट का काम पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे आबजैक ान को कंसीडर किया गया। 27–2–79 को चीफ मिनिस्टर साहब और फाइनैंस मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में यह तय कर लिया गया कि यह सारा पैसा 31 मार्च 79 तक दे दिया जाये।

श्री फतेह चन्द विज: जैसे सवाल में पूछा गया है कि क्या सरकार यह दरूस्त नहीं समझतील कि जिन गांवों में पंचायतें सर्व सम्मति से चुनी गई हैं, उनकी लिस्ट बना कर उनका माडल गांव बना दिया जाए ?

श्री अध्यक्ष: यह सुझाव है, सवाल नहीं है। इसके बारे में मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं।

चौधरी सरदार खा: मैं डिवैल्पमैंट मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत से अगला कदम ब्लाक समिति का आता है। क्या उकसे बारे में कोई कदम उठाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्षः इसका सवाल से कोई संबंध नहीं है?

चौधरी लाल सिंहः यह जो पांच हजार रुपया दिया जायेगा यह किस के सुपुर्द किया जायेगा और किस काम पर खर्च होगा ?

श्री अध्यक्षः यह रुपया पंचायतों को दिया जायेगा।

श्रीमती सुशमा स्वराजः मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आद र्श गांव बनाने का क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है ? कुछ गांवों मकें पंचायतें सर्व सम्मति से चुनकर आद र्श स्थापित किया है। अगर ऐसे गांवों को आद र्श गांव नहीं बनाया जायेगा तो और कौन से गांवों को बनाया जायेगा ?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

Mr. Speaker: Order please (Interruptions)

श्री जगन नाथः यह महकमा पहले सदार तारा सिंह के पास था, फिर सरदार लछमन सिंह के पास आ गया और अब इनके पास आ गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह सवाल नहीं है।

Re-opening of Liquor Vends

***896. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether it is a fact that liquor vends in Gram Panchayat Badshahpur and notified

area of Ferozepur Jhirak have been re-opened, if so, the reasons therefor ?

आबकारी व कराधान मंत्री (चौधरी भोर सिंह): परचून देसी भाराब ठेका बाद ाहपुर तथा फिरोजपुर डिरका के लाईसेंसिज वश्र 1978–79 के लिये 19–3–1978 को उपायुक्त गुड़गांव की उपस्थिति में लाटस निकालते हुए अलाट किये गये थे परन्तु इन ठेकों के अलाटीज द्वारा इनकी लाईसैंस फीस व प्रतिभूति की रा ि ा जमा नहीं करवाई गई थी। इसके उपरांत उक्त दो ठेकों, साथ में अन्य 24 ठेकों के लाईसैंसिज अलाट करने हुत नये सिरे से प्रार्थना पत्र मंगवाये गए थे और इनके लाईसैंसिज 23–10–78 को उपायुक्त गुड़गांवा की उपस्थिति में लाटस निकालते हुए अलाट कर दिये गये थे।

स्वामी आदित्यवे ा: सरकार की यह नीति है कि जिन ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव आ जाएगा वहां पर भाराब के ठेके नहीं खोले जायेंगे। बाद ाहपुर और फिरोजपुर झिरका की पंचायतों से ऐसे प्रस्ताव पास होकर आ चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी वहां भाराब के ठेके खोले गये हैं इस प्रकार सरकार ने 24 नए ठेके और खोले हैं। क्या सरकार बतायेगी कि नये ठेके खोलने का क्या कारण है ?

चौधरी भोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, भाराब के ठेके हर साल पहली अप्रैल से चालू किए जाते हैं। जब बाद ाहपुर की पंचायत से रैजोल्यू ान प्राप्त हुआ इससे पहले यह ठेका दिया जा

चु का था। 12–4–1978 को यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। वश्र 1977–78 में टोटल 588 ठेके थे, जिनमें से 188 पंचायतों से रैजोल्यू ान आये थे जिसमें से 123 प्रस्ताव मंजूर कर लिये गये और 34 को इस बिनाह पर रिजैक्ट कर दिया था कि वहां पर नाजायज भाराब का धंधा होता था और 31 ठेके ऐसे थे जिनकी किीस ने बोली नहीं दी थी। जहां तक 24 नये ठेके खोलने का ताल्लुक है ये ठेके इसलिये दोबारा नीलाम किये गये थे क्योंकि ठेकेदारों ने लाईसैंस फीस समय पर जमा नहीं की थी, इसलिये उनकी नीलामी दोबारा की गई।

चौधरी लाल सिंहः पहले जो कांग्रेस पार्टी की बदनाम पंचायतें थीं क्या उनको हटा कर अगर नई पंचायतें रैजोल्यू ान भेजेंगी तो उन रैजोल्यू ान्ज को कब तक लागू किया जायेगा ?

चौधरी भोर सिंहः जब भी रैजोभ्यू ान आएगा, लागू कर देंगे।

श्री फतेह चन्द विजः 1–4–1978 से ठेके लागू होते हैं लेकिन कहा गया है कि ठेकेदारों ने रुपया जमा नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ठेके 7 महीने बंद रहे और 23–10–78 को दोबारा नीलामी की गई। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 7 महीने सरकार क्या करती रही ?

चौधरी भोर सिंहः यह इस अवधि में प्रौसेस में रहा।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, जिन लोग को ठेके अलाट किए गऐ थे, उन्होंने अपने ठेके अपने आप न खोलकर आगे किसी दूसरे को बेच दिए हैं। अगर हम मन्त्री महोदय के नोटिस में लाएं तो क्या वे इसकी इन्क्वायरी करवाएंगे ?

चौधरी भोर सिंहः बिल्कुल इन्क्वायरी करवायेंगे।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, सरकार ने 25 फीसदी ठेके बन्द करने का निर्णय लिया था। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 25 फीसदी ठेके बन्द हो गए हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्षः यह सवाल नहीं बनता।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, बाद ााहपुर गांव वालों का रैजोल्यू ान 11–4–78 को आया था, यह सही बात नहीं है। सही बात यह है कि 17 मार्च 1978 को आया था। इसके बाद अगस्त में दूसरा रैजोल्यू ान भेजा था, दो रैजोल्यू ान पास करके भेजने के बावजूद भी वहां पर ठेका खोल दिया गया, क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि वहां पर ठेका क्यों खोल दिया ?

चौधरी भोर सिंहः अगस्त में जो रैजोल्यू ान आया वह 1 अप्रैल को लागू होगा। मैं माननीय विधायकों की सूचना के लिये बता देता हूं कि बाद ााहपुर में ठेका अगले साल बंद कर दिया जाएगा।

श्री जय नारायण वर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को भाराब के ठेके दिए जाते हैं, वे उस ठेके की आड़ में नाजायज भाराब निकालने का धंधा कर लेते हैं और नाजायज भाराब बेचनी भाुरू कर देते हैं क्या सरकार नाजायज भाराब की बिक्री को रोकने के लिये कोई सक्रिय कदम उठाएगी ?

चौधरी भोर सिंहः जहां से इस प्रकार की ि ाकायत आती है, उचित कार्यवाही की जाती है।

श्री देवी दासः क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि अगर म्युनिसिपैलिटी या नोटिफाईड एरिया कमेटी अपना रैजोल्यू ान पास करके भेज दे कि फलां जगह ठेका नहीं होना चाहिये, तो क्या सरकार रैजोल्यू ान को ध्यान में रखते हुए भाहरों से ठेके बंद करने का प्रयत्न करेगी ?

चौधरी भोर सिंहः न ााबंदी के लिये हमने 4 साल की हद मकरर्र कर रखी है। उसमें कार्यवाही हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका नम्बर भी आ जाएगा।

कंवर राम पाल सिंहः क्या मन्त्री महोदय बतायेंगें कि रैजोल्यू ान आने के बाद भी भाराब के ठेके बंद नहीं किए गए, ठेके खोलने के विरूद्ध रिपोर्ट आने पर भी ठेके खोलना बंद नहीं किया गय, क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इसका क्या कारण है ?

चौधरी भोर सिंहः चार साल में पूरी न ाबन्दी लागू करनी है, इसके इलावा हम कोि ा ा करेंगे कि नाजायज भाराब न बिके।

Levy on Canal Water

***951. Chaudhri Ganga Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the minimum number of times for which the canal water should be supplied to per acre land during one year so as to entitle the Government to levy the water charges ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): पानी दर के ि ाडयूल में निर्दिश्ट दरों के अनुसार फसल के आधार पर सिंचकों से पानी द लिया जाता है। सरकार द्वारा पानी दर लगाने के हक प्राप्त करने के लिये न्यूनतम का अधिकतम पानी की सप्लाई निर्दिश्ट नहीं है। कोई भी क्षेत्र जिस में नहारी पानी लगता है, उस पर पानी दर लिया जाता है।

चौधरी गंगा रामः मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसकी आखिरी लाईन में लिखा है –

"कोई भी क्षेत्र जिसमें नहरी पानी लगता है, उस पर पानी दर लिया जाता है।" इसका सीधा तात्पर्य यह है कि मान लो एक किल्ले में एक बूंद पानी दिया जाए तो भी किसानों से पैसे वसूल करने के लिये सरकार हकदार है। मैंने सवाल पूछा था कि

एक फसल को कम से कम कितनी बार पानी मिले जिसके पैसे सरकार किसान से वसूल करती है। मेरे कहने का तात्तपय्र यही है कि मान लो मेरे पास 50 किल्ले जमीन है जिसमें 25 किल्ले गेहूं बोई हुई है। गेहूं को कम से कम तीन या चार दफा पानी लगना चाहिये लेकिन लगता है सिर्फ 10 किल्ले में और वह भी एक दफा लगता है लेकिन सरकार पूरे पैसे चार्ज करती है। अगर एक ही दफा पानी लग जाए तो भी सरकार किसाने से 50 किल्ले जमीन के आबयाने के पैसे वसूल करती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या रूल्ज में कोई अमैंडमैंट की जाएगी कि किसान को एक फसल के लिये जितना पानी चाहिये, उतना देकर फिर पूरे पैसे वसूल किए जाएं ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः फिलहाल सरकार की जो नीति है, वह सवाल के जवाब में मैंने स्पश्ट की हैं। जहां तक अमैंडमैंट करने का ताल्लुक है, इस नीति में अमैंडमैंट होनी हैं या नहीं, इसके लिये 10–15 साल का अर्सा अव य लगेगा।

श्री अध्यक्षः रूल्ज में परिवर्तन करने के लिये क्या 10–15 साल चाहिये ? (हंसी एव व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अफसोस इस बात का है कि जो अपने आपको गांव में पैदा होने का दावा करते हैं, किसान हैं, वे नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा है कि इस सिस्टम को चेन्ज करने में 10–15 साल लगेंगे, सिस्टम चेंज करने की बात

कही है। हमको सिस्टम में चैंज करना चाहिये और यह तभी पौसिबल होगा जब सारे खाल पक्के हो जायेंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने कहा है कि सिस्टम 10–15 साल में चेंज करेंगे। मैं वजीर साहब को बताना चाहता हूं कि उन्होंने इलैक ान मैनिफैस्टों में यह लिखा है कि किसान का आबियाना मुआफ कर देंगे तो क्या सरकार तीन साल के अन्दर मुआफ कर देगी ? (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः ऐसा कहीं नहीं है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अगर एक फसल मैच्योर हो जाती है, उसके कटने के बाद जमीन बारानी रहती है और किसान अगली फसल तैयार करने के लिये उसमें पानी लगाता है ताकि अगली फसल वो सके लेकिन सरकार पहली फसल पर आबियाना भी वसूल करती है और अगली फसल का भी वसूल करती है। दोनों फसलों में से एक फसल का वसूल किया जाना चाहिये ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः फसल को ज्यों ज्यों पानी लगता है, सरकार आबयाना वसूल कर लेती है।

Mr. Speaker: May I request the Hon. Minister to kindly clarify the matter ? What has been asked is कि अगर गेहूं की फसल को कैनाल का सिर्फ एक ही पानी लगाया जाए और उसके बाद पानी न मिलने की वजह से फसल जल जाए,

खराब हो जाये तो क्या इन हालात में किसान से आबियाना वसूल किया जाएगा या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः तो भी लिया जाएगा।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, अगर एक किल्ले में पानी लगता है और 50 किल्ले के पानी के पैसे वसूल किए जाएं, तो यह किसान के साथ जुल्म है, यह किसान की सरकार है, इसको किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिये।

चौधरी खुर ीद अहमदः जैसा कि वजीर साहन ने स्पीकर साहब, को बताया कि सरकार आबियान वसूल कर लेती है, चाहे एक पानी लगे, चाहे फसल जल जाए, वसूल करना पड़ता है। इस इ ू को एग्जामिन करने के लिये क्या सरकार हाउस की एक कमेटी बनायेगी जो यह देखे कि किसानों के साथ यह ज्यादती क्यों हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मौजूदा नीति के मुताबिक ज्यों ही किसान अपनी फसल में पानी चाहे एक बार लगाता है, चाहे दा बारे लगाता है, सरकार पूरा आबियाना वसूल करती है। यह च्वायस तो है कि सरकार उसको चार पानी, तीन पानी, पांच पानी लगा दे (व्यवधान) भाखड़ा सिस्टम से हम 278 दिन पानी की सप्लाई करते हैं और जमना से 172 दिन के लिये पानी सप्लाई करते हैं। अगर किसी कारण से किसान की खड़ी फसल बिल्कुल तबाह हो जाए और एक पानी लगने के बाद खर्चा

डिक्लेयर हो जाए तो इन हालात में सरकार नीति यह है कि आबियाना मुआफ हो जाता है। आबियाने की जो इस वक्त नीति है, इसको बदलने की आव यकता सरकार नहीं समझती। ज्यों ही किसान के खेत को पानी लगेगा, सरकार अबियाना वसूल कर सकती है।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने 10–15 साल में नीति बदलने का विचार रखा है, 15 साल का तो बहुत लम्बा अर्सा होता है। यह बड़ा अहम सवाल है, इस पर खास तौर पर बहस होनी चाहिये और कम से कम आधे घंटे की डिस्क ान होनी चाहिये (व्यवधान)

कई सदस्यः आधा घंटा तो कम है, दो घंटे की डिस्क ान होनी चाहिये। (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री मूल चंद जैन): स्पीकर साहब, अभी तो गवर्नर एड्रैस पर बहस होगी, जनरल बजट पर भी बहस होगी। उस वक्त मैम्बर साहेबान, अपने विचार रख सकते हैं। इसलिये अगल से डिस्क ान करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह प्र न बहुत जरूरी है। इससे लाखों किसानों के भविश्य का वास्ता है। हाउस की जनरल फीलिंग यह है कि जिन किसानों की फसल को एक पानी मिलने के बाद दोबारा पानी नहीं मिलता और फसल खराब हो जाती है और उनसे आबियाना वसूल

कर लिया जाता है, यह किसानों के साथ अन्याय है। इसलिये अगर आप ठीक समझते हैं तो उचित टाईम अलाट करके इस पर डिस्क ान कर ली जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अगर हाउस की सैंसह है तो दो घंटे की डिस्क ान तो नहीं, आधे घंटे की डिस्क ान हो सकती है लेकिन जैसा कि जैन साहब ने बहा है कि अगर गवर्नर एड्रैस पर बहस करते हुए इस टौपिक पर डिस्क ान हो जाती है तो आधे घंटे की डिस्क ान की आव यकता नहीं होगी। अगर गवर्नर एड्रैस पर यह टौपिक डिस्कस नहीं होता है ..... (व्यवधान)

कई सदस्यः इस विशय पर अलग से डिस्क ान होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप लिखित रूप में मेरे पास भेज दें। (व्यवधान)

चौधरी हुक्म सिंहः स्पीकर साहब, कई बार किसान की पकी हुई फसल खराब हो जाती है, नहर टूट जाने से कई बार पानी नहीं दिया जाता लेकिन सरकार किसान से पूरा आबियाना वसूल करती है। यह बड़ा अहम मसला है, इस पर आध घंटा किस्क ान होनी चाहिये। (व्यवधान)

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाशण में इरीगे ान के बारे में बहंत कुछ कहा गया है। उस पर डिस्क ान करते वक्त आधे घंटे

का टाईम इसके लिये निि चत कर दें, और इस प्वायंट पर डिस्क ान कर लें। अगर इस समय डिस्क ान के लिये आप समय देंगे तो मन्त्री महोदय पूरा जवाब नहीं पायेंगे। राज्यपाल महोदय के भाशण में सारी बात आई हुई हैं, उसमें डिस्क ान हो जाएगी।

श्री अध्यक्षः जैसा मैंने कहा है, गवर्नर एड्रैस पर डिस्क ान के बाद, अगर जरूरत महसूस हुई तो आध घंटे के लियेे बहस की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः अगर गवर्नर एड्रैस पर डिस्क ज्ञन करने के बाद जरूरत महसूस हुई तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिस्क ान करवा लें।

T.A. Drawn by Each Minister

***878. Shri Shamser Singh, Swami Aditayavesh:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) the total expenditure incurred on the Chief Minister and on each of other Ministers in respect ot T.A./D.A., telephone and petrol, separately during the current financial year to date and during the period from 4th July, 1977 to 31st December, 1978, separetely;

(b) the details of the days on which each Minister remained on tour during the period form 4th July, 1977 to 31st December, 1978; and

(c) the month wise number of days on which the Chief Minister and Industries Minister remained on official

tour at Delhi during the current financial year together with the purpose of their visits ?

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): विवरण, जिसमें यह सूचना दी गईं है, सदन के पटल पर रखा जाता है। (अनुलग्नक 'ए' 'बी' तथा 'सी')

ANNEXURE –A

Statement showing the total expenditure incurred on the Chief Minister and on each of other Minister in respect of T.A./D.A. Telephone and Petrol.

Sr. No.	Name and Designation	T.A./D.A.		Telephone Charges		Petrol Expenditure	
		4-7-77 to 21-12-78	1-4-78 to 15-2-79	4-7-77 to 21-12-78	1-4-78 to 15-2-79	4-7-77 to 21-12-78	1-4-78 to 15-2-79
1.	Sh. Devi Lal, C.M.	18194.00	11284.00	81113.45	393336.45	26644.47	11969.84
2.	Sh. Mangal Sein, I.M.	20988.25	15552.25	122012.95	73380.00	70336.65	49.79.04
3.	Sh. Ran Singh, A.M.	4284.00	4794.00	1294.10	15590.10	14913.01	16987.64
4.	Sh. Mool Chand Jain, F.M.						
5.	Sh. Verender	12806.50	8471.50	49647.15	35196.85	46580.46	30044.26

	Singh, I.P.M.						
6.	Sh. Bhajan Lal, C.D.M.	2699.00	4689.00	12010.75	13361.75	17665.06	22657.43
7.	Sh. Prit Singh, R.M.	10251.00	6069.00	51532.90	32720.05	53467.23	36817.49
8.	Sh. Bir Singh, D.M.	4947.0 0	6273.00	9721.95	10059.45	25770.00	30463.02
9.	Sh. Lachhman Singh, P.W.M.	4692.00	5304.00	10467.80	11345.30	1528.25	17775.51
10.	Smt. Dr. Kamla Verma, Health Minister	12589.75	6470.75	42906.75	25993.55	40385.49	24307.27
11.	Sh. Ram Lal L.G.M.	8508.25	9987.25	16799.55	21632.95	39917.81	29407.94
12.	Sh., Hira	5284.00	5845.00	14933.10	17669.50	15683.59	19467.13

	Nand, E.M.						
13.	Sh. Mehar Singh, J.C.M.	3417.00	4641.00	7480.35	9222.05	18116.53	21997.05
14.	Sh. Sher Singh, E.T.M.	3060.00	3672.00	8723.35	9756.85	16361.20	20249.34
15.	Sh. Gajraj Bahadur Nagar, F.S.M.	4712.00	6758.00	5812.95	9981.15	12384.66	17350.79
16.	Sh. Om Parkash, Ex. Minister			300.50		676.31	
17.	Sh. Baldev Tayal, Ex-Minister			1831.00	1831.00	5362.94	5362.94
18.	Col. Rao Ram Singh, Ex-Minister	8485.00	1479.00	22935.50	3675.30	31908.18	6079.51

19.	Sh. Tara Singh, Ex Minister	7366.00	1224.00	17997.75	3536.95	23818.48	3458.64
20.	Sh. Satbir Singh Malik, Ex Minister	6222.00	1632.00	24628.80	5804.00	20129.18	2808.14
21.	Smt. Sushma Swaraj, Ex Minister	5881.00	625.00	33488.80	8434.10	20083.50	3710.60

ANNEXURE –'B'

Statement showing the details of the days on each Minister remaind on tour during the period from 4-7-77 to 31-12-78.

Sr. No.	Name and Designation	Tour Days for which T.A. claimed by the Minister	Tour Days for whicdh T.A. not claimed by the Minister	Total Tour days
1.	Sh. Devi Lal, C.M.	266	5	271
2.	Sh. Mangal Sein, I.M.	328	26	354
3.	Sh. Ran Singh, A.M.	98	10	108
4.	Sh. Mool Chand Jain, F.M.			
5.	Sh. Verender Singh, I.P.M.	239	35	274
6.	Sh. Bhajan Lal, C.D.M.	72	24	96
7.	Sh. Prit Singh, R.M.	212	54	266
8.	Sh. Bir Singh,	111	21	132

	D.M.			
9.	Sh. Lachhman Singh, P.W.M.	112	7	119
10.	Smt. Dr. Kamla Verma, Health Minister	268	22	290
11.	Sh. Ram Lal L.G.M.	133	7	140
12.	Sh., Hira Nand, E.M.	84	15	99
13.	Sh. Mehar Singh, J.C.M.	98	1	99
14.	Sh. Sher Singh, E.T.M.	69	1	70
15.	Sh. Gajraj Bahadur Nagar, F.S.M.	94	1	95
16.	Sh. Om Parkash, Ex. Minister			
17.	Sh. Baldev Tayal, Ex-Minister	20	9	29
18.	Col. Rao Ram Singh, Ex-Minister	121	24	145

19.	Sh. Tara Singh, Ex Minister	133	16	149
20.	Sh. Satbir Singh Malik, Ex Minister	126	11	137
21.	Smt. Sushma Swaraj, Ex Minister	108	53	161

Note:- The above days do not include those journey days on which the Minister either departed from Chandigarh after 4.00 P.M. or arrived in Chandigarh before 11.00 A.M.

ANNEXURE –'C'

Statement showing the month wise number of days on which the chief Minister and Industries Minister remaind on official tours at Delhi during the period from 1-4-78 to 31-1-79.

(1)Chief Minister			Purpose of Journey
	Month	No. of Days	
	April, 78	12 days	
	May, 78	6 days	
	June, 78	5 days	
	July, 78	13 days	

	August, 78	8 days	In connection with the affiars of the State.
	Sept. , 78	8 days	
	Oct., 78	2 days	
	Nov., 78	4 days	
	Dec., 78	7 days	
	Jan., 79	11 days	
(2)Industris Minister			
	Month	No. of Days	
	April, 78	12 days	
	May, 78	7 days	
	June, 78	8 days	
	July, 78	9 days	
	August, 78	5 days	
	Sept. , 78	6 days	In connection with the affiars of the State.

	Oct., 78	6 days	
	Nov., 78	4 days	
	Dec., 78	7 days	
	Jan., 79	6 days	

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने टी0ए0 और डी0ए0 आदि पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है। क्या सरकार के विचाराधनी यह बात है कि इस तरह के खर्चे पर सीलिंग लगाई जाये ?

श्री मूल चन्द जैनः ऐसा कोई विचार नहीं है। रूल्ज जो बने हुए हुं, उनके मुताबिक एक मिनिस्टर महीने में 12 दिन से ज्यादा डी0ए0 नहीं लेग सकता।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है, आपने तो डभ्0ए0 का जवाब दिया है। डा0 मंगल सैन का 1 लाख 20 हजार का बिल टैलीफोन का है और 70 हजार पैट्रोल का है जो इन्होंने 16 महीनों में खर्च किया है। इतना खर्च नहीं होना चाहिये, क्या सरकार इस खर्च पर सीलिंग लगाने के लिये विचार करेगी ?

श्री मूल चन्द जैनः ऐसा कोई विचार नहीं है।

स्वामी अग्निवे I: स्पीकर साहब, मन्त्रियों का टी0ए0का कुल खर्चा 2 लाख 30 लाख हजार का है और इसमें से 36 हजार रुपया अकेले डा0 मंगल सैन का है। इसी प्रकार डा0 मंगल सैन का पैट्रोल का खर्चा 1 लाख 19 हजार है, टैलीफोन पर भी सबसे अधिक खर्चा इन्हीं का है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इतना ज्यादा खर्चा होने का क्या कारण है ? इतना तो मुख्य मंत्री का होना चाहिये, लेकिन उनका इनसे कम है, इसका कारण कया है ?

श्री अध्यक्ष: इनके महकमें ज्यादा हैं महकमे ज्यादा होने की वजह से उतना ही ज्यादा काम है। (व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे I: स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी का सबसे कम खर्चा आ रहा है, इसका क्या कारण है कि इनका सबसे ज्यादा है ? (व्यवधान)

श्रीमती भाांति देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि हमारे घोशणा पत्र में यह दिया है कि हम जनता की भलाई के काम करेंगे। लेकिन हम रोजना यह देख रहे हैं कि कारैं चण्डीगढ़ और हरियाणा के बीच में भागती हुई दिखाई देती हैं। आप जानते हैं कि पैट्रोल का आज क्या भाव है ? टैलीफोनी का बिल भी आपने देख लिया है। अगर हमारे मन्त्रियों का यही रवैया रहा तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा का भविश्य क्या होगा ? (व्यवधान)

कामरेड भांकर लालः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री के सी0ए0, टी0ए0, डी0ए0 वगैरा सब चीजों का खर्चा बताया जाए। (व्यवधान) हवाई जहाज का खर्चा भी बताया जाए ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इसका नोटिस दे दिया जाए, जवाब दे दिया जाएगा।

चौधरी सन्त कंवरः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय खर्च कम करने के बारे में तो कह रहे हैं लेकिन अखबरों के जरिए जनता को यह पता लगा है कि माननीय वित्त मंत्री खुद लम्बी गाड़ी, जिसमें ज्यादा पैट्रोल खर्च होता है, लेने के चक्कर में थे। क्या ये स्वयं जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगें ?

श्री अध्यक्षः इस स्पलीमैंटरी का मेने क्वै चन से कोई सम्बंध नहीं है।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि 12 दिन के बाद मिनिस्टर साहेबान डी0ए0 नहीं लेंगें। क्या वे बतायेंगे अिक इन 12 दिन के बाद अपनी ही कांस्टिचुएंसी को कवर करने के लिये क्या मिनिस्टर साहेबान सरकारी गाड़ी का प्रयोग करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्षः 12 दिन के अन्दर वे अपनी कांस्टियुएंसी में भी जा सकते हैं और हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी जा सकते हैं।

श्रीमती भाांति देवी: 12 दिन के बाद डी0ए0 न लेने का जहां तक सम्बंध है, इसके लिये तो हम सरकार को बधाई देते हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि पैट्रोल और टैलीफोन के खर्च पर भी अंकु ा लगाया जाये।

श्री अध्यक्ष: यह आपका सुझाव है, सवाल नहीं है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यह 12 दिन की लिमिट लगाई गई हे, उसी प्रकार से क्या टैलीफोन और पैट्रोल के इस्तेमाल पर भी कोई लिमिट लगाई जाएगी ?

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का वे जवाब दे चुके हैं।

Plying of buses from Chandigrah to Sirsa *via* Sunam

***886. Chaudhri Jagdish Kumar BeniwalB:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to ply the buses of the Haryana Roadways from Chandigarh to Sirsa via Patiala, Sunam and Mansa, being the shortest route ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह औजला): 13 जनवरी 1979 से सिरसा और चण्डीगढ़ के मध्य वाया मानसा सुनाम, पटियाला, हरियाणा राज्य परिवहन की एक बस सेवा वापसी चक्कर हित चला दी गई है।

चौधरी जगदी ा कुमार बैनिवालः मैं इसके लिये आप का धन्यवाद करता हूं।

तारांकित प्र न संख्या 937

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र भार्मा, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Haryana Raodways Kaithal Depot

***939. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Chief Minister be pleased to state the monthwise loss suffered by or profit accruedc to the depot of Haryana Roadways, Kaithal with effect from 1st April, 1977 to 31st January, 1979 separately ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री सुरेन्द्र सिंह औजला): कथन सदन के सम्मुख प्रस्तुत है।

विवरणी

हरियाणा राज्य परिवहन कैथल डिपो में प्रत्येक मास में हुए लाभ तथा हानि का ब्यौरा

मास	लाभ/हानि 1977–78	(लाख रुपयो में) 1978–79

अप्रैल	(–) 0.35	(–) 2.44
मई	(+) 2.47	(–) 1.27
जून	(+) 5.63	(+) 4.11
जुलाई	(+) 2.06	(–) 1.81
अगस्त	(–) 0.00	(–) 2.45
सितम्बर	(–) 1.05	(–) 4.95
अक्तूबर	(–) 0.42	(+) 0.02
नवम्बर	(–) 0.48	(+) 0.02
दिसम्बर	(+) 0.48	(–) 1.24
जनवरी	(–) 1.53	(–) 1.26
कुल	(+) 1.53	(–) 13.17

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: अध्यक्ष महोदय, कैथल डिपो हरियाणा का एक बहुत कड़ा डिपो है लेकिन इन्होंने दस महीनो का जो हिसाब किताब बताया है उसके मुताबिक 8 महीने में तो घाटा हुआ है, एक महीने में बराबर है और एक महीने में मुनाफा है। क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साइब इस बात की

इन्कवायरी करवायेंगे कि ऐसा क्यों ह ै? इनको वैसे पता है कि कुछ दिन पहली उस जी0एम0 को, सी0एम0 साहब ने मुअत्तिल किया है, कई आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और उसका साला भी गिरफ्तार हुआ है।

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, जहां तक घाटे का ताल्लुक है, उसके कई कारण हैं। सबसे पहली वजन फ्लड की है। दूसरा कारण यह है कि यह टाटा बैस्ड डिपो है, इसमें टाटा गाड़िया हैं। टाटा वकिल्ज के स्पेयर पार्टस की कीमत ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से टाटा बैस्ड अम्बाला, चण्डीगढ़, जींद, करनाल और कैथल के डिपुओं में खर्च ज्यादा आया है। इसके अलावा इस डिपों के अंदर छोटे छोटे रूटस हैं और गाड़ियां मोस्टली गांवों के अंदर चलती हैं। बाकी ओवरआल पोजी ान अगर आप देखें तो इसके अंदर इम्प्रूवमैंट है। इसके अलावा स्पीकर साहब, वैसे तो यह बात इस सवाल से संबंधित नहीं है फिर भी मैं पोहलू साहब की सूचना के लिए बता देना चाहता हूं कि जनरल मैनेजर के बारे में पोहलू साहब जो कह रहे थे, उसक ेअगेन्स्ट इंक्वायरी चल रही है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि कौन सी गड़ी सस्ती आती है ? साथ ही ये यह भी बताएं कि

अगर टाटा गाड़ी महंगी हैं तो इन्होनें इन गाड़ियों को क्यों खरीदा ? इसके अलावा मैं एक बात और जानना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्षः आप एक एक सवाल पूछें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः वह इसी का भाग है। तफती ा से कई हजार के पुर्जे बरामद हुए हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये इसकी थारो इंक्वायरी करवाएंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः स्पीकर साहब, जहां तक सस्ती गाड़ी का सवाल हे, यह तो टाटा की गाड़ी सस्ती पड़ती हैं लेकिन उसके स्पेयर पार्टस महंगे हो गए हैं। जहां तक डीजल का ताल्लुक है, लै लैंड गाड़ी ज्यादा कंज्यूम करती है और टाटा की गाड़ी कम करती है। टाटा वाले चूंकि हमारी टोटल रिक्वायरमैंट मीट नहीं कर सकते इसलिए हमने कुछ जगह लै–लैंड की गाड़िया भी रखी हैं। हमारे पास इस वक्त चालीस परसैंट टाटा गाड़ियां और 60 परसैंट ले–लैंड गाड़िया हैं। यह हमने इस वजह से भी किया है कि हम एक ही कम्पनी पर निर्भर नहीं होना चाहते ताकि किसी समय वह हमें धोखा न दें। जनरल मैनेजर के बारे में पोहलू साहब ने जो सवाल उठाया है, उसकी इंक्वायरी चल रही है और उस केस में दी तीन आदमी गिरफ्तार भी हो चुके हैं।

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब ने अभी बताया कि चूंकि कैथल डिपो में टाटा की गाड़ियां हैं इसलिए घाटा है। क्या वे बताएंगे कि यह घाटा सिर्फ

कैथल में ही है या दूसरी जगह पर भी है जहां टाटा की गाड़िया हैं ? अगर दूसरे डिपोज में भी है तो उनकी क्या हालत है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजलाः जींद की हालत कैथल से भी ज्यादा खराब है। जिन डिपोज में ज्यादा फ्लड आया है वहां पर ज्यादा घाटा है। स्पीकर साहब, मैं हाउस का ध्यान इस डिपार्टमैंट के टोटल रिसोर्सिज की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले साल हमारे टोटल रिसोर्सिज 147.22 लाख रुपये के थे लेकिन अब 163. 51 लाख रुपये के हैं। इसके अन्दर बढ़ौतरी है हालांकि पिछले दो साल से हमने कोई किराया नहीं बढ़ाया है (विघ्न)

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए

ताराँकित प्र नों के लिखित उत्तर

Stipend to evening class students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

***867. Chaudhri Peer Chand:** Will the Minister for Education be please to state-

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to give stipend to the students belonging to Scheduled Cast5es and Scheduled Tribes who have joined eveing classes; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(क) नहीं।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Embezzlement in Haryna Matches Ltd.

***870. Shri Sumer Chand Bhatt:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether any case of embezzlement of funds to the tune of Rs. 0.23 lac has been registrered by the Haryana Matches Ltd., againstg its former Manager, Shri O.S. Kaushik; and

(b) if reply to part(a) above be in the affirmative whether the police investigations in the aforesaid case have since been completed and, if not, the time by which these are likely to be completed ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन):

(क) हां जी।

(ख) नहीं मामले में पुलिस की छानबीन अभी जारी है और भीघ्र ही पूरी होने की सम्भावना है।

Construction of Roads

***873. Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Public Works be pleased to state the time by which the following roads already sanctioned are likely to be constructed-

(i) Kabulpur to Beri;

(ii) Kasrethi to Pakasma;

(iii) Nanrnand to Kalawar; and,

(iv) Morekheri to Humayunpur ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री लछमन सिंह):

(1)(2) तथा (3) यह सड़कें निर्माण के प्रोग्राम में भाामिल हैं। कोई निि चत समय नहीं दिया जा सकता क्योंक निर्माण की प्रगति धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

(4) मामला विधाराधीन है।

Revision of Pay Scale of Class IV Employees

***884. Shri Mange Ram Gupta:**Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the pay scale of Class IV employees has recently been revised form Rs. 70-2-80/3-95 to 80-3-104/4-120;

(b) whether it is alos a fact that the above said revision of scale is applicable only to the class IV employees working in the Haryana Civil Secretariat; and

(c) if reply to part (b) above be in the affirmative, the reasons for having discrimination with other departments ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल):

(ए) जी हां। हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्य कर रहे श्रेणी–4 के कर्मचारियों नामतः सेवादार, स्वीपर्ज, फ्रा ा और हैड चौकीदारों के ग्रेड 70–2–80/3–95 से 80–3–104/4–120 कर दिए गए हैं।

(बी) जी हां।

(सी) भिन्न भिन्न विभागों के कर्मचारियों के वेतनमान भिन्न हो सकते हैं। उक्त निर्णय सिविल सचिवालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया था। अन्य विभागों के चपड़ासियों से अब प्राप्त हुए प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग विचार करेगा।

Empezzlement in Panchayats

***897. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the Gram Panchayat, Neemka, Tehsil Ballabgarh, District Gurgaon has embezzed the Panchayat funds during the construction of buildings for Primary School and Veterinary Hospital and in road construction of village Neemka; and

(b) is so, the action, if any, taken by the Government agaisnt the Panch or Sarpanch found guily for committing the offence ?

विकास मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(क) हां।

(ख) श्री बदले राम सरपंच, सरपंच के पद से हटाया जा चुका है तथा उसे 5 वर्श के लिीये पुनः चुनाव के लिये अयोग्य घोशित किया गया है। सरपंच/पंचों द्वारा पंचायत को पहुंचाई गई हानि की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है।

Cases registered against various offences

***879. Shri Shamsher Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total number of cases registered against offences of murders, attempt to murder, riotings, dacoities, robberies, therfts, kidnapping, rape, arson excise, opium and

under Arms Act during the year 1978-79b to date together with the corresponding figures of such type of cases registered during the year 1976-77; and

(b) the total number of persona challaned for security proceedings during the current financial year ?

Irrigation and Power Minister(Shri Verender Singh):

(a)	1-4-78 to 31-1-79	1-4-76 to 31-1-77
Murders	247	147
Attempt to murder	147	44
Riotings	162	35
Dacoities	19	5
Robberies	54	15
Thefts	3540	1914
Kidnappoing	175	90
Rape	48	21
Arson	64	29
Excise Act	7459	11565
Opium Act	1696	3668

Arms Act	765	1931
(b) 26110 Persons		

Shifting of Corporation to Sirsa

***887. Chaudhri Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift office of any Corporation of the Government of Haryana to Sirsa during the current financial year or during the next financial year ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल): जी नहीं।

Appointment of Standing Counsel

***938. Shri Devender Sharma:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state whether any instructions were issued to the Corporate Bodies/Local Bodies to appoint standing counsel and engage counsel for conduction the cases in the High Court through the Advocate General, Haryana, if so, a copy fo the same be laid on theTable of the House ?

Excise and Taxation Minister (Chaudhri Sher Singh): A copy of the Instructions issued on 11-8-77 to the Corporations etc. is placed on the Table ot the House. As regards Local Bodies no such instructions have been issued separately.

No. 5517-4JJ-77/22123

From

The Secretary to Government, Haryana,

Administration of Justice Department.

To

1	The Managing Director, The Haryana Dairy Development Corporation Ltd., SCO No's 6 and 7, Sector 17E, Chandigarh.
2	The Managing Director,

	Haryana Harijan Kalyan Nigam Ltd., Chandigarh.
3	The Managing Director, Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. SCO 4-5, Sector 17A, Chandigarh-17
4	The Managing Director, Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) Corporation Ltd. SCO 66-67, Sector 17, Chandigarh.
5	The Chairman, Rural Development Board Haryana Kothi No. 1283, Sector 8-C, Chandigarh.
6	The Manager, The Haryana State Co-op. Bank Ltd., Sector -17B, Chandigarh.
7	The Chairman, The Haryana Khadi and Village Industries Board, Kothi No. 53, Sector 2B, Chandigarh.

8	The Managing Director, Haryana Agro-Industries Corporation Ltd., 8, Sector 9A, Chandigarh.
9	The Managing Director, The Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Ltd., Chandigarh.
10	The Managing Director, The Haryana Land Reclamation and Development Corporation, SCO 32-34, Sector 17-C, Chandigarh.
11	The Chairman, Housing Board, Haryana Kothi No. 64, Sector-8A, Chandigarh.
12	The Managing Director, The Haryana State Small Industries and Export Corporation Ltd., SCO 104-105, Sector -17, Chandigarh.
13	The Chairman, Kurukshetra Development Board, Kurukshetra
14	The Managing Director,

	Haryana Financial Corporation, Sector-17A (Opposite L.I.C. Buildings) Chandigarh.
15	The Managing Director, Haryana Tanneries Ltd., SCO 4 and 5, Sector -17A, Chandigarh.
16	The Chairman, Haryana Agricultural Marketing Board, Chandigarh.
17	The Chief Executive Officer, Ther Haryana State Federation of Consumer's Co-operative Wholesale Stores Ltd., 1015, Sector -22B, Chandigarh.
18	The Manger, The Haryana State Co-operative Land Development Bank Ltd. SCO 106, Sector 22B, Chandigarh.
19	The Managing Director, Haryana Tourism Corporation Ltd., Chandigarh.
20	The Managing Director, Haryana Seeds Development Corporation

	Ltd., SCO 32-34, Sector 17, Chandigarh.
21	The Managing Director, Haryana Warehousing Corporation, SCO 8, Sector 17-E, Chandigarh.
22	The Chairman, Haryana State Social Welfare Board, 2125, Sector -15C, Chandigarh.
23	The Chairman, Board of School Education, Haryana Chandigarh.
24	The Executive Director, Ther Haryana State Co-operative Development Federation Ltd., SCO 1050-51, Sector 22-B, Chandigarh.
25	The Managing Director, The Haryana Breweries Ltd., G.T. Road, Murthal (Sonepat)
26	The Chairman, The Haryana State Electricity Board,

	Chandigarh.
27	The Managing Director, Haryana Minerals Ltd., Narnaul.
28	The Managing Director, Haryana Matches Ltd., Narnaul.
29	The Chairman, Water Polluction Board, Haryana, Chandigarh.
30	The Managing Director, Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Ltd. Chandigarh.
31	The Manager, Sonepat co-operative Sugar Mill Ltd., Sonepat.
32	The Manager, Karnal Co-operative Sugar Mill Ltd. Karnal.
33	The Registrar, Kurukshetra University, Kurukshetra.

34	The Registrar, Haryana Agricultural University, Hissar.
35	The Managing Director, Haryana Electronics Ltd., Faridabad.

Dated, Chandigarh the 11th August, 1977.

Subject: Appointment of Standing Counsels/Legal Advisers in the Autonomous Bodies

Sir,

1. No. 7722-4JJ-75 dated 1-10-75 2. No. 2020-4JJ-77/9733 datdd 22-4-77	I am directed to refer to the subject cited above and to say that in supersession of teh marginally noted communications it has been decided that the following procedure will be followed by the autonomous bodies with regard to appointment of Standing Counsels/Legal Advisers by them:-
3. 4109-4JJ-77/14790 dated 17-6-77.	(i) The Managing Directors or the Chief Executives as the case may be of the atutonomous bodies shall, in consultation witht the

	Advocate General, Haryana, prepare a panle of suitable lawyers to act as their Standing Counsels/Legal Advisers.
	(ii) Legal Advisers/Standing Counsels shall be appointed amongst the panel and case entrusted to them ini consultation with the Advocate General, Haryana.
	(iii) All existing Legal Advisers/Standing Counsels other than those who have been appointed in consultation with the Advocate General, Haryana or are whole time Government employees shall cease functioning forthwith. However, cases, already entrusted to them and pending in Courts, whose fee has been paid, shall continue to be handled by them.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary

for Secretary to Governmnet, Haryana,

Administration of Justice, Department

No. 5517-4JJ-77/22124 dated, Chandigarh, the 11th August, 1977.

A copy, with 5 spare copies is forwarded to the Advocate General, Haryana, Chandigarh, for inforamation.

Sd/-

Deputy Secretary

for Secretary to Governmnet, Haryana,

Administration of Justice, Department

A Copy is forwarded to all the Administrative Secretaries to Government, Haryana for inforamation.

Sd/-

Deputy Secretary

for Secretary to Governmnet, Haryana,

Administration of Justice, Department

To

All the Administrative Secretaries to Government,

Haryana

U.O.No. 5517-4JJ-77, dated, Chandigarh, the 11th August, 1977.

Marketing Committee Kaithal

***940. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Agricultur be pleased to state-

(a) the total amount of expenditure incurred by the Marketing Committe of Kaithal during the last two years separately; and

(b) the total amount of income accru9ed to the Marketing Committee of Kaithal during the last two years ending 31-1-1979, separately ?

कृशि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह):

	1977—78	1978—79 (31—1—79 तक)
(क) खर्च	4656640.31	3788661.39

(ख) आय	5989404.74	7115192.41

Blue Print of Jalwahara Head

***947. Sardar Tara Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the date on which the blue print of the JALWAHARA head work was finally printed; and

(b) the time by which the head work mentioned in part(a) above is likely to be completed ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह): जलवाड़ा नाम का हैडवर्कस कोई नहीं है परन्तु एक जाबेहड़ा है।

(क) 21—10—1953

(ब) पहले ही पूर्ण है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Patch work on 'Kachha' Canals

228. Swami Adityavesh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total number of 'Kachha' Canals in the State on which patch work has been done during the period from 4th July, 1978 to 31st October, 1978;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Governmnet for completing the patch work of distributaries of Gurgaon Canal; and

(c) if not, the steps taken or proposed to be taken by the Government for bringing the water upto the tail and for increasing the flow of water therein ?

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh):

(a) Lining work on 18 Kachha distributaries and Minors was taken up during the period from 4th July, 1978 to 31st October, 1978 (List attached)

(b) No.

(c) At present Gurgoan canal is fed from Agra Canal and only small quantity of wate4 is available for Gurgoan Canal as Agra Canal is in U.P. and we have no control over the same. Agreement has been arrived at between U.P. and Harayana on remodelling of Okhla Weir and work has been taken up by U.P. After the Okhla Weir is remodelled more water canbe expected in Gurgoan Canal.

List

List of Channels lined from 1-7-78 to 31-10-78

	Name of Minor	Length
1	Jind Disty. No. 7	1750 ft.
2	Mali Seman Link Channel	150 ft.
3	Adampur Disty.	2000 ft.
4	Chiberwal Minor	2090 ft.
5	Sarangpur Minor	3000 ft.
6	Shekhupura Disty.	14000 ft
7	Sultanpur Minor	4000 ft
8	Kharkheri Disty.	8000 ft
9	Burak Minor	6000 ft
10	Daha Sub Minor	10000 ft
11	Gohana Disty.	21875 ft
12	Naraina Disty.	10000 ft
13	Guhna Minor	2000 ft

14	Rithal Minor	14000 ft
15	Gangesar Minor	3000 ft
16	Rutana Disty.	4000 ft
17	Nirana Minor	4000 ft
18	Kharaitinal Minor	2000 ft

Grants for Adult Education

229. Swami Adityavesh: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the total number and names of the Social Service Institutions in the State to whom the grants have been given for adult Eduation togetherwith the amount granted in each case for the year 1978-79; and

(b) the criteria adopted for including the Social Services Institutions in Adult Education Programme ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(क) 98200 रुपये प्रति संस्था की दर से तीन स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान दिया गया है जिनका नाम इस प्रकार है

1. गान्धी भाान्ति प्रतिश्ठान केन्द्र, अम्बाला छावनी

2. सो ाल वर्क एण्ड रिसर्च सैंटर, खोडी महेन्द्रगढ़ तथा

3. जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी।

(ख) राज्य के प्रौढ़ कार्यक्रम में सामाजिक सेवा संस्थाओं को सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियत किया गया सिद्धान्त संलग्न9 अनुबन्ध 'ए' में द ार्शाया गया है।

अनुबन्ध 'ए'

योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक संस्था :–

1	का एक विधिवत विधान अथवा संघ नियम होना चाहिए;
2	की विधिवत गठित प्रबंध समिति होनी चाहिए तथा उस की भाक्तियों और कर्त्तव्यों की स्पश्ट व्याख्या इसके विधान में होनी चाहिये;
3	ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर जानकार व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त कर सकें;

4	किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संगठन के लाभ की दृश्टि से न चलाई जा रही हो;
5	स्त्री पुरूश, धर्म, जात–पात आदि के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति कोई भेदभाव न करती हो;
6	किसी राजनीतिक दल के हित में प्रत्यक्षतः काम न करती हो;
7	साम्प्रदायित असामंजस्य किसी प्रकार से भी न भड़काती हो;
8	धर्म प्रचार न करती हो; और
9	हिंसा न भड़काती हो।

Hospitals in Big Villages in the State

230. Swami Adityavesh: Will the Minister for Healt be please to state-

(a) the criteria fixed for opeing hospitals, with modern facilities, in the big villages in the State; and

(b) the number of such villages where the hospitals have been opened during the period from 4th July, 1977 to 31st October, 1978 ?

Health Minister (Smt. Dr. Kamla Verma):

(a) There is no fixed criteria for opening hospitals with modern facilities in big villages in the State. The hospitals are opened considering the needs of the villages vis-a-vis the availability of funds.

(b) Two

Openiing of Girls High Schools in the Villages

231. Swami Adityavesh: Will the Minister for the Education be pleased to state-

(a) the criteria fixed for opening Girls High School,s with Modern facilities in the big villages in the State; and

(b) the number of such villages where the School have been opened during the period from 4th July, 1977 to 31st October, 1978 ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(ए) सीधे हाई स्कूल खोले नहीं जाते। यह पूर्व माध्यमिक स्कूलों का स्तर भूमि, भवन तथा छात्र संख्या के आधार पर बढ़ाया जाता है।

(बी) भून्य।

Shortages/Thefts/Mis-appropriation in Government Material

243. Shri Devender Sharma: Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) the number of cased in which shortages/thefts/mis appropriations of Government materials were noticed in the P.W.D. (B&R) during the years 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 together with the value thereof;

(b) the number of cases referred to in part (a) above where material has been recoveed together with its value;

(c) the number of said cased pending with the Department/Police/Court and since when; and

(d) the number of cases referred to part (a) above where action has been pending for the last three to five years ?

Interim Reply

"Subject: Unstarred Assembly Question No. 243 asked by Sh. Devender Sharma, M.L.A., regarding shortages/thefts/mis approprtiation in Government material.

The answer to Haryana Vidhan Sabha Unstarred Assembly Question No. 243 to be asked by Shri Devender Sharma M.L.A. at a meeting of the Haryana Vidhan Sabha to be helf on 1st March, 1979 is not ready. This information is

being collected and is likely to take a perioed of about 10 days.

I am to request that theis question may please be included in the list of questions for any day after 15th Mach, 1979.

Sd/-

Public Works Minister,
Haryana

To

The Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh

U.O. No. 29/11/79/P.W.IV (1) dated 27-2-1979"

Yoga Education

244. Shri Mool Chand Mangla: Will the Minister for Education be please to state-

(a) the steps taken or porposed to be taken for imparting Yoga Education in the State;

(b) whether there is any proposal under consideration of teh Govenment to make Yoga Education compulsory in Schools and College; and

(c) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(ए) योगा ि ाक्षा पहले ही भाारीरिक ि ाक्षा के पाठयक्रम में सम्मिलित है।

(ख) नहीं, भिन्न विशय के तौर पर नहीं।

(ग) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता।

Qualification for the Post of Coach in Yoga

245. Shri Mool Chand Mangla: Will the Minister for Education be please to state-

(a) whether it is fact that the grade of the post of Coach in Yoga in the Sports Department is Rs. 300-600;

(b) whether it is also a fact that the grade of the post of Instructors in Yoga is Rs. 14-400, and whether the qualification for Coach in Yoga and Instrctors in Yoga is the same; and

(c) if so, the reason therof ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(ए) इस विभाग में योगा प्रि ाक्ष की कोई असामी नहीं है।

(ख) योगा ि ाक्ष के पद का वेतनमान 160—400 है। फिर भी एक योगा ि ाक्षक को उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं को सम्मुख रखते हुए उसको 300—600 का वेतनमान दिया गया, क्योंकि उसने 8—2—77 को जी0एस0 कालेज आफ योगा, लोनावला से वि ोश प्रि ाक्षण लिया था। योगा प्रि ाक्षक और योगा ि ाक्षक की अर्हताओं में भिन्नता है।

(ग) योगा प्रि ाक्षक का विभाग में कोई पद नहीं है, इसलिए तुलना का प्र न ही नहीं है।

Cases of Dacoity

246. Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of cases of dacoity registeed in Jagadhri Sub-Divion since the formationof janata Government in the Stage;

(b) the total number of cases out of those referred to in part (a) above traced out and persons prosecuted; and

(c) the number of cases which are pending in the Courts ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह):

(अ) दो।

(ब) एक मुकद्दमा खोज हुआ और चार व्यक्ति चालान किए गए।

(स) एक।

Theft Cases

247. Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the tehsil-wise number of theft cases registered in Amabal district after formation of Janata Government in the State;

(b) the total number of cases out of those referred to in part (a) above which have been traced out and the perosn peosecuted so far as a result therof;

(c) the number of cases which are still pending in Courts; and

(d) the number of cases which have been filed as untraced ?

Irrigation and Powers Minister (Shri Verender Singh):

(a)	Ambala	533	
	Jagadhri	278	
	Naraingarh	56	
	Kalka	83	
(b)			Persons prosecuted
	Ambala	165	162
	Jagadhri	130	48
	Naraingarh	22	44
	Kalka	28	53
(c)			
	Ambala	90	
	Jagadhri	57	
	Naraingarh	18	
	Kalka	15	
(d)			
	Ambala	195	
	Jagadhri	123	

	Naraingarh	24	
	Kalka	43	

Murder Cases

248. Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the tehsil-wise number of murder cases registered in Amabal district after formation of Janata Government in the State;

(b) the total number of cases out of those referred to in part (a) above which have been traced out and the perosn peosecuted so far:

(c) the number of cases field as untraced; and

(d) the total numher of cases whoch are pending in the Courts at present ?

Irrigation and Powers Minister (Shri Verender Singh):

(a)	Ambala Tehsil	17	
	Jagadhri Tehsil	11	
	Naraingarh Tehsil	6	
	Kalka Tehsil	4	

(b)		No. of cases traced out	Persons prosecuted
	Ambala Tehsil	17	50
	Jagadhri Tehsil	10	22
	Naraingarh Tehsil	5	17
	Kalka Tehsil	4	2
(c)			
	Jagadhri Tehsil	1	
	Naraingarh Tehsil	1	
(d)		9	

15.00 बजे।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके एक बात स्पश्टीकरण चाहता हूं। पिछले दिनों मैंने एक सवाल भी किया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, आप बैठिए। मुझे रावी व्यास के पानी को मनासिब ढंग से इस्तेमाल करने और एस0वाईएल0 नहर

को फौरन बनाने के बारे में एक काल अटैन् ान मो ान मिला है। (विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, एक बड़ा स्पैसिफिक पब्लिक इम्पोटैंस का मामला है। आज हरियाणा में आलू की कीमतें गिर रही हैं ... (विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप इस बारे में मुझे नोटिस दे दें। मैं जरूर कन्सिडर करूंगा। पोहलू साहब अब आप बैठ जाइये। (विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, आलू की कीमतें * * * * * * * * * * * *

Mr. Speaker: Nothing will be taken down which is spoken without my permission. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mr. Speaker: Mr. Pohloo, if you do not stick to the discipline of the House, I will have to name you.

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के बावजून भी पोहलू साहब बोल रहे हैं आपने पहले ही कह दिया है कि कुछ रिकार्ड न किया जाये, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ इन्होंने रिकार्ड किया है उसको एक्सपंज किया जाये और श्री बूरा साहब को रेजोल्यू ान पढ़ने दिया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मैंने यह पहले ही कर दिया है कि जो मेरी परमि ान के बिना बोलेगा। वह नोट न किया जाये। (विघ्न)

ध्यानाकर्शण सूचना–

रावी ब्यास के पानी को मुनासिब ढंग से इस्तेमाल करने और एस0वाई0एल0 नहर को फौरन बनाने सम्बंधी

श्री अध्यक्षः मुझे रावी ब्यास के पानी को मुनासिब ढंग से इस्तेमाल करने और एस0वाईएल0 नहर को फौरन बनाने के बारे में एक काल अटैं ान मो ान मिला है। चौधरी हरस्वरूप बूरा का नोटिस राव राम नारायण से पहले मिला था, इसलिए मैं चौधरी हरस्वरूप बूरा से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे अपना काल अटैन्ा ान मो ान नोटिस पढ़ें।

चौधरी हरस्वरूप बूराः मैं सदन का ध्यान अत्याव यक लोक महत्त्व के विशय अर्थात हरियाणा का भविश्य रावी–व्यास से बन्ध हुआ हूं। की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पानी राज्य के 80 प्रति ात किसानों को सुनहरा स्वप्न है और यह बहुत पुराना स्वप्न है। इस संबंध में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। यदि एस0वाईएल0 का निर्माण नहीं किया जाता तथा 3.5 एस0ए0एफ0 पानी अर्जित नहीं किया जाता है तो हरियाणा को गम्भीर आर्थिक

हानि उठानी पड़ेगी। जनता सरकार के बनने के प चात हमने इस स्वप्न को नया रंग दिया था, परन्तु आज हमारे सामने वास्तविकता कुछ और है। यह एक केवल राजनीति नारा नहीं है, परन्तु हमें उसे व्यवारिक रूप देना होगा। यह वास्तविकता है कि पिछले दो सालों के दौरान पानी की कमी महसूस नहीं की गई है। यह बात भारी और समय पर हुई वर्शा के कारण हो सकती है या सरकार द्वारा की गई कोि ा ाों के कारण हो सकती है परन्तु आज यह बात कहनी पड़ रही हे –

"स्वप्न देखा था अभी इस एस0वाई0एल0 के निर्माण का,

उठा दिखाई दे रहा है लेकिन जनाजा उस अरमान का।"

उपरोक्त के दृश्टिगत यह बात बिलकुल स्पश्ट है कि एस0वाईएल0 नहर का निर्माण बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है बल्कि यह हरियाणा के किसानों के लिए मौत और जीवन का सवाल है। हरियाणा ने लगभग अपना काम समाप्त कर लिया है, परन्तु दुर्भाग्यव ा बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी यह काम पंजाब में भाुरू नहीं किया गया है। इन दोनों सरकारों के मध्य केन्द्रीय सरकार द्वारा कई बैठकें की गई हैं। पंजाब के मुख्य मन्त्री सरदार प्रका ा सिंह बादल ने एक वचन दिया था, परन्तु निर्णय के ऊपर अमल नहीं किया गया। 1976 में हरियाणा सरकार ने इस प्रयोजन

के लिए एक करोड़ रुपया दिया था, जिसका प्रयोग कर लिया गया है। 1978–79 की पहली तिमाही के लिए उन्होंने तीन करोड़ रुपया और मांगा था। फरवरी 1978 में पांच किलोमीटर लम्बी भूमि अर्जित करने के लिए धारा 4 तथा 17 के अधीन एक अधिसूचना जारी की गई थी। परन्तु धारा 6 के अधीन अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। भारत सरकार ने चोधरी देवी लाल के निवेदन पर कैपेसिटि के बारे में निर्णय किया है। इस सारी बात के बावजूद यह काम पंजाब में एक या दूसरे बहाने से भाुरू नहीं किया गया है जिससे हरियाणा में चिन्ता पैदा हो रही है। प्रधान मंत्री ने भी बहुत सी बैठकें बुलाई हैं उन सब प्रयत्नों के बावजूद मुझे यह खेद से कहना पड़ता है कि पंजाब के क्षेत्र में इस नहर पर काम अभी तक भाुरू नहीं किया है।

मैं इस महान सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमें मिल कर इसका कोई हल ढूंढना चाहिए ताकि इस नहर पर काम तुरन्त भाुरू किया जा सके तथा हरियाणा में बनाए गए नहरी सिस्टम को पानी मिल सके। हरियाणा की सरकार को ऐसे ठोस पग उठाने चाहिए जिससे जनता को यह वि वास हो जाए कि सरकार उनके जायज हकों के प्रति जागरूक है।

हरियाण असीमित अवधि के लिए इन्तजार नहीं कर सकता क्योंकि भारत सरकार का निर्णय अंतिम है तथा समानता पर आधारित है और लगभग यह पुराना हो चुका है।

श्री अध्यक्षः साहेबान, चूंकि आज प्राइवेट मैम्बर का दिन है और श्री भाम ोर सिंह सुरजेवाला का दिया हुआ इसी विश पर रेज्योलू ान बैलेट में आ करके आज की लिस्ट आफ बिजनैस में आ गया है। इसलिए मैं चौधरी हरस्वरूप बूरा और राव राम नारायण जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस पर डिस्क ान इस वक्त न करें। जब उसी विशय पर प्राइवेट मैम्बर को रेजोल्यू ान डिस्कस होगा तो उस वक्त इस पर भी डिस्क ान हो जायेगी।

एक मैम्बरः हो सकता है कि इस रेज्येलू ान की टर्न ही न आये ?

श्री अध्यक्षः अगर हाउस सीटिंग एक्सटैंड करना चाहेगा तो एक्सटैंड कर देंगे। समय अभी काफी हैं

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, कल मैंने चौधरी राम लाल वधवा के खिलाफ एक प्रीविलिज मो ान का नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्षः वह नोटिस आ गया है, एग्जामिन हो रहा है। एग्जामिन होते ही रूलिंग दे दी जायेगीं It is being examined by me.

श्री भाम ोर सिंहः मेरी दरखास्त यह है कि रूल 278 के तहत आप बिना हाउस को रैफर किये, कोई भी मैटर प्रीविलिज कमेटी को एग्जामिने ान के लिए रैफर कर सकते हैं।

Mr. Speaker: Unless I examine the matter, I cannot say what step I will take in the matter. पहले मुझे मैटर को फुली एग्जामिन करने के लिए मौका तो दें। I assure you that I will deal with the matter on its merits.

श्री भाम ोर सिंहः इसका नोटिस मैंने कल साढ़े ग्यारह बजे दिया था .....

Mr. Speaker: I am collecting the necessary material required by me to examine the matter. Please give me time. I will examine it and take a decision on the merits of the case.

श्री भाम ोर सिंहः मैं कब तक इस फैसले को एक्सपैक्ट कर सकता हूं ?

Mr. Speaker: As early as possible.

श्री भाम ोर सिंहः कब तक ?

Mr. Speaker: Tomorrow moring, after the Question Hour.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker: I have to report the time table fixes by the Business Advisory Committe in regard to various business.

समिति की बैठक बुधवार 28 फरवरी 1979 को 3.45 बजे मध्याह्न प चात माननीय अध्यक्ष महोदय, के चैम्बर में हुई।

कुछ चर्चा के प चात समिति ने सिफारि ा की कि 1, 2, 5, 6, 7, 8 तथा 9 मार्च 1979 को सभा द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाये :–

वीरवार, 1 मार्च, 1979 (2.00 बजे मध्याह्न प चात)

1. प्र नोत्तरकाल।

2. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट पे ा करना तथा ग्रहरण करना।

3. गैर सरकारी कार्य।

भाुक्रवार, 2 मार्च 1979 (9.30 बजे प्रातः)

1. प्र नोत्तरकाल।

2. राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा।

भानिवार, 3 मार्च, 1979

खाली दिन।

रविवार, 4 मार्च, 1979

छुट्टी।

सोमवार, 5 मार्च, 1979 (2.00 बजे मध्याह्न प चात)

1. प्र नोत्तरकाल।

2. राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा का पुनरारम्भण।

मंगलवार, 6 मार्च, 1979 (2.00 बजे मध्याह्न प चात)

1. प्र नोत्तरकाल।

2. सदन की मेज पर कागज पत्र रखना पुनः रखना।

3. 1978–79 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) पे ा करना।

4. राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

भाुक्रवार, 7 मार्च, 1979 (2.00 बजे मध्याह्न प चात)

1. प्र नोत्तरकाल।

2. वर्श 1979–80 का बजट पे ा करना।

वीरवार, 8 मार्च, 1979 (2.00 बजे मध्याह्न प चात)

1. प्र नोत्तरकाल।

2. गैर सरकारी कार्य।

भाुक्रवार, 9 मार्च, 1979 (9.30 बजे प्रातः)

1. प्र नोत्तरकाल।

2. वर्श 1978–79 के अनुपूरक अनुमान (तीसरी कि त) पर चर्चा तथा मतदान।

कुछ चर्चा के प चात समिति ने यह और सिफारि ा की कि 10 से 15 मार्च 1979 तक सभा की कोई बैठक नहीं होगी तथा उसके प चात सदन की बैठक भाुक्रवार 16 मार्च 1979 को होगीं

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, 16 तारीख को सदन की बैठक कितने बजे होगी ?

श्री अध्यक्षः 16 तारीख को 2 बजे होगी। रूल्ज के अनुसार तो साढ़े नौ बजे होनी चाहिए क्योंकि फ्राइडे को आम तौर पर हाउस के मैम्बरों को जाना होता है। लेकिन अब क्योंकि सदस्यों ने आना है इसलिये हमने 2 बजे का समय तय किया है। बाकी हाउस की ओपीनियन पर डिपैंड करेगा।

चौधरी भजन लालः ठीक है जी, आप दो बजे का ही टाईम रखें क्योंकि मैम्बरों को बाहर से आना पड़ेगा।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैन्ा ान मो ान दिया था और वह एडमिट हो गया है। मुझे तो आपने पढ़ने के लिए कहा नहीं ?

श्री अध्यक्षः क्या एडमिट हुआ है ?

श्री फतेह चन्द विजः हां जी, मेरे पास लैटर है जो आपके सैक्रेटेरियेट की तरफ से आया हुआ हैं

श्री अध्यक्षः आप मेरे से चैम्बर में आकर डिस्कस कर लें।

वित्त मंत्री (श्री मूल चन्द जैन): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की प्रथम रिपोर्ट में दी गयी सिफारि ाान स्वीकार करता है।

Mr. Speaker: Motion moved –

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

स्वामी अग्निवे I: अध्यक्ष महोदय, मुझे कार्यक्रम के बारे में एक छोटा सा निवेदन करना है। इस कार्यक्रम के अनुसार जैसे कि आपने बताया है 10 से लेकर 15 तारीख तक अधिवे ान स्थगित रहेगा और फिर 16 तारीख को एक दिन की बैठक होगी। 17–18 तारीख को छुट्टी होने के कारण बैठक नहीं होगी। मेरा सुझाव यह है कि बजाय इसके कि 16 तारीख को 2–4 घंटे के लिये हम इनती दूर से आयें, क्यों न 18 तारखी के बाद ही इकट्ठे हो जायें ?

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने जो फैसला कर दिया है, वह हाउस के सामने है, हाउस उसमें कोई तरमीम करना चाहते तो कर सकता है।

स्वामी अग्निवे ाः मेरा सुझाव तो यही है कि 19 तारीख से रिज्यूम कर लिया जाये।

श्री मूल चन्द जैनः यह प्वायंट बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी आया था। वहां पर भी यह स्वीकार इसलिये नहीं किया कि एजेन्डा काफी बकाया है। इसलिये अब भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, मैंने और राव साहब ने पंजाब असैम्बली देखी है और यहां पर भी देखा है। वहां पर यह हुआ करता था कि जिस रोज हम पहली बार मिलते थे या छुट्टियों के बाद जिस समय हम पहली बार मिलते थे, उस रोज तो सिटिंग भााम को 2 बजे हुआ करती थी लेकिन बाकी के दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे होती थी और अब भी हो रही है। इसका कारण यह है कि यहां पर जो प्रैस वाले बैठते हैं, वे अगर भााम 6साढ़े 6 बजे तक बैठे रहेंगे तो वे किस समय जाकर अपनी रिपोर्ट देंगे ? इसका रिजल्ट यह होगा कि यहां की कार्यवाही अगले दिन न आकर उसे अगले दिन आयेगी। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि सोमवावर को तो 2 बजे और बाकी के सारे दिन साढ़े नौ बजे का टाईम निि चत किया जाये।

श्री अध्यक्षः आप अपना यह सुझाव उचित समय पर रखनां अभी तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर गौर हो रहा है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः वह तो ठीक है लेकिन सुबह की सिटिंग का थोड़ा समय होने की वजह से हमें बोलने के लिए कम समय मिलेगा।

श्री अध्यक्षः राव साहिब, आपका क्या विचार है ?

राव बीरेन्द्र सिंहः यह तो सर, हाउस की सैंस की बात है। श्री जगन नाथ जी ने ठीक ही कहा है कि असैम्बली की कार्यवाही लोगों तक पहुंचे, यह बहत जरूरी है। जब हाउस हफ्ते में पहली बार मिले उस दिन 2 बजे मिल ले और उसके बाद 9साढ़े नौ बजहे का टाईम हो जाये। मेरे विचार में यह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्षः इसका मेन डिस एडवान्टेज तो यही रहेगा कि जो हाउस की सिटिंग का टाईम है, वह कम हो जाएगा क्योंकि सुबह अगर चलेगा तो सुबह साढ़े नौ बजे से चलकर एक बजे खत्म हो जायगा।

राव बीरेन्द्र सिंहः एक बजे की बजाये डेढ़ बजे तक रह सकता है।

श्री अध्यक्षः इस बारे में मैं श्री जगन नाथ जी से यही कहना चाहूंगा कि वे अपनेा सुझाव लिख कर भेज दें। मैं दूसरे मैम्बरों से सलाह म ाविरा करके अपना फैसला दे दूंगा।

अब मैं इास की इस बारे में सैंस लेना चाहूंगा कि 16 तारीख को हाउस 2 बजे मीट करना चाहिए या कि साढ़े नौ बजे ?

आवाजेः 2 बजे ठीक है जी।

श्री जगन नाथः मेरा कहना यह है कि जब भी हाउस छुट्टी के बाद पहली बार मीट करता है तो हाउस 2 बजे होना चाहिए। बाकी के दिन साढ़े नौ बजे होना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees witht he recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

गैर–सरकारी संकल्प–

(1) स्वर्गीय चौधरी छोटू राम की जन्म भाताब्दी मनाने के लिए एक समिति गठित करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान पहले दो प्राईवेट मैंबर्ज रैज्योलू ान एक ही चीज से सम्बन्धि हैं जो चौधरी संत कंवर

और राव राम नारायण की ओर से हैं। संत कंवर साहिब का रैज्योलू ान पहले बैल्ट में आया है इसलिये He may kindly move his resolution.

चौधरी सन्त कंवरः स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

कि स्वर्गीय चौधरी छोटू राम की जन्म भाताब्दी को मनाने के लिये जिन्होंने अपना जीवन किसानों के उत्थान तथा उन्नति के लिये समर्पित कर दिया, यह सदन सरकार से सिफारि ा करता है कि वह प्रसिद्ध विद्वानों, समाज सेवकों, साहित्य प्रेमियों तथा संसद सदस्यों की एक समिति गठित करे जो कि वर्श 1981 में आने वाली उसकी जन्म भाताब्दी को राज्य स्तर पर उचित ढंग से मनाकर राश्ट्र के विख्यात सपूत को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिये उपयुक्त पग उठाने के लिये सरकर को सुझाव दे।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

Withe a view to commemorate the birth centenary of Late Chaudhri Chhotu Ram who dedeicated his life for the uplift and betterment of the peasantry, this House recommedns to the State Government to constitute a Committee comprising the renowned academicains, Social Workers, literateures and Parliamentarians for sugesting to the Government to take suitable steps to pay hoage to the

illustrious son of the Nation by celebrating the occassion in the befitting manner which falls in the year, 1981 at at State level.

चौधरी सन्त कंवर (हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय चौधरी सर छोटू राम जी हरियाणा के ही नहीं बल्कि राश्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत थे। उन्होंने जो काम हरियाणा और यूनाइटिड पंजाब के लिये किया, वह काम भुलाया नहीं जा सकता। बड़ी बदकिस्मत हमारी यह रही कि उन्होंने जो सिद्धांत जो नीतियां और जो रास्ते आने वाली पीढ़ियों को बताई थीं, आने वाली हरियाण की पीढ़िया उन रास्तों पर नहीं चल पायी। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने तो उनके बारे में पढ़ा होगा कि वे गरीबों से कितना प्यार करते थे, गरीबों के प्रति उनके दिल में कितनी सहानुभूति थी। वे जब भी गांव के अन्दर जाते थे तो वे एक बात अक्सर कहा करते थे "ए भोले किसान मेरी एक बात ले मान, बोल न, ले सीख और दु मन को ले पहचान"। डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिनको कि आने वाली पीढ़िया भूल नहीं सकती और उन्हीं कामों की वजह से हम इस सदन से सिफारि ा करते हैं कि 1981 में उनकी जो जन्म भाताब्दी आ रही है, उस भाताब्दी को सारे हिन्दुस्तान में धूमधाम से मनाने के लिये एक समिति बनाएं जिसमें पार्लियामैंट के मैंबर, असैम्बलियों मैंबर, ि ाक्षा भाास्त्री, और दूसरे बड़े आदमी हों ताकि चौधरी छोटू राम ने जो अपने जीवन में अच्छे काम किए, गरीबों के लिये जो सुधार के काम किए उनको आने वाली पीढ़ियों के सामने रखा जा सके।

यह काम सरकार द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा ही अच्छी तरह से किया जा सकता है क्योंकि किसी भी प्राईवेट संस्था के पास इतना पैसा नहीं है कि उनकी जन्म भाताब्दी पूरी धूमधाम से मना सके। इसलिये यह सदन सरकार से सिफारि ा करता है कि एक समिति गठित करे। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता होगा कि भाखड़ा जिसकी वजह से आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान खु ाहाल बने हुए हैं। यह सारी स्कीम चौधरी छोटू राम के दिमाग की उपज थी। अगर चौधरी छोटू राम के दिमाग में यह स्कीम न होती तो आज भाखड़ा न होता यह बदकिस्मत की बात है कि आठ तारीख को जब चौधरी छोटू राम मृत्यु भाय्या पर पड़े हुए थे, तो पंजाब असैम्बली का सै ान चल रहा था। इतने बीमार होने के बावजूद भी वे असैम्बली में गए, वहां जाकर भाखड़ा के बारे में रैज्योल्यू ान पास करवाया और नौ तारीख को उनका स्वर्गवास हो गया। इस बात से पता चलता है कि कितने आगे की बात वे सोचा करते थे। डिप्टी स्पीकर साहब, जो उनहोंने पत्र लिखे थे, अगर उनको पढ़ कर देखा जाए तो पता लगेगा कि जो चिट्ठियां उन्होंने चाली पचास साल पहले लिखी थी, वे आज सही साबित हो रही हैं। एक दूसरे महापुरूश थे जिनका मैं नाम नहीं लेता, जब पंजाब असैम्बली में किसान की भलाई के लिए काननू बना तो उस महापुरूश ने उसको काला कानून कहा और अखबार में अपना ब्यान दे दिया। जब चौधरी साहब ने उसको पढ़ा तो उन्होंने अपने मुं ाी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने यह बयान दिया है उस आदमी के दिमाग के अंदर गरीब वर्ग की

भलाई की बात नहीं है और आने वाले दिनों में यह बात बिल्कुल ठीक साबित हुई। मैं उस महापुरूश का नाम नहीं लेता। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी साहब ने एक चिट्ठी महात्मा गांधी को लिखी और दूसरी चिट्ठी मि0 जिन्ना को लिखी थी। महात्मा गांधी को लिखा था कि मि0 जिन्ना कायदे आजम का नाम देकर पाकिस्तान बनाने के लिये पग उठा रहे हैं। चौधरी साहब कहा करते थे कि जब तक मैं जिन्दा हूं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। यह हिन्दुस्तान सब का है और इस दे ा में सब लोग पूरी आजादी के साथ रहने चाहिएं। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर वे जिन्दा रहते तो मुझे पूरा वि वास है कि वे पाकिस्तान नहीं बनने देते। डिप्टी स्पीकर साहब, वे बहुत बहादुर इन्सान थे। उस समय अंग्रेज सरकार ने एक वीट कन्ट्रोल एक्ट पास करने की बात कही थी और तमाम प्रदे ाों के मुख्मंत्रियों का बुलाया गया। पंजाबी तरफ से चौधरी छोटू राम जी को भेजा गया था। चौधरी साहब ने उस मीटिंग में, जिसमें कि तमाम प्रदे ाों के मुख्यमंत्री भाामिल थे, उस कानून को काला कानूनी कहा था और साथ ही यह कहा था कि यह काला कानून खत्म होना चाहिए। चौधरी साहब ने बड़ी बहादुरी से यह बात कही कि हम इस कानून को नहीं मानते। डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय ऐसा कहना कोई मामूली बात नहीं थी क्योंकि अंग्रेज सरकार थी और वायसराय के खिलाफ कोई बात कहना मामूली बात नहीं थी। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो वह बैठक का बायकाट करके उठ कर चले आये। उन्होंने यह कहा था कि आप बे ाक यह काला कानून पास कर लें, लेकिन मैं

पंजाब में जाकर जितनी भी गेहूं की फसल खड़ी है उसको आग लगवा दूंगा। उनके साथ हिन्दुस्तान का किसान था जब वायसराय के दिमाग में यह बात आई कि यह इंसान सारे हिन्दुस्तान की खड़ी फसल को आग लगवा सकता है तो उस समय की सरकार ने वह काला कानून वापिस ले लिया। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता होगा कि उस समय एक मिनिस्टर की तनखाह तीन हजार रुपये होती थी लेकिन जब चौधरी साहब का स्वर्गवास हुआ तो बैंक में उनके नाम पर कोई पैसा नहीं मिला। उन्होंनें तमाम पैसा गरीबों पर खर्च कर दिया था। गरीब घरानों के लड़कों को वे छात्रवृत्तियां देते थे और उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न किया करते थे उन्हीं व्यक्तियों में से एक थे चौधरी चांदराम भी हैं। चौधरी चांद राम कहा करते हैं कि अगर चौधरी छोटूराम मेरी मदद न करते तो मेरी ि ाक्षा पूरी नहीं होती और न ही मैं राजनीति में आ सकता था। पंजाब और हरियाणा में बहुत से लोग हैं जिनकी चौधरी साहब ने हर तरह से मदद की थी और आज वे बड़े बड़े औहदों पर बैठे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी छोटूराम के खानदान के साथ मेरे खानदान का कुछ खास संबंध रहा है क्योंकि 1914–15 में जब चौधरी साहब वकील थे तो मेरा दादा जी भी वकील थे। चौधरी साहब मेरे दादा जी के साथ मेरे गांव में आया करते थें बदकिस्मती यह है कि हम उनको नहीं देखा सके। वह हमारे पेदा होने से पहले ही इस संसार से विदा हो चुके थे। डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने किसान की भलाई के लिये ऐसे काम किए, ऐसे कानून बनाए जो भुलाए नहीं जा सकते। आज

सोद देश में जो मार्किट कमेटियां बनी हुई हैं वह उन्हीं की देन है और ये इसलिये बनाई ताकि मंडी में बैठने वाला व्यापारी किसान का न लूट सके। माननीय चौधरी साहब ने इसके अलावा भी कई एक्ट पास करवाए उनमें से एक मंडी एक्ट है। उस जमाने में जो धनवान महाजन होते थे वे गरीब किसानों को कर्जा दे दिया करते थे और सूद पर सूद लगा कर वह रकम इतनी बढ़ा लेते थे कि बेचारा किसान उस पैसे को दे नहीं सकता था। वह महाजन उस गरीब किसान की जमीन ले लेता था, उसके प ा ले लेता था और उसका घर तक भी नीलाम करा देता था। चौधरी साहब ने इस ज्यादती को देखा और गरीब किसान की भलाई के बारे में कानूनी पास करवाया। उस जमाने में हर गांव में एक दो महानज ऐसे हुआ करते थे जो किसानों को कर्जा दे दिया करते थे और अपनी बही में सूद दर सूद लगा कर थोड़ से पेसे को बड़ी रकम बना लिया करते थे और किसान के लिये वह पैसा देना बड़ी मु ि कल का काम होता था। चौधरी साहब ने तमाम गरीब लोगों का कर्जा माफ करवाया और इसको माफ करवाने के लिये एक कर्जा बिल के नाम से कानून पास करवाया और उस कानून में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी महाजन किसी गरीब किसान के रहने वाले मकान को नीलाम नहीं करवा सकता जिस मकान में किसान प ा बांधता है उसको महाजन नीलाम नहीं करवा सकता जो घर के अंदर अनाज जमा है उसको नीलाम नहीं करवा सकता और न ही किसान की बोने वाली जमीन को नीलाम करवा सकता

है। आज हमारे जो मंत्री महोदय बैठे हैं वे भी चौधरी छोटूराम के सिद्धांतों को अपने दिमाग में रख कर काम करना चाहते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी सर छोटू राम जी के बारे में और ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि अभी हाउस के और बहुत से मैम्बर साहेबान ने बोलना है। केवल एक दो बातें कह कर ही समाप्त करूंगा। चौधरी साहब जब मिनिस्टर थे, उस वक्त वे लाहौर में रहते थे और बड़ा सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका खाना बड़ा सादा था, पहनना सादा था। डिप्टी स्पीकर साहब, भाायद आपने उन्हें नजीदक से देखा होगा। चौधरी साहब, खिचड़ी और दलिया जो कि एक गरीब किसान और मजदूर का भोज है, खाया करते थे। इन्हीं कुछेक बातों के साथ, मैं सरकार से इस सदन के द्वारा सिफारि ा करना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में एक कमेटी बनाये और वह कमेटी पूज्नीय सर छोटू राम जी की बरसी जो कि 1981 में आ रही है को बड़ी धूमधाम, जोर भाोर से मनाये ताकि चौधरी साहब के बताये हुए सिद्धान्तों पर अमल किया जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार चौधरी छोटूराम जी के पद चिन्हों पर चल कर अच्छे काम करेगी। धन्यवाद!

राव राम नारायण (साहलावास): डिप्टी स्पीकर साहब, जो रेजोलू ान चौधरी संत कंवर जी ने मूव किया है, यही रेजोलू ान मैंने भी दिया था उनका नम्बर पहले आ गया इसलिये उन्होंने इसको पहले मूव कर दिया। मैं भी इस रेजोलू ान की पुरजोर हिमायत करता हूं। चौधरी सर छोटू राम जी के नजदीक

आने का मुझे खास सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1931 से लेकर, जब मैं कालिज में पढ़ता था तब से लेकर उनकी मौत तक मैं उनके काफी नजदीक रहा। चौधरी साहब एक गरीब किसान घराने में पैदा हुए थे। उन्होंने बड़ी कु कलात के साथ अपनी तालीम हसिल की थी। बी0ए0 की तालीम सैंट स्टीफन कालेज से हासिल करने के बाद वे एक अखबार की एडीटिंग करते रहें उसके बाद उन्होंने ला पास किया और फिर आगरा में प्रैक्टिस करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आगरा से ि ाफ्ट होकर रोहतक में प्रैकटिस भाुरू कर दी। वे निहायत मेहनती और ईमानदार भाख्स थे। वह हमे ाा ही गरीब किसानों और मजदूरों के भले के लिये सोचते रहते थे और काम करते रहते थे। वे रात के दो दो बजे तक काम में लगे रहते थे। वे हमे ाा ही यह सोचते रहते थे कि गरीबों का उत्थान कैसा किया जाए और गरीब किसनों, हरिजनों और मजदूरों को साहूकारों के जाल सै कैसे बचाया जाए यानि जो लोग कर्जा में फंसे हुए थे उनको कैसे आजादी दिलवाई जाए। उस वक्त गरीब किसानों के घर और जमीन साहूकारों के कब्जे में थी। साहूकारों से छुटकारा दिलवाने के लिये चौधरी साहब ने कई किस्म के एक्ट बनाये जैसे रजिस्ट्र ान आफ मनी लैन्डर्ज एक्ट, इनडेटडनेस रिलीफ एक्ट, रेस्टीटयू ान आफ मार्टगेजड लैन्ड एक्ट। इन एक्टस के द्वारा गरीब किसानों को साहूकारों के पंजों से छुड़वाने काम चौधरी साहब ने ही किया है। इसी तरह से जिलों के अन्दर डैट कंसिलिए ान बोर्ड वगैरह भी कायम किये गए जिनमें तीन प्रकार के लोग होते थे एक मनी लैंडर्ज दूसरे

जमीरदारों की क्लास और तीसरे लायर्ज की क्लास के लोग इन बोर्डों के सदस्य होते थे ये लोग इकट्ठे बैठ कर यह सोच विचार करते थे कि गरीब किसानों और मजदूरों की कर्जे की दिक्कतों को किस प्रकार हल किया जा सकता है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इन बोर्डों ने आपस में फैसले करवा कर रूरल एरियाज के कर्जाजात बिल्कुल साफ और मुआफ कर दिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी सर छोटू राम जी एक बड़े दिलेर भाख्स थे और वे इकबाल साहब की भाायरी के बड़े भाौकीन थे। वह अमूमन इस भोर को कहते थे –

"खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले

खुदा बन्दे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है?"

चौधरी साहब रि वत के बड़े खिलाफ थे। इसी रि वत के खिलाफ उन्होंने 1923 में एक अंग्रेज डी0सी0 के विरूद्ध रि वत की ि ाकायत गवर्नन से की थी। वह डी0सी0 एक अंग्रेज था जो रि वत लेता था। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी हर स्वरूप बूरा पदासीन हुए।) चेयरमैन साहब, इस केस पर इतनी खींचातानी हुई कि वह चौधरी साहिब को गिरफ्तार करने पर विचार करने लगे लेकिन चौधरी साहब की ि ाकायत के ऊपर गवर्नर ने इंक्वायरी की और यह साबित हो

गया कि वह डी0सी0 रि वत लेता है। फिर उस डी0सी0 को इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापिस जाना पड़ा।

चेयरमैन साहब, चौधरी साहब बड़े दलेर थे। एक सै ान जज की अदालत में एक इनका केस लगा, वह सै ान जज ऐसा था कि छोटी सी बात पर लाइयर्ज को डरा धमका देता था, किसी को बोलने नहीं देता था। जब चौधरी साहब एक मर्डर के केस को प्लीड कर रहे थे तो सै ान जज ने उन्हें हाथ उठा कर रोकना चाहा लेकिन चौधरी साहब ने अपनी बहस जारी रखी। सै ान जज ने कहा कि तुम को मेरा सिगनल दिखाई नहीं देता। चौधरी साहब ने जवाब दिया कि मैं कोई रेल गाड़ी नही हूं जो सिगनल को देख कर चलूं या ठहरूं। चौधरी साहब ने सै ान जज को कहा कि आप इस तरह से जो लाइयर्ज को रोकते हैं यह कन्टेम्पट आफ कोर्ट करते हैं उसके बाद उस सै ान जज ने अपना रवैया बदल लिया उसी दिन भााम को चौधरी साहब के घर जाकर माफी मांगी और आगे के लिये लाइयर्ज को पूरी तरह से सुनने लग पड़े।

चेयरमैन साहब, एक बार गेहूं के रेट के बारे में बात चली। करनाल रैस्ट हाउस में ठहरे जब चौधरी साहब लार्ड वेवल को मिलने गये उस वक्त मैं भी वहां पर था इन्होंने लोगों केा कहा कि यह बूढ़ा या कैद में होगा या जमींदारों के लिये कुछ लेकर आयेगा। इस पर वेवल साहब को झुकना पड़ा और जो रेट गेहूं का चौधरी सर छोटू राम जी चाहते थे, वही मकरर्र करना

पड़ा। इसी के कारण उनकी छाप सारे दे ा पर पड़ी। चौधरी साहब 1936 में स्पीकर बने और 1937 में बनियनिस्ट गवर्नमैंट में एक पावरफुल वजीर बने। 1921 से 1945 तक भी पंजाब की सियासत पर इनकी बड़ी छाप रही।

सर खिजर हियात खां चौधरी साहब पर बड़ा भरोसा रखते थे। जिन्ना साहब ने मुसलिम मैम्बर्ज की मीटिंग बुलाई पर वहां पर किसी मैम्बर ने उनकी मदद नहीं की। चौधरी रियासत अली खां जो कि उस वक्त के पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी थे, ने कुछ कहा जो कि जिन्ना साहब की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि आपकी लीग को तो यहां खोती भी नहीं जानती फिर बाद में ममदोट साहब ने उन्हें समझाया। उसके बाद सियालकोट में मुसलिम लीग ने एक मीटिंग करनी चाही, सियालकोट में दफा 144 लगा दी गई लेकिन चौधरी साहब गिरफ्तारी से बड़े घबराते थे। वे पंजाब को छोड़ कर भाग गये। उसके बाद उन्होंने जमींदारा लीग को मजबूत बनाने के लिये सारे पंजाब का दौरा किया और तीस लाख रुपये जमींदारा फंड के जमा किए। इन दिनों मुस्लमान, हिन्दु और सिक्ख सब इनके फालोअर बन चुके थे। उन दिनों लायलपुर में एक कान्फ्रैंस हुई थी जिसमें मुस्लमानों को एक जैसा समझते थे अगर वे पार्टी ान के टाईम पर जिन्दा रहते तो मुमकिन था कि पाकिस्तान न बनता। भाखड़ा की स्कीम सन 1921 से उनके दिमाग में थी और जब वे 1937 में मिनिस्ट्री में आये तो उन्होंने इस पर तेजी से काम भुरू किया लेकिन सीनियर अंग्रेज

इंजीनियर इस काम में उनको कोआप्रेट नहीं करते थे। सर बट्रांड ग्लांसी उस वक्त गर्वनर थे। इन्होंने गवर्नर से बात करके सात सीनियर अंग्रेज इंजीनियरों को सुप्रसीूड करवा कर खोसला साहब को चीफ इंजीनियर बनवाया था और खोसला साहब और कंवर सैन को डेम की स्टडी के लिये बाहर अमेरिका भिजवाया। उनकी स्टडी के आधार पर यह भाखड़ा डैम तामीर हुआ। एक दफा चौधरी सूरज मल और मैं उनके पास बैठे थे तो चौधरी सूरज मल ने उनसे कहा कि आपकी जमींदारा लीग कागजों पर ही है क्योंकि न तो आपने कोई कमेटियां बनाई हैं, न कोई प्रैजीडैंट बनाया है और न ही कोई सैक्रेटरी बनाया है। उन्होंने कहा था कि हमारी जो तहरीक है वह आइंदा चलती रहेगी। जैसे हिन्दुओं में आर्य समाज की तहरीक चल रही है उसी तरह से यह भी चलती रहेगी।

श्री सभापतिः राव साहब अब आप कन्कलूड करें क्योंकि बाद में मंत्री जी ने भी जवाब देना है।

राव राम नारायणः तो मैं समय का ध्यान रखते हुए हाउस से प्रार्थना करता हूं कि इस रैजोल्यू ान की सब हिमायत करें और महान सपूत की सौ साला जयन्ती विफिटिं मैनर से मनाई जाये।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा (किलोई): चेयरमैन साहब, यह एक आर्थिक और ऐतिहासिक रैजोल्यू ान आया है और इस रैजोल्यू ान ने इतिहास को एक मोड़ दिया है, इसलिये मैं इसकी

ताइद करता हूं। चौधरी छोटू राम क्या थे ? लहरों से जो टकराये उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टकराये उसे सर छोटू राम कहते हैं। हिन्दुस्तान की सर जमीं पर जहां ऋशि दयानन्द ने मजहबी और सामाजिक नीतियों को निचोड़ कर रख दिया और करैक्टर को झिंझोड़ कर रख दिया वहां सर छोटू राम ने सियासी और आर्थिक पोजी ान को निचोड़ कर रख दिया। 80 फीसदी गरीब आदमी चाहे वे पाकिस्तान में बसते हैं, चाहे बंगला दे ा में बसते हैं और चाहे हिन्दुस्तान में बसते हैं, उनको एक नया रास्त दिया जिसके ऊपर आज तक वे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो उनकी यह सब से बड़ी देन है। जहां तक सामाजिक नीति का ताल्लुक है वह मजहब से बहुत ऊपर थी। उन्होंने सिक्ख, मुसलमान, हिन्दू और इसाई को एक जगह बैठा कर दिखा दिया था तो जहां रूस को अपने लैनिन पर फखर हे, वहां हिन्दुस्तान को सर छोटू राम पर फखर है। वे हिन्दुस्तान के लैनिन थे। उन्होंने हिन्दुस्तान के गरीब आदमियों को एक जगह इकट्ठा किया और आज तक, वे वगैर किसी जात पात के और बगैर किसी भेद भाव से चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। जाहं तक सर छोटू राम का ताल्लुक है, उनकी नये इतिहास में पहली जगह होगी। हमारा जो नया इतिहास होगा वह आजादी से भाुय नहीं होगा बल्कि वह प्रार्टी ान से भाुय होगा। यह एक नया मोड़ है कि हिन्दुस्तान का नया इतिहास पार्टी ान से भाुरू होगा क्यौंकि उस पार्टी ान को हटाने में और उस पार्टी ान में रूकावट पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ सर छोटू राम का रहा है। इतिहास चिल्ला चिल्ला कर कह

रहा है कि हिन्दुस्तान के अंदर उन्होंने जो अपनी नीति और सिद्धान्त रखे थे, वह मजहब और जात से ताल्लुक नहीं रखते थे। बल्कि उन्होनं जो सिद्धांत दिये थे, वे इंसान की भलाई के लिये दिये थे। इसलिये यह जो रैजोल्यू ान आया है यह इतिहास में एक मोड़ है जिससे एक नया इतिहास खड़ा हो रहा है। इस नये इतिहास की लाइट में 80% लोग चाहे वे हिन्दू हों, चाहे पाकिसतानी हों और चाहे बंगला दे ा, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान किसी समय वापिस इकट्ठे मिलेंगे तो ये सर छोटू राम की वजहइ से ही मिलेंगे क्योंकि इन तीनों दे ाों के बीच में से किसी की भी आंख उनके सामने नहीं उठी थी। अगर सर छोटू राम पार्टी ान के समय जिन्दा होते तो पाकिस्तान बनने का सवाल ही पैदा न होता। इन भाब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि सर छोटू राम की सौंवीं जयंती मनाने के लिये एक कमेटी बनाई जाये और उनके जो सिद्धान्त थे उनको हिन्दुस्तान के 80% आदमियों को मानना चाहियै।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): चेयरमैन साहब, मैं इस रैजोल्यू ान की पुरजोर ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। चौधरी साहब ने जितना इस महान हस्ती के बारे में कहा है कि बिलकुल दुरूस्त बताया है, मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं। चौधरी छोटू राम जी इंसान नहीं महान हस्ती थे। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और वैस्ट पंजाब जो उस वक्त का पंजाब था सभी 36 बिरादरियों की रहनुमाई की। चौधरी साहब एक बिरादरी के नहीं

थे वे तो सभी 36 बिरादरियों के नुमाइंदे थे। वे कमेरे की बड़ाई करते थे और लुटरे की मुखालफत करते थे। कमेरा वह है जो अपनी निजी मेहनत की कमाई करता है और लुटेरा वह जो दूसरे की कमाई को लुटता है। जब साहूकार लोग जो गरीबों का खून चूसते थे, चौधरी छोटू राम उनकी मुखालफत करते थे। साहूकार से गरीब लोग कर्जा लेते थे और साहूकार अपने हिसाब से उनसे कर्जा वसूल करते थे। इस तरह वे साहूकारों के कर्जे के नीचे दबे हुए थे। छोटू राम जी नै बिल परस करवार कर साहूकारों से गरीबों का छुटकारा करवाया। मैं सरकार से कहूंगा कि वह सर छोटू राम के बताये हुए कदमों पर चलने का प्रयास करे और गरीबौं की जितनी मदद कर सकती है करे। इस तरह सर छोटू राम जी सिर्फ हरियाणा के नहीं, बल्कि भारतवर्श के महान इन्सान थे। चौधरी छोटू राम जी के बारेम में जो किताबें हैं, वे स्कूलों और कालेजों में पढ़ाई जानी चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी के बच्चे छोटू राम जी के कदमों पर चल कर महान बन सकें।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह): कौन सी किताबें हैं जो पढ़ाई जायें ?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: किताबों को तो नाम मालूम नहीं है फिर बता दूंगा। सर छोटू राम जी ने उस समय यह अपील की थी कि अनाज का भाव ज्यादा मुकर्रर किया जाए। कपड़े का भाव अनाज के भाव के मुताबिक मुकर्रर किया जाये। चेयरमैन साहब, आज हम देख रहे हैं कि कपड़े के भाव दो सौ

तीन सौ रुपया प्रति मीटर तक भी है लेकिन अनाज का भाव कम है। सर छोटू राम जी ने इस बात के लिये अंग्रेजों की मुखालफत मोल ली। छोटू राम जी को वायसराय ने बुलाया और कहा कि हम अनाज कम भाव पर लेना चाहते हैं। छोटू राम जी ने जैसा कि आपको पता है, उसको जवाब दिया कि मैं कम दाम पर गेहूं नहीं उठने दूंगा और खड़ी फसल को आग लगवा दूंगा। आज सभी एम0एल0एज0 इस बात को मानते हैं। मैं अपने हर सदस्य तथा वजीर को कहूंगा कि जिस तरह चौधरी साहब ने काम किये हैं, उसी तरह ये भी करें।

Sh. Verender Singh: On a point of order, Sir, इनको कहें कि रैजोल्यू ान पर बोलें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चौधरी साहब मैं यह कहना चाहता हूं .....

श्री सभापतिः आप रैजोल्यू ान पर बोलें।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः सर छोटू राम जी ने गरीब मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा। वे कहते थे कि जो मजदूर को तनख्वाह मिलती है उससे उसका खर्चा पूरा नहीं चलता। वे किसी में भेदभाव नहीं रखते थे। उन्होंने अपने घर में भी हरिजन नौकर रखा हुआ था। चेयरमैन साहब, 1981 में सर छोटू राम जी की जन्म भाताब्दी जो मनाने जा रहे हैं, वह बड़ी धूम धाम से माननी चाहिये। उन्होंने गरीबौं की भलाई के लिए

सरकार की मुखालफत की। परिणाम स्वरूप चौधरी साहब के सगे भतीजे को मुअत्तिल कर दिया गया था लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से भतीजे के लिए सिफारि ा नहीं की। वे कहते थे कि मैं अपनी पोजी ान डाउन नहीं करना चाहता। छोटू राम जी जो आज स्वर्ग सिधार चुके हैं, हम सभी सदस्यों और वजीरों को, उनके नक्े कदमों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे अच्छे कार्यों के लिए अपने पद की परवाह ने करें। उन्होंने अपनी पोजी ान बनाये रखने के लिए क मीर के प्राइम मिनिस्टर का पद भी ठुकरा दिया था। सर छोटू राम जी के समय में जैसे साहूकार लोग, कर्जदार से ब्याज लेने के लिए घर के सामने खड़े रहते थे। उसी प्रकार आज हमारी सरकार उसके सिर पर खड़ी रहती है। जो गरीब है उसको कर्जा नहीं दिया जाता लेकिन उसके मुकाबले में कारखानेदारों को एक लाख रुपये तक कर्जा दिया जाता है। मैं संत कंवर जी और अन्य सदस्यों की तरफ से कहता हूं कि आज गरीब किसान को कर्जा न देकर सरमायेदारा को कर्जा दिया जाता है। किसान कौ कहीं नौकरी भी नहीं दी जाती। मैं यह कहूंगा कि यह सरकार किसानों की है लेकिन फिर भी वह किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती (विघ्न) 36 बिरादरी एक होकर सरकार से यह मांग करती हैं कि किसानों की उपज का पूरा मूल्य दिया जाए .....

Mr. Chairman: Please wind up.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सारी पार्टियों को लेकर एक कमेटी बनाये ताकि सर छोटू राम जी की जन्म भाताब्दी बड़ी धूमधाम से मनायी जाये।

जेल मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी): चेयरमैन साहब, यह मामला सरकार के नोटिस में पहले से ही है और अभी तो भाताब्दी मनाने में दो साल का समय बाकी है। इसके लिये कमेटी बनायी जायेगी तथा अच्छे ढंग से उनकी भाताब्दी मनायी जाये तो ठीक रहेगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: सारी पार्टियों को मिलाकर कमेटी बनायी जाये तो ठीक रहेगा।

चौधरी मेहर सिंह राठी: हम बड़े सोफिस्टिकेटिड ढंग से मनायेंगे। मैं मैम्बर साहेबान से कहूंगा कि वे इस रैजोल्यू ान को वापिस ले लें। उनकी भाताब्दी हम बड़े अच्छे ढंग से मनायेंगे।

आवाजें: बड़े अच्छे ढंग से मनायेंगे।

चौधरी संत कंवर: चेयरमैन साहब, मुख्य मंत्री जी तो इस समय मौजूद नहीं हैं परन्तु मंत्री जी ने जो अ योरै।स दी है मैं उसको ध्यान में रखते हुए इस रैजोल्यू ान को वापिस ले लूंगा।

श्री सभापतिः मंत्री महोदय ने अ योरैंस दे दी है, तो क्या आप इसे विदड्रा करते हैं या मैं इसे पुट करूं ?

श्री वीरेन्द्र सिहः जब सदन ने और वजीर साहब ने अ योरैंस दी है तो आप इस रैजोल्यू ान को विदड्रा कर लें।

चौधरी संत कंवरः मैं इस रैजोल्यू ान को विदड्रा करता हूं।

Mr. Chairaman: Has the Hon. Member the leave of the House to withdraw his resolution ?

(Voices : Yes)

The resolution was, by leave of the House, withdraw.

(2) राज्य में रहने वाले ि ाक्षित हरियाणाा अधिवासी व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने सम्बंधी।

स्वामी आदित्यवे ाः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं– कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारि ा करता है कि वह राज्य में रहने वाले ि ाक्षित हरियाणा अधिवासी व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का उपबंध करे।

16.00 बजे।

Mr. Chairaman: Motion move-

This House recommends to the State Government to provide un-employment allowance to the education persons of Haryana domicile residing within the State.

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): सभापति जी, आज जो मैंने सदन के सामने प्रस्ताव रखा है, यह मेरे दिमाग की ही कल्पना नहीं है बल्कि हमारे दे ा की ऐतिहासिक परम्परा है। वेदों से लेकर के गीता तक यह परम्परा रही है कि हर व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिये ठीक प्रबन्ध किया जाता था जैसे कि :–

सर्वे भवन्त सखिन, सर्वे सन्तु निरामया,

सर्वे भद्राणि प यन्ति, मा कि चद दुःख भाग्भवेत।

सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरापद हों। सभापति जी, इस भावना को ले करके केवल यह सरकार ने ही नहीं किया था बल्कि हमारी इसी धरती के महान भाासक आ ापति ने यह घोशण की थी कि –

न में स्तेनों जनपदे न कदर्य, न मद्यपः नाचहिताः अग्नि, न स्वैरी स्वैरिणी कुता।

हमारे राज्य में कोई चोर न हो, कोई कंजूस न हो, कोई भाराबी न हो। इस प्रकार उस समाज रचना में हर एक व्यक्ति बड़ा सुखी सम्पन्न था। महाराज मन ने मनुस्मृति में ललकार कर यहां तक कह दिया कि अगर रोजगार की व्यवस्था समाज में नहीं की जाती, समाज का भाासक वर्ग बच्चों की पढ़ाई

के लिये प्रबंध नहीं करता तो ए नौजवान! तू केवल तीन दिन तक इंतजार कर। अगर तीन दिन के अन्दर सरकार की ओर से तेरी जीविका उपार्जन की व्यवस्था नहीं की जाती तो तुझे मैं पूरा अधिकार देता हूं कि जहां से तुझे खाने को मिले उसे प्राप्त करने की कोि ा ा कर। अपने उदर की पूर्ति के लिये चाहे खेत से मिले, चाहे खलिहान से मिले, चाहे बैंक से मिले, चाहे खजाने से मिले कहीं से भी मिले तुम छीन लो और अगर कोई आदमी आकर कहता है कि नौजवान तुम ऐसा क्यों करते हो तो उसे यह ख्याल करके कह देना चाहिए कि –

तथेव सप्तये मुक्ता, भुकतानि ाड़ न न्तः

अस्तेन विद्यानेन हर्तव्यं होन कर्यण,

ख्यालात क्षेत्रात गारदवा यथा वायुप लम्यते।

आख्यातव्यम त तस्यै पृच्छते यदि पृच्छति।।

इस किस्म के डर को छुपा करके नहीं रखना चाहिए। सभापति जी, आज कितनी विडम्बना है कि हमारे दे ा का नौजवान जब एम्पलायमैंट एक्सचेंज में नाम लिखवा कर इंट्रव्यू देने के लिये जाता है तो उसमें बड़ी उमंग और उत्साह की भावना होती है कि मुझे रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं यह देखता हूं कि प्रथम श्रेणी में एम0ए0, बी0ए0 पास लड़के रोजगार की इंतजार करते करते बूढ़े हो गये हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं लेकिन उनकी अभिलाशा पूर्ण नहीं हुई। सरकार की ओर से रोजगार की

कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इन हालात में कोई नौजवान बैंक में डाका डाल देता है तो अपराधी घोशित करके उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में दोनों टाईम उसकी रोटी का इन्तजाम किया जाता है, यदि बीमार रहता है तो दवाई का इंतजाम करते हैं, कपड़ा फट जाए तो कपड़े का इंतजाम करते हैं और अगर वह रोटी नहीं खाता है तो उसे मार मार के खिलाई जाती है लेकिन जब बाहर वह नौजवान नौकरी मांगता था तो कहते थे कि भाग जाओ, कोई नौकरी नहीं। आज यह हालात हो गए हैं कि नौजवान बेसहारा होकर सिद्धान्तहीन हो कर अपने रास्ते भटक रहा है। उसकी जिम्मेवारी नौजवान पर नहीं है बल्कि सरकार पर है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। जितेन समजवादी दे ा हैं, उनमें बेरोजगारी की समस्या नहीं है। वे नौजवान जो काम करना चाहते हैं उनके लिये काम की पूरी व्यवस्था की जाती है। चाहे चीन है, चाहे रूस है और चाहे यूगोस्लाविया है, जो पूंजीवादी दे ा हैं वे सब बेरोजगारी भत्ता देने लग गए हैं हमारे दे ा का संविधान इस बात का परिचायक है, जैसा कि उसकी प्रस्तावना में साफ लिखा हुआ है कि हम हर एक नौजवान को आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय देंगे। संविधान की प्रस्तावना में यह विस्तारपूर्वक लिखा हुआ है लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले दिनों आपने देखा था कि कुछ नौजवानों ने यहां सदन में नारे बुलन्द किए थे कि हमें हलाल मत करो, रोजगार दो। नौजवान कमा कर खाना चाहता है, भत्ते पर नहीं जीना चाहता लेकिन जिस समय भत्ते की बात मानी

जाएगी तो सरकार के ऊपर एक बोझा पड़ेगा। सरकार के ऊपर एक जिम्मेवारी आएगी और उस जिम्मेवारी का एहसास करते हुए सरकार उसके लिये कोई न कोई रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। इन्हीं बातों को ले करके हमारे स्वामी दयानन्द ने यहां तक कहा था कि चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे दरिद्र की संतान हो, चाहे अमीर की हो, 8 साल की आयु से लेकर 25 साल तक विद्यार्थियों के भरण पोशण तथा ि ाक्षा दीक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं कि आज उनकी स्थिति भाोचनीय है। लड़का पढ़े लिखे तो अपनी बला से, भूखा मरे तो अपनी बला से लेकिन यह सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदार महसूस नहीं करती। कहने को तो कहा जा सकता है कि सरकार ने ि ाक्षित बेराजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था की है लेकिन सभापति जी सिर्फ कह देने से तो समस्या हल नहीं हो पाती उसमें बहुत सारी कम्पलीके ांस हैं जिनके कारण समस्या हल नहीं हो पा रही है। आज हमारे समाज का नौजवान पढ़ाई की डिग्री ले कर फाड़ने को मजबूर हो रहा है। बेकारी के कारण वह महसूस करता है कि पढ़ाई की डिग्री बेकार है। वह समझता है कि अगर कहीं डिग्री लेकर जायेगा तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं। आज नौकरी लेने के दो ढंग हैं – "रि तेदारी बताओं नौकरी पाओ" "रि वत दो नौकरी लो"। यह दोनों नारे समाज में बुलन्द हो रहे हैं किसी से छिपे हुए नहीं हैं। यह बात यहीं तक नहीं है। जैसे महात्मा गांधी ने स्पश्ट कहा था कि राश्ट्र की आय जितनी है उससे ज्यादा खर्च करते हैं तो राश्ट्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं

रह सकती। कोई व्यक्ति कपड़ा मकान आदि दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों पर आमदनी से ज्यादा खर्च करता हो तो वह चोर समझा जायेगा। महात्मा गांधी ने भी अपना जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यतीत किया था। उन्होंने स्पश्ट कहा था कि मन्त्री या उच्च पदाधिकारी 500 रुपये से ज्यादा वेतन नहीं लेगा। इस प्रकार उन्होंने एक सीमा निर्धारित की थी लेकिन आज किस प्रकार मन्त्री और पदाधिकारी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दो दो लाख रुपये टैलीफोन पर खर्च हो रहे हैं और दो दो लाख रुपये भत्ते पर खर्च हो रहे हैं। एक तरफ तो हालत यह है कि रोटी खाने के लिये आदमी चोरी करने पर मजबूर हो रहा है और दूसरी तरफ नाजायज खर्चा किया जा रहा है। आपने चण्डीगढ़ में देखा है कि पिछले दिनों रोज फैस्टीवल मनाया गया और उस पर लाखें रुपया खर्च किया गया। कितनी बड़ी विडम्बना है इस गरीब के दे ा में, एक तरफ ऐ ाो अया ाी पर अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ नौजवान भूखा रह कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या यही न्याय है ? उसे कोई पूछने वाला नहीं कि उसे क्या चाहिए ? तेरी हम क्या मदद कर सकते हैं ? सभापति जी ऐसे हालात को देखते हुए, समाज की मांग को देखते हुए बेरोजगारी की समस्या को हल करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी बात को लेकर हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार ने घोशणा की है कि उनके यहां जो पढ़े लिखे बेकार नौजवान हैं उनको वे 50 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं सदन के सामने यह सुझाव रखना चाहूंगा

कि यदि हमारी सरकार भी बेरोजगाचरी भत्ता देने की बात मान लें तो कम से कम नौजवान अपना पेट तो भर सकें। हरियाणा में एक लाख 20 हजार पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। आज सारे हरियाणा में 30 हजार नौकरियों के रिक्त स्थान पड़े हैं, इसलिये इनमें से 30 हजार को तो फौरन नौकरी पर लगाया जा सकता है। इनमें से 30 हजार ऐसे नौजवान होंगे तो नौकरी के लिये ज्यादा इच्छुक नहीं होंगे क्यों वे सम्पन्न घरों से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद 60 हजार नौजवान बचते हैं। इन 60 हजार में से 40–50 हजार के लगभग मैट्रिक पास और 10 हजार के लगभग बी0ए0, एम0ए0 पास होंगे। जो नौजवान मैट्रिक तक पढ़े हैं उनको 50–50 रुपये और जी बी0ए0, एम0ए0 उनको 100–100 रुपये मासिक भत्ता दिया जाए। सरकार का टोटल खर्चा मु कल से चार करोड़ रुपया वार्शिक बैठेगा। आज हमारी सरकार बड़े बड़े होटलों, बड़खल जैसी झीलों पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रही है। वहां से कुछ नहीं मिलता। जो दूसरी जगह से आने वाले लोग हैं, ए ाोअयासी करने वाले लोग हैं, रंगीनियां मनाने वाले लोग हैं उन पर सरकार खर्च कर रही है। सभापति जी पिछले साल आपने देखा होगा कि 10 लाख रुपये पिंजौर गार्डन पर खर्च किए गए। सरकार को इस तरह की फिजूल खर्ची रोकनी चाहिए। टी0ए0डी0ए0 पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोक कर यदि सरकार थोड़ा सावधानी से खर्च करे तो उसका फायदा यह होगा कि सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हमारे हरियाणा में कत्ल और छुरेबाजी के केसिज जो बेरौजगारी के कारण हो रहे हैं, यह

बंद हो जायेंगे। सभापति जी, बड़े दुख के साथ कहिना पड़ रहा है कि दे ा का नौजवान, हरियाणा का नौजवान जेल की सीखचों में सड़ रहा है। किस बात के लिये ? क्योंकि उसने अपने उदर की पूर्ति करने के लिये पिक पाकेटिंग की है। नौजवान ने किसी बात के लिये सम्गलिंग की है, अपने उदर की पूर्ति के लिये, किस बात के लिये बैंक में डाका डाला, अपनी क्षुधा की अग्नि बुझाने के लिए। अगर समाज का नौजवान गलत कामें में पड़ कर गलत दि ाा में भटकता जाएगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस राश्ट्र का क्या बनेगा ? वेद में लिखा है :–

तथैव सप्तये मुक्ता, भुक्तानि ाड न न्तः

अस्तेन विद्यानेन हर्तव्यं होन कर्यणा,

ख्यालात क्षेत्रात गारद्वा यथा वायुप लभ्यते।

आख्यातव्यम ते तस्यै पृच्छते यदि पृच्छति।।

इस धरती पर किसी व्यक्ति को बेकार नहीं रहना चाहिए। यह हमारे वेद का आदे ा है। विनोबा जी ने कहा था कि अगर मेरे पास किसी चोर का मुकद्दमा आ जाये तो उसको छः महीने की सजा देने की बजये 6 एकड़ जमीन दूंगा ताकि वह जमीन को जोत कर अपना गुजारा कर और चोरी करने की प्रवृति समाप्त हो। हमारे पड़ौसी राज्य ने भी यह सोचा है कि बेरोजगारों को अगले साल बेरोजगारी भत्ता देंगे .....

श्री सभापतिः आप अपनी स्पीच को कनकलड करें, काफी टाईम ले लिया है आपने।

स्वामी आदित्यवे ाः दो मिनट में समापत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दे ा के नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। दे ा के नौजवानों को हमने दे ाभक्त बनाना हैं। दे ा भक्त बनाने के लिये सबसे अहम सवाल उनको रोजगार मुहैया करने का है, जिसका इंतजाम सरकार को करना आव यक है। सरकार गरीब की हिमाजत का नारा देती है, लेकिन अगर सही मायनों में गरीब की हिफाजत नहीं की जाएगी तो यहां पर ऐसी सामाजिक क्रान्ति, समग्र क्रांति आयेगी जिसका मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस साल के बजट में यह व्यवस्था कर दी जानी चाहिए कि बेरोजगार नौजवान को 50 रुपये और 100 रुपये बेरोजगारी भत्ता जरूर दिया जाएगा। इन भाब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे समय दिया अपने विचार सदन में रखने के लिये। अगर आप रोजगार देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आगे भयानक क्रांति होगी। उसको रोकना कोई आसान काम नहीं, इसलिये नौजवानों को ही मार्ग दिखा कर दे ा को सुधारने के लिये कदम उठाए जाएं और बेरोजगारी भत्ता अव य दिया जाए।

श्री मांगे राम गुप्ता (जीन्द): चेयरमैन साहब, स्वामी जी ने एक महत्त्वपूर्ण विशय पर सदन का ध्यान दिलवाया है। मैं समझता हूं कि समय को देखते हुए इस दि ाा में उचित कदम

उठाने चाहिए। सरकार के सामने और समाज के सामने बेरोजगारी की बहुत भारी समस्या है। चेयरमैन साहब, यह बात बिल्कुल ठीक है –

तावद भय समय तमयं

यावद भय मनागतम्

अनागतम तु भार्यूम

विलयः नरः करो ठचिरम।

जब तक भय पास नहीं हो तक तब भय से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भय पास आ जाये तो यह फर्ज बनता है कि उससे बचने के लिये जल्दी से जल्दी उचित कदम उठाएं। कांग्रेस की सरकार ने खिलाफ ही जय प्रका ा नारायण ने जो नारा दिया था, अगर दे ा का नौजवान उस वक्त सहयोग न देता तो जनता पार्टी की सरकार बनने का सपना पूरा न होता। नौजवान हमारे साथ इसलिये नहीं लगे थे कि उन्होंने वजीर बनना है, इसलिये नहीं लगे थे कि उन्होंने एम0एल0ए0 बनना है बल्कि इसलिये लगे थे कि दे ा की राजनीति में परिवर्तन लाना है। ऐसा दिखाई देता था कि पढ़ा लिखा नौजवान जिन्होंने एम0ए0पी0एच0डी0 की डिग्रियां ले रखी हैं, उसके सामने यह उद्दे य था कि कांग्रेस सरकार पलटे और नई सरकार बने। इन नौजवानों के लिये सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे यह बेकार न

फिरे, दर दर धक्के न खाते फिरें। अफसोस की बात है कि आज का नौजवान बेकार घूम रहा है। इस सम्बंध में लिखा है –

अत्रं निजः परोबीति गनना लघु चैतसाम

उधार चरितरता ननतु वसुदेव कुटम्बकम।

दे ा का इतिहास बताता है कि बड़े आदमियों का यह काम है कि वे किसी एक वर्ग के लिये नहीं सोचते हैं, हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं। इसी प्रकार सरकार भी एक बड़े इन्सान की तरह धरती पर रहने वाला हर इन्सान, चाहे वह किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखता हो अगर उसकी उचित मांग है तो उसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। चेयरमैन साहब, आप किसी भी जगह पर जाकर देख लें चाहे रेलवे स्टे ान पर देख लें, बस स्टैंड पर जार देख लें, सिनेमा के बाहर या अन्दर जाकर देख लें, हर जगह नौजवान बुरी आदतों का ि ाकार हो गया है, तोड़ फोड़ कर रहा है, उसके सामने अन्धेरा है। कुछ करने के लिए असमर्थ है, इन हालात में वह यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हमने इस राज को इसीलिये बदला था ? क्या हम बी0ए0, एम0ए0 पास करके इसी तरह फिरते रहें ? वह बी0ए0, एम0ए0 की डिग्री लेकर मां बाप के पास जाता है। किसी मां बाप ने अपनी जमीन गिरवी रख कर अपने लड़के को पढ़ाया है, किसी ने सरकार से लौन लेकर पढ़ाया है, लेकिन परिणाम यह हुआ कि आज न वह घर का काम करता है और न ही उसको नौकरी मिलती है। जब उसके मां

बाप उसको यह सब बातें कहते हैं तो वह उनको बरदा त नहीं कर पाता और घर से भाग निकलता है। उसके दिमाग में बुराई का प्रवे ा कर जाता है। हमारा इतिहास बताता है कि हमारे दे ा की हजारों देवियां वै याएं बनने पर मजबूर हो गई थीं। इसका कारण यह था कि उनकी मजबूरी थी और सरकार ने उनको सम्भालने की कोि ा ा नहीं की। आज दिखाई देता है कि दे ा का हर नौजवान ि ाक्षित है और सरकार भी कोि ा ा कर रही है कि हिन्दुस्तान का हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए और इस तरीके से पढ़ाई चलती रही तो हमारे बच्चे पढ़ते चले जायेंगे और बेकारी की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती चली जाएगी। इसलिये चेयरमैन साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, जैसे कि किसान की तकलीफ को दूर करने के लिये हम सब उत्तेजित हैं, जब तक किसानी की हालत अच्छी नहीं होगी तब तक दे ा तरक्की नहीं कर सकता। उसी तरह इस बेरोजगारी के मसले को भी हमें हल करना चाहिए। जब तक पढ़े लिखे नौजवान को नौरी या कोई न कोई काम धंधा नहीं मिलेगा। तब तक दे ा तरक्की नहीं कर सकता। भगवान न करे, अगर सरकार ने इस समस्या पर काबू न पाया तो भाायद दूसरी क्रांति न हो जाये। मैं सरकार का वि ोश तौर पर इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हुई हैं, उनको कारोबार दिलवाने की कोि ा ा की जाए ताकि वे अपने जीवन को सैट अप कर सकें। जब तक वे अपने आपको सैट न कर लें, तब तक माहवारी भत्ता जरूर दिया जाए। (चौधरी जगजीत सिंह पोहलू की

तरफ से विघ्न) चेयरमैन साहब, पोहलू साहब बोलने के लिये बड़े उतावले हैं। मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को कम से कम 200 रुपये माहवारी भत्ता दिया जाए। मैं तो 200 रुपये महीना की मांग करता हूं, लेकिन जितना सरकार दे सकती है, वह दे या उनको काम दिलवाने की कोि ा ा करे। इस सम्बन्ध में मेरी एक तजवीज है। जैसा कि मैंने दूसरे मुल्कों से पता किया है कि वहां पर टैक्नीकल एजुके ान 95 फीसदी बच्चों को दी जाती है। वहां पढ़े लिखे बेकारों की समस्या ज्यादा नहीं है। अगर हमारी सरकार भी टैक्नीकल एजुके ान देने की कोि ा ा करे तो हो सकता है पढ़े लिखे नौजवानों की समस्या दूर हो जाए। हमारी ि ाक्षा का ढांचा कुछ ऐसा बन गया है जिससे किताबी हरफ पढ़ने के सिवाये दूसरी किसी किसम की नोलेज नहीं मिलती। वहां पर ढांचा अलग किसम का है। जिस लड़के का दिमाग खेती बाड़ी की तरफ चलता है, उसकी पढ़ाई पहली जमात से ही खेतीबाड़ी के बारे में करवाई जाती है, उसको अलग पढाया जाता है। जिसका दिमाग प ाु पालन9 की तरह है उसको उसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका इंडस्ट्रीज की तरफ चलता है उसको इंडस्ट्रीज की तरफ लगाया जाता है। चेयरमैन साहब, वहां पर इस किसम का प्रौसीजर बन गया है कि जो जिस काम में अच्छा है, उसको वही काम दिया जाता है। फर्ज करो एक क्लास में 10 लड़कें हैं, जो खेती में रूचि रखने वाले हैं, उनकी अलग पढ़ाई होती है, इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में पढ़ाई होती है। खेती करने वाला बच्चा खाद का

हिसाब किताब लगाता है और उस खेती से जो आमदनी होती है वह उसके अकाउंटस में जमा कर देते हैं 10–12 साल वह पढ़ता है और उस वक्त तक उसके अकाउंट में ठोस पैसा जमा हो जाता है और बिजनेस में एक्सपर्ट हो जाता है। जब वह स्कूल से निकलता है उस वक्त उसका दिमाग नौकरी की तरफ नहीं होता, बिजनैस की तरफ होता है और बिजनैस ही करना भुरू कर देता है उसको बिजनैस भुरू करने में दिक्कत आती हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, वहां उनके अकाउंट में जो पैसा जमा हो जाता है, दस बारह साल के दौरान वह उन्हें स्कूल से निकलने के बाद दे दिया जाता है। इससे न तो सरकार के ऊपर बर्डन पड़ता है और न ही लड़के बेकार रहते हैं। चेयरमैन साहब, यह बात मैं हाउस के सामने इसलिये रख रहा हूं ताकि हमारे यहां भी यह सिस्टम लागू हो सके। अगर पढ़ाई का ढंग बदल जाए और इंडस्ट्रीज की तरफ और खेती बाड़ी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि बेकारी की समस्या में कुछ कमी आ जाए। धन्यवाद!

श्री भले राम (बडौदा–अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, जब सन् 1947 में हमारा दे ा आजाद हुआ और जब हमारा संविधान बना तो उसमें कल्याणकारी राज्य की बात लिखी गई हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकार हरेक के लिये रोटी, कपड़े और मकान का इंतजाम करेगी। जवाहर लाल नेहरू ने कहा भी था कि हमें राजनैतिक आजादी तो प्राप्त हो गई है लेकिन आर्थिक आजादी प्राप्त करनी है। लेकिन खेद से कहना पड़ता है कि 30

साल तक कांग्रेस सरकार वायदे तो बड़े बड़े करती रही लेकिन वास्तव में किया कुछ नही। इसकी वजह से बेकारी बढ़ती रही। यही कारण है कि जनता ने अब की बार कांग्रेस सरकार को बदल दिया क्योंकि उसने देखा कि कांग्रेस सरकार वायदे तो बहुत करती है लेकिन उनको पूरा नहीं करती। जनता पार्टी के घोशणा पत्र में यह था कि इस पार्टी की सरकार बेरोजगारी दूर करेगी। बड़ी खु ाी की बात है कि देवी लाल सरकार ने इस दि ाा में कई कदम उठाएं हैं। इसके लिये हम 11 तारीख से एक कम्पेन भी चलाना चाहते हैं। इसमें एक हरिजन होगा, एक बैकवर्ड क्लास का आदमी होगा, एक किसान होगा और एक गरीब बनिया होगा। उम्मीद है कि इस कम्पेन से बेरोजगारी काफी हद तक कम हो सकेगी। चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि देहात तें मैनुअल वर्क करने वाले लोग भी रहते हैं उनमें जो बेकारी की समस्या है उसके लिये भी हमारी सरकार वर्क फार फूड नामक प्रोग्राम चला रही है। गवर्नर ऐड्रैस में भी आपने देखा हेगा कि जिस ढंग से अब स्टूडैंटस तैयार होंगे उससे यह समस्या ज्यादा विकट नहीं होगी। 10+2+3 का जो यह फार्मूला है इसके तहत काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली से लेकर दसवीं कक्षा तक बच्चे हाथ से काम करना सीखेंगे। बी0ए0 के लैवल तक पहुंचते पहुंचते वे अपने काम में इतने निपुण हो जाएंगे कि वे पढ़ाई खत्म करते ही अपना धंधा चला सकेंगे। फिर भी स्वामी जी ने अन एम्पलायमैंट भत्ता देने की जो बात कही है, वह ठीक है। यह मिलना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन हाउस के सामने एक सुझाव

जरूर रखूंगा। जवाब तो वैसे मन्त्री महोदय देंगे हो सकता है कि वे कहें कि पैसे की मजबूरी है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वह नौकरी में लग जाए तो दिया गया पैसा उसकी तनख्वाह में से काट लिया जाए। बस, यही बात कह करके मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्रीमती भाान्ति देवी (कैलाना)– चेयरमैन साहब, बेरोजगारी भत्ते के बारे में स्वामी आदित्यवे ा जी ने जो ध्यान आकर्शण प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं उसके अनुमोदन के लिये खड़ी हुई हूं। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बेकारी इतनी बढ़ रही है कि हमारे नौजवान दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। बहुत से मैट्रिक, बी0ए0 और एम0ए0 पास लड़के नौकरी के लिये रखी गई आयु सीमा को पार कर चुके हैं किन्तु किसी को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह बात जरूरी है कि जो बच्चे गरीबी की हालत में ग्रैजए ान या पोस्ट ग्रैजुए ान करेंगे, वे अव य चाहेंगे कि उन्हें नौकरी भी उपलब्ध हो। कांग्रेस ने बेरोजगारी का जो जनाजा निकाला था उसकी अपेक्षा मैं कहूंगी कि हमारी जनता सरकार ने रूचि तो अव य ली है कि किसी तरह से बेरोजगारी की समस्या हल हो, लेकिन जब तक कोई बात इम्पलीमैंट न हों, प्रैक्टिकल भोप में न आये तो कैसे तसल्ली की जा सकती है। अभी 11 तारीख से हमारा एक प्रोग्राम भाुरू हो रहा है। नौकरी तो उपलब्ध हमारी सरकार नहीं करा रही है किन्तु यह लघु उद्योग धन्ध बेरोजगार लोगों को उपलब्ध करायेगी। यह बहुत सुन्दर

स्कीम है लेकिन इसमें भी जो प्रैक्टिकल कठिनाइयां हैं जब तक उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी तक तक हमें कामयाबी मिलना कठिन है। तो मैं चाहूंगी कि जब तक हमारी सरकार बेरोजगार बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम न हो जाए तब तक कम से कम यह जो पांच पांच, दस दस रुपये के पोस्टल आर्डर बच्चों से लिये जाते हैं, वे माफ किए जाएं। यह बड़ा रचनात्मक सुझाव है क्योंकि बच्चों के मां बाप उनसे कहते हैं कि बड़ी मु कल से तो हमने तुम्हारी पढ़ाई कराई है, अब इतने पैसे कहां से लाएं। दूसरी अर्ज मेरी यह है कि बेरोजगारी भत्ता चाह वह 100 रुपये का हो, चाहे 80 रुपये का हो, चाहे 50 रुपये का हो, जब तक सरकार रोजगार उपलब्ध न करा पाए, अव य ही मिलना चाहिए। एक सुझाव मैं और देना चाहती हूं। पिछले सै ान में भी यह बात आई थी लेकिन उस पर कोई वि ोश तवज्जह नहीं दी गई। मैं चाहती हूं कि जिन बच्चों के नाम 10–10 साल से एम्पलायमैंट ऐक्सचैंज में दर्ज हैं जिनको रोजगार दिलाने में सरकार असमर्थ रही है और उनकी आयु सीमा पार हो चुकी है उनको आयु में कुछ छूट दी जाए। इन सुझावों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं।

चौधरी ई वर सिंह (गहला–अनुसूचित जाति): आदरणीय चेयरमैन साहब, मैं स्वामी आदित्यवे ा के इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार जब किसी नौजवान को डिग्री देती है तो यह इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि यह उसकी रोटी

और रोजी का भी इंतजाम करे। अब समस्या इस बात की है कि ि ाक्षा ही ऐसी दी जाती है जो केवल बाबू बनाती है। ि ाक्षा की यह प्रणाली अंग्रेज के वक्त से चली आ रही है। आज मैट्रिक या बी0ए0 पास करने के बाद बच्चा सिर्फ नौकरी की तरफ भागता है। उसमें कोई क्रियात्मक काम करने की भाक्ति नहीं होती जिससे दे ा का निर्माण हो सके। इसमें सरकार का दोश नहीं है। दोश ि ाक्षा का है, हमारी ि ाक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को हाथ से काम करना सिखाए। कालेजों या किताबों को रट्टा लगाने या पढ़ लेने से उसमें कोई बड़ी काबलियत नहीं आ जाती। वह तो कुछ दिन के बाद सब कुछ भूल जाता है। मैट्रिक करके दास साल के बाद जब लड़का स्कूल से बाहर निकलता है तो उसमें तथा एक अनपढ़ आदमी में केवल इतना ही फर्क होता है कि पढ़े लिखे में तो अक्षर ज्ञान होता है और अनपढ़ आदमी में नहीं होगा और वह अपनी आजीविका भाारीरिक मेहनत से कमाता है। तो मेरा सुझाव यह है कि पढ़ाई की वर्तमान पद्धति को बदला जाना चाहिए। इसकी वजह 10+2+3 की प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए या किन्डर गार्टन आदि की जितनी भी विधियां हैं, वे सब नयें तरीके से लागू करके बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाये।

श्री सभापतिः यह रेज्योलू ान अनऐम्पलायड को अलाउन्स देने के बार में है इसलिये आप इसी विश पर ही बोलें।

चौधरी ई वर सिंहः चेयरमैन साहब, विद्या अच्छी न होने कारण ही बेरोजगारी फैली हुई है। यहां पर हाउस में यह भी सवाल उठा था कि अज्ञानता के कारण बेरोजगारी की समस्या अधिक बढ़ी हुई है। मैं आपके थ्रू सरकार के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि जो बच्चे मैट्रिक, बी0ए0 या एम0ए0 पास कर लेते हैं, उनको एम्पलायमैंट एक्सचेंज में सीनियरिटी नहीं दी जाती है क्योंकि वे गांव में रहने के कारण अपना नाम पहले दर्ज नहीं करा पाते हैं और भाहरो के लोग पहले ही नाम दर्ज करवा देते हैं अगर कोई जगह एम्पलायमैंट के थ्रू निकलती है तो उनको गांव में समय पर सूचना दी जानी चाहिए ताकि वे नौकरी प्राप्त कर सकें। मेरा सरकार से सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार कार्यालय खोल जाने चाहिए। जो बच्चे भाहर में रहते हैं वे अपना नाम दर्ज पहले करवा देते हैं और उनकी सीनियरिटी बन जाती है। यही कारण है कि भाहर के बच्चे ही अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त करते हैं और गांव के बच्चे बेकार रहते हैं। इसलिये मेरी सरकार से दरखास्त है कि देहातों में एम्पलायमैंट एक्सचेंज खोले जायें और क्रियात्मक काम सिखाये जायें। इन भाब्दों के साथ मैं इस रेज्योलू ान की ताईद करता हूं।

राव दलीप सिंह (कनीना): चेयरमैन साहब, स्वामी जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, मैं इसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। हरियाणा में 30 दिसम्बर, 1978 तक इम्पलायमैंट एक्सचेंजीज में 2 लाख 90 हजार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। इनमें

से मैट्रिक, एफ0ए0 1 लाखउ 20 हजार हैं, ग्रेजुएट 29 हजार 728 हैं और पोस्ट ग्रेजुएट 3 हजार 642 हैं। करीब तीन लाख हरियाणा में बेरोजगार हैं जो सरकार से काम चाहते हैं। चेयरमैन साहब, ऐसे भी काफी बेरोजगार हैं जो हैंडीकैप्ट हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है या जिनकी आंखें नहीं हैं, वे भी रौजगार की तला ा में हैं।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, मैं आपकी मार्फत सरकार से कहूंगा कि अगर उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं तो उन बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाये। अगर सरकार सब नौजवानों को नहीं दे सकती है तो जो बेचारे हैन्डीकैप्ट हैं चल फिर नहीं सकते, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, उनको तो कम से कम बेरोजगारी का भत्ता जरूर दिया जाये। हमारे संविधान के डायरैक्टिव प्रिसीप्लज में दिया हुआ है कि अन एम्पलायमैंट दूर करना स्टेट का सब्जैक्ट है और प्रांतीय सरकार अन एम्पलायमैंट भत्ते के लिए बिल ला सकती है। सरकार चाहे तो इन्र योरैंस स्कीम भी जारी कर सकती है। सरकार जिस व्यक्ति को भी रोजगार दे, उस आदकी की तनख्वाह में इन्र योरैंस स्कीम के तहत पांच रुपए महीना काट लें। इस तरह से अगर बीस हजार आदमियों को रोजगार मिलता है तो एक महीने में एक लाख रुपया बनता है और साल भर में 12 लाख रुपया बनता है। इन्र योरेंस स्कीम के तहत काफी रुपया इकट्ठा हो जायेगा इस

रुपये से सरकार लोगों को रोजगार भी दे सकेगी और बेरोजगारी का भत्ता भी दे सकेगी।

चेयरमैन साहब, अभी एक सवाल सदन में आया था कि जिसका उत्तर फाइनैंस मिनिस्टर महोदय ने दिया था। उस उत्तर से पता चलता है कि लाखों रुपया पैट्रोल पर, टेलीफोन करने पर खर्च किया जा रहा है। अगर सरकार इस पैसे को बचाने के लिये कोई रास्ता अपनाये और फिजूल खर्ची न करे तो यह रुपया लोगों की भलाई के लिये काम आ सकता है। जैसा कि अभी स्वामी ने बताया है कि कुछ लोग फोरन कंट्री का टूर करके भी आये हैं, ऐसे टूर्ज को भी कम किया जाना चाहिए।

चेयरमैन साहब, मैंने गवर्नर साहब को एक बिल बना कर भी भेजा था जो एम्पलायमैंट देने के बारे में अन एम्पलायमैंट अलाउन्स देने के बारे में और एम्पलाएमैंट इन् योरैंस स्कीम लागू करने के बारे में था। उन्होंने वह मुझे वापिस कर दिया है लेकिन मैं उसको हाउस की टेबल पर ले करता हूं। सरकार इस बिल को देख कर दूसरा बिल तैयार कर सकती है।।

श्री सभापतिः राव साहब, आप इस बिल का आफिस में दे दें, वहां पर एग्जामीन कर लेंगे।

राव दलीप सिंहः बहुत अच्छा जी।

श्री भाम ोर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहब, कल बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में यह फैसला

हुआ था कि पहले रेज्योलू ान पर 45 मिनट, दूसरे पर एक घंटा और तीसरे रेज्योलू ान पर पौने दो घंटे डिस्क ान होगी। इस रेज्योलू ान का टाईम खत्म हो गया है।

श्री सभापतिः इसका टाईम पांच बजे तक है।

श्री भाम ोर सिंहः पौने दो घंटे का टाईम मेरे वाले रेज्योलू ान के लिये रखा गया था।

श्री सभापतिः आप बैठिए, अभी टाईम है। अगर जरूरत पड़ी तो हाउस को पौने सात बजे तक एक्सटेंड किया जा सकता है।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी): चेयरमैन साहब, मैं स्वामी आदित्यवे ा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंनें इस प्रस्ताव को सदन में रखा और सदन का ध्यान आकर्शित किया। सदन के सदस्यों ने यहा ंपर अपने विचार व्यक्त किये। आज हमारे दे ा में चारों तरफ गरीबी, बेरोजगारी फैली हुई है। सड़कों तथा विद्यालयों का अभाव है। अगर यह बात किसी अमीर मुल्क में होती कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो हम स्वीकार कर सकते थे लेकिन ऐसे दे ा के अंदर जहां चारों तरफ गरीबी का बोलबाला है और बेकारी है तो यह सारे दे ा के लिये बड़ा चिन्ता का विशय है।

सभापति महोदय, इस समाज के अंदर अगर कोई पढ़ा लिखा नवयुवक ईमानदारी से अपनी जीविकोपार्जन करना चाहता है तो उसके लिये कोई साधान नहीं है। वह बेचारा आठ दस घंटे

ईमानदारी से अपनी रोटी कमाना चाहता है लेकिन फिर भी उसको रोजगार नहीं मिलता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करे, डाका डाले तो इस पूंजीवादी ढांचे में उसको जेल में रोटी, दवाई, मकान और कपड़ा सभी चीजें दी जाती हैं। आप ही सोचिए यह कितनी विडम्बना की बात है कि एक आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है लेकिन उसको रोजगाचर नहीं मिलता है लेकिन जो व्यकित गलत काम करता है उसको सभी चीजों के बारे में गारंटी दी जाती है। वह जेल में जाता है तो उसको भूखा नहीं मरने दिया जाता, हर चीज का प्रबन्ध किया जाता है। इसलिये यह जो सदन में प्रस्ताव रखा गया है मैं इसका अनुमोदन करना चाहता हूं और एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं। सभापति महोदय, बेरोजगारी की समस्या का सबसे बड़ा करण यह है कि सम्पति उत्पादन के साधन कुछ ही सीमित लोगों के हाथों में हैं। एक आदमी खेत का भी मालिक है, नौकरियों पर भी उसका कब्जा है और कारखानों में भी भोयर होल्डर है। इस प्रकार उस व्यक्ति के पास आय के कई साधन हैं परन्तु मितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई भी साधन नहीं है। दूसरी तरफ हजारों नहीं, सैंकड़ों नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक भी साधन रोजगार का नहीं है। सबसे पहले इस दि ाा में हमें यह कदम उठाना चाहिये कि एक व्यक्ति को एक से ज्यादा साधन रखने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके पास आय का धान केवल एक ही होना चाहिये। तभी जाकर बेरोजगारी का कुछ समाधान हम कर सकते हैं। दूसरत

तरफ जेसे मेरे दूसरे साथियों ने सुझाव दिया मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूं। ि ाक्षा की पद्धति डिफैक्टिव होने के कारण हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं इससे बिलकुल सहमत हूं। यह भी कहा गया कि हमारी ि ाक्षा में ि ाल्प और दस्तकारी की ि ाक्षा नहीं है। यह होनी चाहिये। ऐसे ि ाक्षा देने मात्र से इसका समाधान नहीं हो कसता जब तक कि हम अपनी आदत नहीं बदलते। आज इस सदन में जितने सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, इनमें से अधिकां ा व्यक्तियों ने वे कपड़े पहने हुए हैं, जो मिल से बने हुए हैं, जूते वे पहने हुए हैं जो बाटा के यहां बने हुए हैं। जब तक हम अपनी इस आदत को नहीं बदलते कि मिल या फैक्ट्री की बनी हुई चीज नहीं पहननल है, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। कपड़ा जिसे गांव में हाथ से बनाया जा सकता है, जूता जिसे गांव में बनाया जा सकता है, जब तक वह नहीं पहनेंगे और मिल से और फैक्ट्रियों से बना हुआ हो पहनेंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरे साथी स्वामी आदित्यवे ा जी से मुझे आ ाा ही नहीं बल्कि वि वास भी है कि वे मेरे इस सुझाव का अपने इस प्रस्ताव में भाामिल कर लेंगे कि केवल ि ाक्षित बेरोजगारों को ही नहीं बल्कि अि ाक्षित बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाये। मेरे इस सं ाोधन को वे सहर्श स्वीकार करेंगे। वे अि ाक्षित लोग जो कि किसी न किसी वजह से अि ाक्षित रह जाते हैं, ि ाक्षा से वंचित रहे जाते हैं, उनको भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिये। उन बेचारों ने क्या पाप किया है ? उनको हमारे समाज ने ि ाक्षा के अधिकार सं

वंचित किया हुआ है। चेयरमैन साहब, गरीब मां का बच्चा अगर सुबह उठते ही मां के साथ घास काटने नहीं जायेगा तो वह भाम को चुल्हा नहीं जला सकते। चेयरमैन साहब, एक बच्चा अगर होटल पर बर्तन साफ करता है, अगर वह वहां पर जूठी प्लेटें साफ नहीं करेगा तो उसको रोटी कहां से मिलेगी ? उन हजारों लाखों बच्चों को, जिनको समाज ने पढ़ाई के अधिकार से वंचित कर रखा है, उन्होंने क्या पाप किया है कि उन्हें भी बेरोजगार भत्ता न दिया जाये। इसलिये मेरा कहना यह है कि उन ि ाक्षित बेरोजगारों के साथ ही अि ाक्षित बेरोजगारों को भी भत्ता दिया जाये। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह उनके साथ सरासर अन्याय है, सरासर ज्यादती है, सरासर जुल्म है। तो मेरा सुझाव यह है कि जो अपने माता पिता से अलग होकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जीविका उपार्जन करना चाहते हैं, उनको हमारे समाज की तरफ से या सरकार की तरफ से एक नि ि चत रा ि ा मिलनी चाहिए ताकि वे अपना गुजारा कर सकें चाहे वह रा ि ा 100 रुपया हो या 500 रुपया हौं, लेकिन इस बात को ध्यान में रख कर दी जानी चाहिये कि उनका गुजारा हो सके। यह नहीं होना चाहिये कि हम उन्हें 50 रुपये महीना देकर उनके साथ एक किस्म का मजाक करें। धन्यवाद।

श्री जगन नाथ (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति) : आदरणीय चेयरमैन साहब, जो यह बेरोजगारों को भत्ता देने की बात है मैं तो यह समझता हूं कि हाउस इसे कर ही नहीं सकता।

अगर यही व्यवस्था चलती है तो यह सम्भव नहीं है। जहां पर समाजवाद की बात आती है हरेक मंत्री हरेक एम0एल0ए0 भी कहता है, हम भी कहते हैं, वे भी कहते हैं कि हरेक की रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहियें रोटी, कपड़ा और मकान के सिद्धांत की बराबर बात होती रहती है। रोटी, कपड़ा और मकान सब को उस समय तक मिल नहीं सकता जब तक अमीर को खत्म नहीं किया जाता और गरीबा को ऊपर नहीं उठाया जाता। अमरी को जो आका ा से भी ऊपर है उसको हमें नीचे लाना होगा। दुनियां के बहुत से दे ाों के अन्दर यह स्थिति नहीं है। वहां पर अमीर और गरीब के अन्दर इतना अन्तर नहीं है जितना हिन्दुस्तान के अंदर है। राजस्थान और पंजाब की सरकार ने भत्ता देने की कोि ा ा की है लेकिन भाायद वह भी इसमें फेल हो जाये क्योंकि सालाना लोगों की संख्या जो बेरोजगार हैं, बढ़ती जा रही है और वे भी लगातार काफी देर तक उन्हें यह भत्ता नहीं दे सकती। यह सारे का सारा जो रोटी, कपड़ा और मकान का नारा है, यह इस पूंजीवादी ढांचे में सम्भव नहीं है। आपको पता है कि बेरोजगारी किन लौगों में है। उन लोगों में है जो लोग गरीब हैं। जितने भी अफसर यहां पर बैठे हुए हैं, इनको घरों में कोई भी बेकार नहीं है, जितने भी सरमायेदार होते हैं, उनके घरों में कोई भी बेकार आपको नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, बेकारी रहेगी और बेरोजगारी को कोई दूर नहीं कर सकता। धन्यवाद।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : चेयरमैन साहब, आज यहां पर बेरोजगारों को भत्ता देने के बारे में एक रैज्योलू ान डिस्कस हो रहा है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उन्हें यह भत्ता नहीं मिलना चाहिये। चेयरमैन साहब, मामला बहुत गम्भीर है। इसके बारे में मैं एक दो तोड़ की बात करना चाहता हूं। हमारी जो सरकार है यह सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। बेरोजगारी फैलाने के लिये यह सरकार बहुत ज्यादा जिम्मेवार है। चेयरमैन साहब, एक पोस्ट के लिए हजारों आदमियों को बुला लिया जाता है इसलिये चेयरमैन साहब, मेरा सुझाव यह है कि जो हजारों लड़के इन्टरव्यू के लिये यूं ही बुलाये जाते हैं, उनको या तो बुलाना नहीं चाहिये और अगर बुलाया जाये तो उनको आने जाने का किराया मिलना चाहिये। अभी पिछले दिनों बैंकों में इन्टनव्यू हुई। 10–12 हजार एप्लीकैंटस थे। कुरुक्षेत्र बैंक की बाबत मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी। न मेरी बात मानी और न स्वामी जी की ही मानी। 40 आदमी अपने ही भर लिये। यातो यों कर लिया जाये कि 90 कांस्टच्यूंसीज के हिसाब से हरेक एम0एल0ए0 को बांट दिया जायें जितने भी एम0एल0ए0 हैं, उनको अपने अपने आदमली लगवाने दिये जाएं या फिर किसी एक के सारे आदमी न लेकर मैरिट पर लिये जायें।

चौधरी ई वर सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहब, पोहलू साहब की बात आप सब समझ सकते हो।

यह एक आठवीं पास लड़के को बैंक में क्लर्क रखवाना चाहते थे . .....

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : आठवीं नहीं दसवीं पास है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे एम0एल0ए0 और मिनिस्टर एक बार रि ाया जरूर हो आयें ताकि इन को पता लग जोय कि वहां पर रोटी, कपड़ा और मकान हरेक व्यक्ति को कैसे मिलता है। वहां पर किसी को भी इन तीन चीजों से महरूम नहीं रखा जा सकता। इसीलिये चेयरमैन साहब, मेरा सुझाव यह है कि गर सरकार वाकई बेरोजगारी को दूर करना चाहती है तो जैसे आपने किसान के ऊपर 18 एकड़ की जमीन की सीलिंग लगा दी है, उसी तरह से 18 एकड़ जमीलन की कीमत निका कर उतनी ही अरबन प्रौपर्टी पर सीलिंग लगा दी जाये। इस तरह से जो फालतू प्रौपर्टी निकले वह गरीबों में बांट दी जाये। इस तरह एक रोज में ही गरीबी दूर हो सकती है। जिस तरह से मुझे 1967 में एक बार वजीर बनने का मौका मिला था, उसी तरह फिर कभी मौका मिला और उस सरकार में मैं वजीर हुआ तो हम सबसे पहला यही काम करेंगे। चेयरमैन साहब, मैं इस रैज्योलू ान की पुरजोर ताईद करता हूं कि और सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि वह मेरे सुझाव पर गौर करेगी क्योंकि तभी यहां से बेरोजगारी दूर हो सकती है। दो सौ रुपया महीना मैट्रिकुलेट को, 300 रुपया बी0ए0 को और 400 रुपया एम0ए0 को दियाजाये क्योंकि इससे कम से गुजारा होना आजकल के जमाने में नामुमकिन सा है। चेयरमैन

साहब, हमारी इस सरकार में ब्रिगेडियर रण सिंह जी और चौधरी भजन लाल जी जैसे लायक वजीर बैठे हैं फिर भी बेरोजगारी दूर न हो, यह बड़े दु:ख की बात है। यह तो जैसे बकरियों में भोर आ मिला हो, वैसे हैं इनको अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिय। चेयरमैन साहब, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोम का जो काटा इस बार बांटा गया है, वह सारे का सारा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिटस को दिया गया है। कहीं देहात में यह कोटा नहीं दिया गया। मोम का कोटा, अगर आपने इंसाफ करना है, तो उन चौधरी साहब को दे दो। वे ठीक तरह से बांद देंगें।

चेयरमैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी भी महकमे में जो नौकरी दी जाए वह रैगुलर बेसिज पर दी जाए, ऐडहोक बेसिज पर न दी जाए। चेयरमैन साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इंसाफ देना चाहते हैं लेकिन वे मजबूर हैं, क्यौंकि उनको एम0एल0एज0 की वोट चाहिये। गवर्नमैंट स्टेबल होनी चाहिय। अगर चीफ मिनिस्टर साहब स्टेबल गवर्नमैंट चाहतें हैं तो हम नो एम0एल0एज0 उनको स्पोर्ट देंगे। मैं सुझाव दूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब का इलैक ान सीधा होना चाहिये और सरकार बनाने के लिये हर एम0एल0ए0 की वोट होनी चाहिए ताकि हर काम इंसाफ से हो सके। सरकार की तरफ से यह नारा लगाया जाता है कि खड्डी लगाओ। मैं कहना चाहता हूं कि खड्डी तो, जो जुलाहा है, वह लगाएगा। पढ़ा लिखा नौजवान खड्डी नहीं लगा सकता। मेरा कहना यह है कि जो भी पढ़ा लिखा नौजवान

बेरोजगार है, उसको नौकरी दी जानी चाहिये। मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जाट कालिज के लड़कों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया था उसका वापिस लियिा जाना चाहिये ताकि वे अपनी पढ़ाई को चालू रख सकें। चेयरमैन साहब, वैसे मैं इस रैज्योलू ान की ताईद करता हूं।

सहकारिता तथा दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): माननीय सभापति जी, स्वामी आदित्यवे ा जी ने जो प्रस्ताव रखा है यह बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है। सभापति जी, आप जानते हैं कि हरियाणा स्टेट में इस समय 1 लाख 46 हजार 2065 पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान ऐसे हैं जिनके नाम ऐम्पलाएमैंट ऐक्सचेंज में दर्ज है। अगर इन सबको चालीस रुपया महीना भी दिया जाए तो सात करोड़ रुपया सरकार को हर साल देना पड़ेगा और चालीस रुपया देने के बावजूद भी न तो उनका गुजारा होगा और न ही बेरोजगारी दूर होगी बल्कि ज्यादा बेकारी बढ़ेगी और सरकार पर सात करोड़ रुपये का ज्यादा बोझ भी पड़ेगा। सभापति जी, ऐसा करने से यह भी होगा कि जो पढ़े लिखे नौजवान किसी प्राईवेट कम्पनी मैं काम करते हें या कोई लड़का अपने बाप के साथ दुकान करता है या भाई के साथ काम करता है, वे लोग भी चालीस रुपऐ लेने के लिये अपना नाम ऐम्पलाएमैंट ऐक्सचेंज में लिखवा देंगे। इस प्रकार से सरकार पर सात करोड़ से भी ज्यादा

बोझा पड़ेगा। जनता पार्टी ने जनता के सामने वचन दिया था कि हम सब लोगों को रोजगार देंगे .....

श्री बलदेव तायलः सभापति जी, अभी मंत्री महोदय ने फरमाया है कि जो लड़के प्राइवेट कम्पनियों में काम करते हैं या दुकान पर बैठते हैं वे चालीस रुपए लेने के लिये अपना नाम दर्ज करा देंगे। सभापति जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा का नौजवान कोई बेइमान नहीं है। उनके बारे में कोई भी मंत्री या मुख्य मंत्री इस प्रकार की बात नहीं कह सकता कि इस फायदे को लेने के लिये वे अपना नाम दर्ज करा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने हरियाणा के नौजवानों के बारे में जो संदेह प्रकट किया है वह उसको वापिस लें।

चौधरी भजन लालः सभापति जी, मैंने नौजवानों के प्रति बेईमान भाब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैंने यह नहीं कहा कि वे बेईमान हैं। मैंने यह कहा था कि कोई नौजवान किसी प्राईवेट संस्था में काम करता है, अपने बाप या भाई के साथ दुकान पर बैठता हैं वह चालीस रुपए लेने के लिये अपना नाम ऐम्पलाएमैंट ऐक्सचेंज में दर्ज करा सकता है। मैंने बिल्कुल भी बेईमान का भाब्द इस्तेमाल नहीं किया। मेरा आ ाय तो सिर्फ यही था कि ऐसे नौजवान अपना नाम लिखा सकते हैं और इस प्रकार से भत्ता लेने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। इसलिये हमारी सरकार ने फैसला किया है कि पढ़े लिखे बेरोजगार जिनके नाम ऐम्पलाएमैंट ऐक्सचेंज में दर्ज हैं। उनको काम दिया जाये और

इसके लिये हमारी सरकार ने एक नीति अपनाई है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धे लगाए जाएं और वे उद्योग धंधे, पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनके द्वारा लगाए जाने चाहिएं ताकि वे अपने पांव पर खड़े हो सकें। सभापति जी, सभी पढ़ लिखे बेरोजगार नौजवानों को नौकरी की बात करना ठीक नहीं हैं सभी नौजवानों को तो दस साल में भी नौकरी नहीं दी जा सकती। हरियाणा प्रान्त एक छोटा सा प्रान्त है। इसमें एक लाख नौजवान हर साल पढ़ लिख कर तैयार होते हैं और नौकरी बीस हजार भी नहीं निकलती। फर्ज किया कि बीस हजार को हम नौकरी दे भी दें तब भी 80 हजार नौजवान बाकी बच जाएंगे और इस प्रकार से हर साल बेरोजगार नौजवानों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। इसलिये हमने फैसला किया है कि जो पढ़ा लिखा नौजवान गांव में उद्योग धंध लगाएगा और उसमें जितना पैसा लगेगा, उसका 80 प्रति ात तो कमर्ि ायल बैंक कर्जा देगा जिसका रेट आफ इंट्रेस्ट बहुत थोड़ा सा यानी सात परसैंट होगा। दस परसैंट सरकार देगी और बाकी का दस परसैंट उसको अपने पास से लगाना पड़ेगा। सरकार जो कर्जा देगी, उस पर केवल चार परसैंट सूद लिया जाएगा सरकार पन्द्रह परसैंट सबसिडी भी देगी .....

श्री मांगेराम गुप्ताः सभापति जी, कहना यह है कि मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि गांव में जो पढ़ा लिखा नौजवान इंडस्ट्री लगाएगा, उसको सरकार मदद करेगीं मेरा कहना यह है कि उद्योग

वही कामयाब हो सकते हैं जिनको चलाने के लिये तजुर्बा हो। जब किसी काम को किसी नौजवान को नौलिज ही नहीं होगी तो वह कैसे काम करेगा ? इसलिये आप स्कूल में ही ऐसी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करें ताकि जब एक नौजवान पढ़ लिख कर बाहर आए तो वह इंडस्ट्री चला सके।

चौधरी भजन लालः चेयरमैन साहब, इंडस्ट्री डिपार्टमैंट ने इस काम के लिये एक लम्बा चौड़ा प्रोग्राम बनाया है। डिपार्टमैंट के आदमी सब जगह जाकर बताते हैं कि किस जगह पर किस प्रकार का उद्योग चलाया जा सकता है। कच्चा माल सप्लाई किया जाएगा और इंडस्ट्री जो भी माल तैयार करेगी उसके बेचने का इंतजाम उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। इंडस्ट्री डिपार्टमैंट उस तैयार किए हुए माल को खरीदेगा। बेरोजगार नौजवानों द्वारा जो भी उद्योग चलाया जाएगा उसमें सरकार द्वारा काफी सहूलियतें यानि बिजली आदि की सुविधा दी जाएगी। कंसे ानल रेट पर बिजली की सप्लाई की जाएगी। सभापति जी, हरियाणा पहला प्रान्त है जिसने इस किस्म का प्रोग्राम बनाया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम बेरोजगारी तब तक दूर नहीं कर सकेंगे जब तक ि ाक्षा पद्धति में तबदीली नहीं करते क्योंकि आज तो यह हो रहा है कि कोई भी नौजवान बी0ए0 या एम0ए0 पास करके कालिज से निकलता है तो वह नौकरी के पीछे भागता है। भारत सरकार इस बात के लिये चिन्तित है और भारत सरकार फैसला करने जा रही है कि ि ाक्षा पद्ध ति में तबदीली की जाए

ताकि स्कूल और कालिज में ऐसी ि ाक्षा दी जाए कि वहां से पढ़ कर निकलने के बाद वह नौजवान अपना काम कर के अपना गुजारा कर सकें। इसके लिये भारत सरकार पूरी तरह जागरूक है और सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकेगी वह सरकार करेगी। उद्योग धंधे लगाने के लिये हमारी सरकार बहुत कुछ करने जा रही है।

इसके अलावा चेयरमैन साहब, बहुत से सदस्यों ने कहा कि नौकरी में प्रवे ा करने लिए आयु 27 साल से बढ़ा दी जानी चाहिये और मैं समझता हूं कि इस बात में वजन है। चेयरमैन साहब, इसके बारे में सोचा जा रहा है कि 27 साल से आयु बढ़ाकर 30 साल कर दी जाए लेकिन अभी सरकार ने इस बारे में पूरा फैसला नहीं किया है, ऐसा करने का विचार कर रही है।

17.00 बजे।

सभापति महोदय, एक बात श्री पोहलू जी ने मोम के कोटे के बारे में यहां पर कही। मोम का कोटा पिछली सरकार ने बहुत ही थोड़े लोगों को दिया था। अब मैं समझता हूं कि 10 गुना ज्यादा मोम का कोटा देहातों और भाहरों में दिया गया है। (ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : चेयरमैन साहब, यह बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देहातों में एक गुना भी नहीं मिला है।

सरकार ने कोटा कागजों में मुकर्रर कर रखा है लेकिन दिया नहीं गया है।

चौधरी भजन लालः सभापति महोदय, दूसरी बात पोहलू साहब ने कुरुक्षेत्र को ओप्रटिव बैंक के बारे मैं कही कि वहां पर बड़ा घपला हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके चेयरमैन साहब श्री ई वर सिंह हैं, उन्होंने लड़की की सिलैक ान की थी। जहां तक मैं समझता हूं, यह सिलैक ान ठीक हुई है, लेकिन हो सकता है कि पोहलू साहब किसी को लगवाना चाहते हों, और वह न लग सका हो, इसीलिये वे कह रहे हौं (ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : चेयरमैन साहब, मेरा लड़का मैट्रिक पास है और वहां पर थर्ड डिविजन वाले लगाये गये हैं। फिर वजीर साहब ने खुद माना है कि कुछ घपला हुआ है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवाई जाये ताकि पता लग जाए कि * * * * *

* * * * *

चौधरी भजन लालः आदरणीय सभापति महोदय, आनरेबल मैम्बर ने जो भाब्द अभी यहां पर कहे हैं, वे उचित नहीं हैं, इनको एक्सपंज किया जाए। (ाोर)

श्री लहरी सिंह मेराहः अभी पोहलू साहब ने एम0एल0ए0 के बारे में काफी कुछ कहा है पर उन्होंने जो अपना लड़का लगवाना था, उस बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री बलदेव तायलः आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय पोहलू साहब से प्रार्थना करूंगा कि मेरे विचार से तो किसी एम0एल0ए0 साहिबान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वे सारे * * * * * * * * * या तो पोहलू साहब इस बात का कोई साफ प्रमाण प्रस्तुत करें या फिर ये अपने रिमार्कस वापिस लें, यही उचित होगा। (ाोर) मैं अपने आनरेबल मैम्बर से कहूंगा कि उन्होंने जो भाब्द यहां पर कहे हैं वह भाब्द किसी भी आदरणी मैम्बर के लिये प्रयोग करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। अगर पोहलू साहब यह समझते हैं कि यह उनके लिये उचित है तो मैं आपके द्वारा आदरणीय सभापति महोदय, उनसे कहूंगा कि या तो वह इस का प्रामण प्रस्तुत करें या अपने या रिमार्कस वापिस लें और साथ ही सदन से यह कहें कि उनको क्षमा किया जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : चेयरमैन साहब, मैंने तो कहा कि चेयरमैन साहब, की इन्कवायरी करवाई जाए, इंक्वायरी से सब कुछ पता चल जाएगा। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री बलदेव तायलः आदरणीय चेयरमैन साहब, किसी आनरेबल मैम्बर के लिये अपने कहे हुए भाब्द बदलना उचित नहीं है। रिकार्ड उठाकर देखा जा सकता है। उन्होंने यह कहा था कि * * * * * इन्होंने यह कहकर गरीब एम0एल0एज0 को अपमानित किया है। इसका मतलब यह है कि किसी गरीब व्यक्ति को एम0एल0ए0 बनने का अधिकार नहीं है। अगर इत्तफाक

से किसी गरीब आदमी को जनता ने एम0एल0ए0 बना कर भेज दिया है तो उनके ऊपर ऐसे लांछन लगाना उचित नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय सदस्य से यह कहा जाए कि वह अपने दिए हुए रिमार्कस वापिस लें।

श्री सभापतिः यह जो रिमार्कस यहां पर आनरेबल मैम्बर की तरफ से दिये गये हैं, उनको एक्सपंज किया जाए। (ाोर)

श्री बलदेव तायलः आदरणीय सभापति महोदय, इस सदन की गरिमा बड़ी महत्त्वपूर्ण है। इस सदन की गरिमा इस सदन का आदर है, इस सदन के आदरणीय सदस्यों का आदर है, इस बारे में कोई बुरा भला सोचने की आव यकता नहीं है। हो सकता है कि किसी आनरेबल मैम्बर से जो ा में आकर जाने या अनजाने में कुछ अनुचित भाब्द जबान से निकल जाएं मैं फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि आनरेबल मैम्बर अपने कहे हुए रिमार्कस वापिस ले लें।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः आदरणीय सभापति महोदय, पिछले सै ान में भी एक वजीर के खिलाफ एक सपैसिफिक एलीगे ान लगाये गये थे।(ाोर)

श्री बलदेव तायलः आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य गरीब हैं उनको अपमानित करने

का किसी को अधिकार नहीं है। वे भी उतने आदरणी सदस्य हैं जितना कि कोई धनाढय। (ाोर)

श्री भाम ोर सिंहः चेयरमैन साहब, जब कोई भाब्द एक्सपंज हो जाते हैं तो उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं रहती जिसके बारे में कोई बात उठायी जाये। ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि माननीय सदस्य किस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं। विदड्रावल तब होती है जब एक्सपंज न हों। अब तो वर्ड एक्सपंज हो गये फिर विदड्रावल का कोई सवाल ही नहीं उठता।

चौधरी भजन लालः सभापति महोदय, वे वर्ड एक्सपंज हो गये, इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। पर हाउस में कोई माननीय सदस्य गाली निकाल दे और आप उसको एक्सपंज कर दें तो यह ठीक नहीं है। यह तो गाली से भी बुरी बात है, इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वे खड़े होकर अपने भाब्द वापिस लें।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): चेयरमैन साहब, पोहलू साहब का बड़प्पन तो इसी में है कि वे अपने भाब्द वापिस ले लें।

चौधरी भजन लालः सभापति महोदय, हमारी सरकार की ऐसी स्कीमें हैं जिसके अन्तर्गत छठी पंचवर्शीय योजना के अन्त तक हम 5 लाख 12 हजार पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देंगे। मैं

समझता हूं कि 1983 के अंत तक कोई भी पढ़ा लिखा बेरोजगार स्टेट में नहीं रहेगा।

स्वामी आदित्यवे ा: मैं मन्त्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि आज जो आदमी भूखे मर रहे हैं और निरा ा हुए बैठे हैं। उनके लिये इमिजिएट क्या किया जा रहा है ? दूसरी तरफ कारखाने लगाने के लिये सरकार पैसा दे रही है लेकिन लगाने के लिये कोई तैयार नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि रोजगार देने के लिये जितने साधन चाहिए जैसे ट्रेनिंग है, टैक्नीकल ना हाउ है, इन सारी बातों की व्यवस्था नहीं है। सदन में तो हम सारी बातें कर लेते हैं कि यह हो जाएगा वह हो जाएगा लेकिन जिसके पेट में दाने नहीं पड़ते उसकी हालत देखो। मेरे पास बहुत आदमी आते हैं और कहते हैं कि हम बहुत दु:खी हैं। हम आत्म हत्या कर लेंगे। ये सी बातें उभर कर आ रही हैं और इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि बेरोजगारों के लिये हम सात करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। इस साल का बजट लगभग 8 अरब रुपये का आयेगा तो हसमें से सात करोड़ रुपये इस काम के लिये कोई मायने नहीं रखते। आप पंजाब और बिहार की तरफ देखें। बिहार में तो हाई स्कूल तक ि ाक्षा नि: ाुल्क कर दी गई है लेकिन हमारी स्टेट में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हरियाणा सरकार भी इस बारे में अ योंरेंअ दे कि वह भी कुछ करेगी।

चौधरी भजन लालः सभापति महोदय जी, मैं आपके द्वारा स्वामी जी से यह प्रार्थना करूंगा कि हमने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं और वे सारी बातें हाउस में आ जाएंगी इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि वे मेहरबानी करके अपना प्रस्ताव वापिस ले लें। सिर्फ 40 रुपये देने से ही उनका काम नहीं चलेगा। जब तक हम उनको अपने पैरों पर खड़े नहीं करेंगे तब तक उनका काम नहीं चलेगा। इसलिये मैं एक बार फिर उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

स्वामी आदित्यवे ाः प्रस्ताव तो विदड्रा करता हूं लेकिन सवाल यह है कि जो लोगों के साथ हमने वायदे किय थे उनको कब पूरा किया जाएगा ? अब जो सात करोड़ रुपये दिये जाएंगे ये बहुत कम हैं। हम तो चाहते हैं कि इमीजिएटली कोई कदम उठाए जाएं। (ाोर)

Mr. Chiarman: Has the Hon. Member, the leave of the House to withdraw his resolution ?

(Voices : yes)

The resolution was, by leave of the House, withdrawn.

(3) पंजाब तथा हरियाणा के मध्य रावी–ब्यास के अतिरेक पानी के विभाजन तथा पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक नहर के भाग को कम से कम समय में निर्मित करने सम्बन्धी।

श्री भाम ोर सिंहः सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

"इस सदन का यह दृढ़ वि वास है कि भारत सरकार द्वारा पंजाब तथा हरियाणा के मध्य रावी ब्यास के अतिरेक पानी का विभाजन न्यायपूर्ण, न्यायोचित तथा अन्तिम है तथा इस पर बातचीज नहीं हो सकती।

इसलिये यह सदन राज्य सरकार से सिफारि ा करता है कि वह भारत सरकार से निवेदन करें कि वह पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक नहर के भाग को कम से कम समय में निर्मित पूर्ण करवाए।"

Mr. Chairman: Motion moved-

This House is of the4 firm view that the apportionment of surplus Ravi Beas water between Punjab and Haryana by the Government of India was just, equitable, is final and not negotiable.

The House thus recommends to the State Government to approach the Government of India to get portion of Sutlej Yamuna Link Canal in the territory of Punjab constructed/completed within the shorest time.

श्री भाम ोर सिंह(नरवाना): चेयरमैन साहब, सतलुज यमुना लिंक कैनाल के बारे में मेरे प्रस्ताव के दो भाग हैं। पहले भाग में यह बात कही गई है कि सतलुज यमुना लिंग नहर के

पानी को जो बंटवारा पंजाब और हरियाणा के बीच था वह न्यायोचित है, वह फाइनल है और उसके बारे में हरियाणा सरकार को पंजाब सरकार और भारत सरकार के दबाव में आकर कोई बातचीत रिओपन नहीं करनी चाहिए। दूसरे भाग में यह बात कही गई है कि हरियाणा सरकार भारत सरकार से इस बात का आग्रह करे कि वह पंजाब सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डाले कि पंजाब के हिस्से में इस नहर का जो भाग बनना है, उसकी खुदवाई भीघ्र करवाई जाए। सभापति महोदय, 1960 में ईंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत सरकार और पाकिस्तान के दरिम्यान जो ट्रीटी हुई उसके तहत भारत को सतलुज, रावी और व्यास का जो पानी था उसका 15.85 एम0ए0एफ0 हिस्सा मिला। इस ट्रीटी के बाद भारत सरकार ने पंजाब, राजस्थान, जे0 एण्ड के0 और पैप्सू के बीच इस पानी का बंटवारा इस प्रकार किया था–

राजस्थान	8 एम0ए0एफ0
पंजाब	5.9 एम0ए0एफ0
पैप्सू	1.13 एम0ए0एफ0
जे0 एण्ड के0	0.65 एम0ए0एफ0

1966 में पैप्सू का पंजाब में विलय होने के बाद जो प्वांयट पंजाब था उसके हिस्से में 7.2 एम0ए0एफ0 पानी आया। ज्वायंट पंजाब में उस वक्त की जो सरकार थी उसने एक फूड कमेटी मुकर्रर की थी। उस कमेटी का काम यह देखना था कि समूचे पंजाब की सारी जमीन पर सिंचाई के साधन जुटा कर ज्यादा से ज्यादा पैदावार किस तरह से की जाए। कमेटी की रिपोर्ट में हरियाणा के इलाके को 4.56 एम0ए0एफ0 पानी देने की सिफारि ा की गई थी। इसके साथ ही आपको पता है कि हरियाणा का जो बैकवर्ड इलाका था उसकी तरक्की के लिये हरियाणा डिवेल्पमैंट कमेटी के नाम से एक कमेटी मुकर्रर की गई थी। सभापति महोदय, उस कमेटी की सर्वसम्मति से यह राय थी कि जो पानी ट्रीटी के तहत भारत सरकार को मिला है उसका अधिकतर हिस्सा हरियाणा के भाग को दिया जाए। सभापति महोदय, इसके बाद 22—3—66 को पंजाब विधान सभा में पंजाब के मुख्य मंत्री ने अपने ब्यान में यह बात कही थी कि हरियाणा के रीजन का वाटर अलाउंस बढ़ा कर फिरोजपुर और लुधियाना के जिलों के वाटर अलांउ के बराबर ले जाएंगे।

चेयरमैन साहब, इसी विधान सभा सत्र में गवर्नर साहब का जो अभिभाशण पे ा हुआ था, उसमें इस बात का वि वास दिलाया गया था कि हरियाणा के इलाके को इस पानी का अधिकतर भाग मिलेगा और हरियाणा डिवेल्पमैंट कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। इसके बाद चेयरमैन

साहब, हरियाणा बनने के बाद हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को 4.1 एम0ए0एफ0 वाटर जिसको ट्रीटी वाटर कहते हैं। हरियाणा को देने की मांग की थी। पंजाब सरकार के विचार करने पर इस मामले को पंजाब रीओरगेनाईजे ान एक्ट के तहत हरियाणा की सरकार ने फैसले के लिये भारत सरकार को रैफर किया था। इसके प चात भारत सरकार ने यू0पी0 के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री मित्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी मुकर्रर की थी और इस कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने के लिये कैबिनेट के सामने रखा। उस समय श्री के0 एल0 राव और डी0पी0 धर कैबिनेट के मंत्री थे। इन दोनों को इस बात का फैसला करने की जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों से मिलकर इस पानी का फैसला करवायें। चेयरमैन साहब, इसी दौरान में प्लानिंग कमी ान ने एक पत्र पंजाब, हरियाणा और भारत सरकार के जो दूसरे पदाधिकारी हैं, इन के बीच सरकुलेट किया। इस प्लानिंग कमी ान के पत्र में यह बात मानी गई थी कि ट्रीटी वाटर में से हरियाणा का 3.74 एम0ए0एफ0 पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। इन सारी वारदातों के प चात सैंट्रल वाटर एंड पावर कमी ान के चेयरमैन श्री मूर्ति थे उनको इस मामले पर रिपोर्ट करने के लिये कहा गया था। इनकी रिपोर्ट के जो सैलियंट फीचर्ज थे, महत्वपूर्ण बाते थी। उन में से मैं दो तीन का जिक्र करूंगा। वे इस प्रकार थीः उन्होंने यह बात कही थी कि रावी ब्यास के पानी का इस्तेमाल, इन्टेग्रेटिड तौर पर तीनों सूबे उस भूमि के लिय इस्तेमाल करेंगे जो सूखी भूमि है, जिसको पानी नहीं

लगता वहां इसका प्रयोग किया जाना है। दूसरी बात यह कही थी कि हरियाणा के बहुत बड़े भाग को बहुत लम्बे अर्से तक आबपा ाी से वंचित रखा गया है, इसलिये हरियाणा का इस बात पर अधिकार है कि अधिक पानी हरियाणा को मिले। चेयरमैन साहब, पंजाब में इंटैसिटी आफ इरीगे ान 73 परसैंट थी जबकि इसके मुकाबजे में हरियाणा में सिर्फ 38 परसैंट थी। चेयरमैन साहब, 1–11–1966 को, जब पंजाब का बंटवारा हुआ था। उस वक्त जो आंकड़े छपे थे, उसके मुताबिक 28.46 लाख एकड़ भूमि टयूबवैल्ज के जरिए सैराब होती थी जबकि इसके मुकाबले में हरियाणा में केवल 7.43 लाख एकड़ भूमि सैराब होती थी। इसी तरह 1965–66 में पंजाब में कुल का त का रकबा 106 लाख एकड़ था। 106 लाख एकड़ मेंसे ग्रौस इरीगेटिड एरिया 70.40 लाख एकड़ था जबकि हरियाणा में कुल का त का रकबा 98.70 लाख एकड़ था और ग्रौस इरिगेटिड एरिया केवल 36.70 लाख एकड़ था। इन आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार ने 1976 में इस बात का फैसला कि था कि ट्रीटी वाटर पंजाब और हरियाणा दोनों प्रान्तों के बीच में बराबर बराबर बांट दिए। पंजाब प्रान्त के भाई बार बार प्रचार मात्र के लिये कहते हैं कि चूंकि हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री उस वक्त भारत सरकार में डिफैंस मिनिस्टर थे, इसलिये उन्होंने प्रधान मंत्री के ऊपर दबाव डालकर हरियाणा के हक में यह फैसला करवाया। इस फैसले का एमरजैंसी से कोई ताल्लुक नहीं था। चेयरमैन साहब, मैंने यह फिगर्ज और तारीखें की ब्रीफ हिस्ट्री इसलिए कोट की है कि ये आंकड़े इस बात का

गवाह है। इस बात का सबूत हैं कि वे भाई केवल मात्र झूठ बोलते हैं इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि हरियाणा को किसी प्रकार से उसके हिस्से से ज्यादा हिस्सा मिला हो बल्कि सच्चाई यह है कि जितनी कमेटियां ज्वायंअ पंजाब में बनीं या गवर्नमैंट आफ इंडिया ने बनाई, उन सारी कमेटियों द्वारा जितना पानी 1976 में हरियाणा को मिला, उससे अधिक पानी देने का हरियाणा का विचार सब कमेटियों ने माना था। इसलिये पानी के बंटवारे को री–ओपन करने की बात का कतई कोई सवाल पैदा नहीं होता है। हमारी सरकार को कतई तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे यह बात कहने में संकोच नहीं है कि हमारी सरकार ने और सिंचाई तथा बिजली मंत्री महोदय ने बार बार जैसा कि हम अखबार में पढ़ते हैं, यह डटकर स्टैंड लिया है कि पानी का सवाल री–ओपन नहीं हो सकता।

चेयरमैन साहब, मेरे प्रस्ताव का जो दूसरा पो र्न है, वह यह है कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डाले या भारत सरकार पंजाब सरकार के खिलाफ कोई सैक् न लागू करे या कोई और उपाय करे ताकि यह नहर जल्दी से जल्दी खोदी जाए। चेयरमैन साहब, हरियाणा में जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1976 से अब तक करीब 25 करोड़ रुपया खर्च करके अपने हिस्से में नहर पूरी कर ली है। दो करोड़ के लगभग रुपया हमारी सरकार, पंजाब सरकार को दे चुकी है और उसमें से अधिकतर रुपया मैं समझता हूं, पंजाब सरकार ने बहुत बढ़िया

पौ ा दफतर चण्डीगढ़ में खोल कर, आफिसरों को तनखाह देकर खर्च कर दिया है। यह रुपया हमने उनको जमीन एक्वायर करने के लिये दिया था लेकिन उन्होंने वह रुपया दूसरे कामों पर खर्च कर दिया है। इसी प्रकार इस नहर के सिस्टम को बनाने पर, हरियाणा ने अपने इलाके में 100 करोड़ रुपए के लगभग खर्च किया है। इन सारी बातों के इलावा जब तक नहर का पानी हमारे इलाके में नहीं आता हर साल हरियाणा को फसलों के रूप में 100 करोड़ रुपये का घाटा बर्दा त करना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, मैं अपनी सरकार से यह बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार पिछले दो साले से पता नहीं इन्हें किस बात की भार्म है, झिझक है या क्या रिजर्वे ान है, कि इन्होंने हाउस को इस बारे में पूरी तरह से कान्फिडैंस में नहीं लिया है और न ही हरियाणा की भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों को ही कान्फिडैंस में लिया है। क्या दिक्कत है, क्या अड़चन है, कौन सा मसला है जिसके कारण पिछले दो साल से यह मसला लटका हुआ है ? पिछले दो साल से हरियाणा सरकार इस बात का दावा करती थी कि पंजाब के साथ उसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं और हरियाणा के हर आदमी को उम्मीद ीी कि उन ताल्लुकात का फायदा उठाकर हरियाणा का जो असली हक है, वह हरियाणा सारकार दिलवायेगी। लेकिर चेयरमैन साहब, आपने देखा है कि पिछले दो साल से पंजाब के इलाके में नहर की खुदाई के लिये एक कस्सी भी नहीं लगी। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि अगर किसी किस्म की कमजोरी हरियाणा सरकार महसूस करती है तो उसका फर्ज बनता है कि

मात्र हाउस के समस्त सदस्यगण, और जो भी राजनीतिक पार्टिया हैं उनो कान्फिडैंस में लेकर राउंड टेबल कान्फ्रैंस बुला कर फैसला किया जाए क्योंकि हरियाणा की हर राजनीतिक पार्टी हर व्यक्ति इस बात के लिये सरकार के साथ हैं। यह कोई पुलिटिकल झगड़ा नहीं है। चेयरमैन साहब, एक मिनट में यह बात कह कर खत्म करता हूं कि अगर भारत सरकार चाहे तो हरियाणा को उसका जायज हक दिलवा सकती है। अगर दिलाना चाहे तो उसके पास ऐसे तरीके मौजूद हैं ऐसी भाक्ति है जिसका प्रयोग करके इंसाफ कर सकती है। मैं उदाहरण के तौर पर कह सकता हूं कि पंजाब प्रान्त नित रोज भारत सरकार से कभी थर्मल प्लांट मांगने की बात रकता है, कभी सैंट्रल प्रोजैक्ट मांगने की बात करता है, कभी हैवी इंडस्ट्री लगवाने की मांग करता है। चेयरमैन साहब, आपको पता है कि सैंट्रल गवर्नमैंट हर साल हर प्रान्त को करोड़ों रुपये ग्रांट की भाक्ल में और दूसरी भाक्ल में देती है क्योंकिह पंजाब हिन्दुस्तान का हिस्सा है, पंजाब के लोग हमार भाई हैं। चाहे प्रधान मंत्री हो चाहे दूसरे लोग हों, उनके लिये किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वह पंजाबे के ऊपर इस बात का दबाव न डाल सकें कि जो हिस्सा उसे मिलता है वहीं हिस्सा हरियाणा को मिले। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से यह आ ाा करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी मैंने सारी स्टेट के इंट्रैस्ट को सामने रखते हुए यह प्रस्ताव रखा है और आ ाा है कि हाउस इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करेगा।

इससे हमारी सरकार के हाथ मजबूत होंगे और हमारी सरकार को फायदा होगा।

राव राम नारायण (साहलावास): चेयरमैन साहब, इस मसले पर मैंने काल अटैन ान मो ान भी पहले दी थी और इस सै ान में भी दी है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने एक लम्बी चौड़ी स्टेटमैंट पढ़ी थी और उसके आगे कुछ प्रोग्रैस हुई या नहीं, उसका मुझे कुछ पता नहीं है। चौधरी भाम ोर सिंह जी ने इस पानी के बंटवारे की एक बहुत अच्छी वि ाल हिस्ट्री दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि जब से यह बंटवारा हो रहा है तब से हमको कुछ न कुछ ज्यादा पानी मिलने की सिफारि ा होती रही है और अब यह आहिस्त–2 घटते घटते 3.5 मिलियन एकड़ फीट तक रह गया। वह भी अब खत्म हो गया। 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी की उम्मी से हमने जवाहर लाल नेहरू कैनाल तैयार कर ली है जिसमें 10 करोड़ रुपये से भी ठयाजदा खर्च हो चुका है। यह नगहर पानी के बिना क्षु क पड़ी है। यह उस एरिया के लिये बनाई गई है जहां पीने का पानी नहीं मिलता है। जैसे झज्जर का एरिया है, लोहारू का एरिया है, महेन्द्रगढ़ का एरिया है और दादरी का एरिया है। इन खु क इलाकों को इए नहर से पानी जाना है। इन इलाकों में पीने के पानी की भी समस्या है। अगर यह नहर जाएगी तो पीने के पानी के लिये वाटर सप्लाई स्कीम के तहत टैक्स बनसकेंगे। सर्दियों से खु क इालके जहां हमे ाा कहत रहता है वहां आबपा ाी के लिये पानी मिल सकेगा।

इसलिये मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह मजबूती के साथ गवर्नमैंट आफ इंडिया के थ्रू पंजाब पर यह प्रै ार डलवाए कि हमारे हिस्से का पानी जल्दी से जल्दी हमें दिया जाये और पंजाब में जो लिंक कैनाल बनाने में देरी हो रही है उसको जल्दी से जल्दी तैयार करवाया जाए।

चौधरी रिजक राम (राई): चेयरमैन साहब, जो प्रस्ताव आज सदन के सामने चौधरी भाम ेर सिह ने रखा है, उस पर पिछले सै ान में भी अडजर्नमैंट मो ान के द्वारा काफी चर्चा हुई थी। उससे पहले भी जितनी बार यह सवाल सदन के सामने आया, उस पर मुंख्यमंत्री जी ने और हमारे सिंचाई और बिजली मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने भी बार बार आ वासन दिया था कि हरियाणा पानी का पूरा हिस्सा लेकर रहेगा। कितने ही माननीय सदस्यों ने इस समस्या पर विचार प्रकट करते हुए यह जाहिर किया है कि किसी ढंग से हरियाणा सरकार इस समस्या को हल करे, अपने हक को हासिल करने के लिये कोि ा ा करे और उसमें कामयाबी हासिल करे। सरकारी की तरफ से भी बहुत ही जोरदार भाब्दों में यह कहा गया था कि हरियाणा को उाकसा हिस्सा अव य मिलेगा। चेयरमैन साहब, आपको याद होगा, चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने भाुरू में सारे हाउस को यह यकीन दिलाया था कि चाहे हरियाणा में सतलुज यमुना लिंग का सवाल है चाहे रावी ब्यास के पानी का सवाल है, इन का पफैसला करने के लिये जो भी बोर्ड बनेगा उसमें हरियाण के नुमाइंदे भी होंगे। बोर्ड में हमारे

नुमाइंदे लाजमी तौर परह होंगे और पंजाब हमारे हिस्से को खत्म नहीं कर सकता है। अभी चोधरी भाम ेर सिंह जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब सरकारों के दोनों मुख्यमंत्रियों के आपस में बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। इसलिये भाायद यह मामला हल हो जाये लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह सारी समस्या जो उलझती जा रही है, यचह दोनों मुख्यमंत्रियों के प्यार की नि ाानी है। उनका आपस का जो प्यार है उसी के कारण यह सब कुछ उलझन में पड़ा हुआ है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बड़े हौसले के साथ सदन में बयान दिया, अखबारों में भी बयान दिया और एक बार तो इन्होंने एलान भी किया था कि पंजाब में नहर खोदने के लिए तारीख मुकर्रर हो गई है और फलां तारीख को उसका उदघाटन हमारे मुख्यमंत्री जी पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा ने इस काम के लिये पंजाब को जो पैसा दे रखा है, उसको देखते हुए हरियाणा की जनता में बहुत रोश प्रकट हो रहा है। सरकारने इस बारे में लोगों से बड़े बड़े वायदे किए थे और लोगों को बड़ा वि वास दिलाया था कि पानी देंगे लेकिन सरकार अब तक नाकामयाब रही। लोगों का वि वास सरकार से उठ चुका है। यहां पर जो बातें कही जाती हैं वह सिरे नहीं चढ़ रही हैं। यही कारण है कि सदन में दिये यगे आ वासनों का जनता पर कोई असर नहीं हो रहा है।

अब भी बात वहीं अटकी हुई है। अब मामला अटोरनी जनरल के पास पहुंच गया है, वह एग्जामिन करेगा और देखेगा कि हरियाणा का क्लेम जायज है या नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो फैसला हो चुका था, वह कोई फैसला नहीं था, अब सरकारी वकील जो फैसला देगा, उसके ऊपर बात चलेगी, उसको भी अगर पंजाब सरकार माने या न माने, यह उनकी मर्जी पर है क्योंकि इस तरह की बात भी उन्होनें कही है। सब माननीय सदस्यों को याद होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी अमृतसर जिले में एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिये गए थे। वहां रावी–व्यास लिंक के बारे में चर्चा हुई थी। उनकी एक ही बात थी वे कहते थे कि यह झगड़ा हम आपस में खुद सुलझा लेंगे, प्यार से सुलझा लेंगे। दिल्ली सरकार की सारी ताकत लगाने पर भी पंजाब वाले मानते ही नहीं, यह इनके प्यार की कहानी है, क्या ये हरियाणा के हकूक को हासिल करेंगे ? इनको यह बात नहीं कहनी चाहिये कि ये हरियाणा के हकूक की रक्षा करेंगे। एक बात और स्पश्ट करना चाहता हूं, चेयरमैन साहब, पिछले दिनों इस सरकार के पैर डगमगा गये थे। इस सरवकार को बचाने के लिये पंजाब के जितने अकाली मैम्बर थे, वे इस कोि ा ा में रहे कि किसी तरह से यह सरकार टिकी रहे। यह सरकार अगर टिकी हुई है तो पंजाब के अकाली दल के नेताओं की सहायता से टिकी है जिनकी वजह से ये आज यहां बैठे हैं। चौधरी भाम ोर सिंह जी सोचते हैं कि यह सरकार हरियाणा के हितों की हिफाजित करेगी। चौधरी भाम ोर सिंह जी यह बात गलत है, हरियाणा के हितों की रक्षा यह सरकार

कर नहीं सकती। (व्यवधान) मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीयत है कि यह फैसला उसी तरह कायम रहे जो श्री वीरेन्द्र सिंह जी इस सदन में बयान देते रहे, अगर इसको पूरा करना चाहते हैं तो साफ है कि इसके लिये एक डैड लाईन रखी जाए। समय निि चत कर दें कि इतने अर्से के अंदर इसका फैसला करवायेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सारे मैम्बर उन के साथ हैं और यहां इजलास में बैठकर फैसला करें, चाहे जेलों में जाएं चाहे लोगों को पूछें लेकिन पंजाब के साथ वह व्यवहार करें जो होना चाहिये क्योंकि पंजाब सरकार मीठी मीठी बातों से मानने वाली नहीं है। हरियाणा से उनको कदम कदम पर काम पड़ते हैं, उनके ट्रक, बसें सारा कोराबार उनका हरियाणा के इलाके से होकर चलात है, इसको बंद करो।। मिन्नत से, दोस्ती से कुछ नहीं हो सकता। इसलिये चौधरी भाम ेर सिंह जी, मैं यह समझता हूं कि आप यह रैजोल्यू ान बार बार लोकर खामखाह तकलीफ न उठाते रहें, इनमें हरियाणा के हकूकों की रक्षा करने का दम नहीं है, हरियाणा के लिये पानी हासिल नहीं कर सकते, इनकी दोस्ती रहे और हरियाणा तबाह हो जाए, इस बात की परवाह इनको नहीं है। इसलियें हम इसका क्या समर्थन करें, क्या न करें, यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह(तो ाम): चौधरी भाम ेर सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन विधान सभा के तमाम सदस्य दिल से करते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि इस प्रस्ताव को अमली जामा

कैसे पहनाया जाए। यह तभी हो सकता है अगर हरियाणा सरकार चट्टान की तरह अड़ कर के केस लड़े। चौधरी वीरेन्द्र सिंह और जनता विधायक दल के नेता इस बात को भूल चूके हैं और पंजाब सरकार का इरादा, इस पानी के लिये कैरियर चैनल बनाने के प्रति ठीक नहीं है, यह काम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकेता, क्योंकि अकाली पार्टी ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफैस्टों में यह जिक्र किया है कि अगर पंजाब प्रान्त में अकाली गवर्नमैंट बन गई तो हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी नहीं दिया जाएगा। यह बात उनके मैनिफैस्टो में है। उन्होनें केस को री ओपन करवाया और मोरार जी भाई, प्राईम मिनिस्टर पर दबाव डलवाया। उस मीटिंग में श्री बरनाला जी है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और ये इस बात में हिस्सा लेते हैं कि आया यह पानी हरियाणा को ठीक दिया गया था या गलत दिया गया था। सभापति जी, आप अन्दाजा लगाएं कि जो मिनिस्टर पंजाब के मैनिफैस्टों पर चुनाव लड़ कर आए, वह हरियाणा को पानी नहीं दे सकता, वह हरियाणा के भले की बात कैसे सोच सकता है ? इस नहर के बनने से पहले हरियाणा में 150 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, आई एम सब्जैक्ट टू कुरैक ान, मैं गलत नहीं कह रहा, मिनिस्टर साहब बैठे हैं। जैसा राव साहब ने बताया कि 100 करोड़ रुपया जवाहर लाल नेहरू कैनाल पर खर्च हो चुका है। लगभग 150 करोड़ रुपया लिफ्ट इरीगे ान स्कीमों पर या पानी का इंतजाम करने के लिये अन्य तरीकों पर खर्च हो चुके हैं। ताकि जिस वक्त यह कैरियर चैनल बन कर पूरी हो। 3.5 मिलियन फीट एकड़ पानी जब

हरियाणा में आये तो हम इस पानी को कंज्यूम कर सकें। इस के लिये ग्राउंड वर्क तेयार किया गया। सभापति महोदय, 100 करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हर साल होता है, जब तक पानी नहीं मिलेगा, यह होता ही रहेगा। जिस वक्त हरियाणा और पंजाब का 1976 में बेसिक एग्रीमैंट हुआ था, उस वक्त कैरियर कैनाल पर होने वाले पैसे का एस्टीमैट 72 करोड़ रुपये का बना था, लेकिन राज्यपाल महोदन ने अपने अभिभाशण में जिक्र किया है कि कास्ट आफ कंस्ट्रक ान इतनी बढ़ चुकी है जिसके परिणामस्वरूप 138 करोड़ रुपया बाढ़ की रोकथाम के लिये और कैरियर चैनल बनाने के लिये खर्च होगा। आगे चल कर 138 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च हो सकता है। सभापति महोदय, डिले होती जा रही है, कैरियर चैनल बनने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और हरियाणा प्रान्त को और सरकार को वह रूप धारण करना पड़ेगा जिससे हम पंजाब सरकार को कैरियर चैनल बनाने पर मजबूर कर सकें। यह हम टाईम बाउंड प्रोग्राम बना कर तय कर लें तकि क्या क्या कदम उठाने चाहियें। हमें पंजाब वालों को बताना पड़ेगा कि जमीन एक्वायर करके अगर कैरियर चैनल नहीं बनाई गई तो हमारा यह एटीच्यूड होगा। गवर्नमैंट इस सै ान में पालिसी तय कर ले कि हमारा रवैया पंजाब सरकार के प्रति यह होगा। हिन्दुस्तान की सरकार के प्रति यह होगा क्योंकि कठोर लाइन आफ एक ान तय करके ही इस समस्या का समाधान होगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा।

श्री गुलजार सिंह (राजौंद): सभापति महोदय, चौधरी भाम ोर सिंह जी ने जो प्रस्ताव सदन में पे ा किया है, यह बहुत अहम और जरूरी प्रस्ताव है। पिछले सै ान में भी यह प्रस्ताव सदने में आया था और बहस हुई थी, एक काल अटै- ान मो ान भी आया था। जब तक यह काम पूरा नहीं होगा, इस पर बहस होती ही रहेगी, रूकेगी नहीं, क्योंकि यह बहुत जरूरी मसला है। हमारी सरकार का भी यही नारा है कि 'पानी का प्रबन्ध और भ्रश्टाचार बन्द'। यह नारा बहुत अच्छा है, हमारा फर्ज बनता है कि इसमें सहयोग दें। पानी का प्रबन्ध करने में सरकार बहुत जोरों से काम कर रही है, इसमें काफी कामयाबी भी मिली है, लेकिन मैं यह कहने से हिचक्चाउंगा नहीं कि यह सब भगवान की देन है। इस साल दो तीन मौकों पर बारि ा हुई, लेकिन कई इलाके हैं जहां पानी नहीं बरसा। मैं चाहूंगा कि हमें पंजाब से अपना पानी का हिस्सा लेने के लिये प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि असली हल तभी होगा जब यह पानी मिलेगा। इसके लिये हमारी सरकार रात दिन खूब कोि ा ा करे, चाहे कितना संघर्श क्यों न करना पड़े हमें पानी अव य लेना चाहिये। हम सब सरकार के साथ हैं। यह बहुत ही अहम और जरूरी मसला है। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती भाांति देवी (कैलाना): चेयरमैन साहब, एक बड़े अहम मसले के ऊपर एक आव यक प्रस्ताव भाम ोर सिंह जी ने रखा है। हर बार सै ान के अन्दर यह चर्चा का विशय रहात है

और बड़े बड़े आ वासन हमारे मुख्यमंत्री जी और आई0पी0एम0 साहब देते हैं। यही नहीं, रोज एक स्टेटमैंट अखबारों में भी दे देते हैं। इससे थोड़ी सी खु ी तो हमारे ह्रदय के अंदर आती है कि भाायद पंजाब के साथ पानी का मसला निपट जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि बार बारी आ वासन देने के बावजूद भी बात सिरे नहीं चढ़ रही है। हमारी सरकार कोि ा ा कर रही है कि यह अहम मामला निपटे और हमारा अधिकार हमें मिले लेकिन संदेह यहां होता है कि बात सिरे नहीं चढ़ रही है। इसके बारे में सुझाव तो यह है कि यदि कोई चीज प्यार से न निपटे, दोस्ती से न निपटे तो इंसान को इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिये कि दूसरे ढंग की आवाज न उठाए। मुख्यमंत्री जी और आई0पी0एम0 साहब से मेरी पुरजोर अपील है कि इस मामला को आप छोटा न समझें। मैं मानती हूं कि वे दिल से चाहते हैं। कि हरियाणा का अधिकार हरियाणा को मिले लेकिन इसमें जो रूकावट है वह भी तो उन्हें दूर करनी चाहिये। यदि यह प्यार से दूर नहीं होती तो हमें संघर्श के रास्ते पर चलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिय और अपना अधिकार पंजाब से लेना चाहिये। ठीक है पंजाब हमारा पड़ोसी भाई है, दोस्ती का हाथ हमने उसकी तरफ बढ़ा रखा है लेकिन यह हमारे अधिकार का सवाल है। यदि कोई अधिकार प्यार से न मिले तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अधिकार दूसरे तरीके से भी ले लिए जाया करते हैं। इसीलिये मेरी यह पुरजोर अपील है कि यह मामला इस सै ान में अव य निपट जाना चाहिए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई): चेयरमैन साहब, चौधरी भाम ेर सिंह जी ने जो रैजोल्यू ान पे ा किया है, मैं उसकी पुरजोर ताईद करता हूं और हाउस से प्रार्थना करता हूं कि इसको युनानिमसली पास कर दिया जाए क्योंकि पिछले सै ान में पंजाब असैम्बली ने भी युनानिमसली, चाहे कोई अकाली दल का था, चाहे जनसंघ का था या जनता पार्टी का था या कम्युनिस्ट पार्टी का था, एक रैजोल्यू ान पास किया था कि रावी व्यास का पानी हरियाणा को बिलकुल नहीं दिया जाएगा, चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाबी बोलने वाले इलाके लिए जाएंगे। चेयरमैन साहब, इसी तरह से मैं चाहताहूं कि हम चाहे किसी पार्टी के मैम्बर क्यों न हो, हम सबको 89 के 89 मैम्बर्ज को आज युनानिमसली यह रैजोल्यू ान पास कर देना चाहिये कि रावी व्यास के पानी में हमारा जो हक है वह हमें मिलना चाहिये। बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि आज बी0एम0बी0 का कंट्रोल भी पंजाब के पास है और थीं डैम में हमारा हिस्सा छिन गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह कब तक इस जुर्म को बरदा त करती रहेगी ? इनको याद रखना चाहिये कि जुर्म करना तो पाप है लेकिन जुर्म को सहना महापा है। हमारी जनता सरकार का तो नारा है कि 'पानी का प्रबन्ध और भ्रश्टाचार बन्द'। खैर, भ्रश्टाचार के बारे में तो इस समय बोलूंगा नहीं लेकिन इतना जरूर कहंगा कि इनसे भ्रश्टाचार तो बन्द नहीं हुआ परन्तु पानी बन्द हो गया। (हंसी) मेरा कहने का मतलब यह है कि पानी देने की बजाये पानी बिल्कुल बन्द हो गया। पंजाब सरकार कहती है कि सैन्ट्रल

गवर्नमैंट ने जो अवार्ड दिया है, प्राईम मिनिस्टर ने जो फैसला किया है उसको मानने के लिये वह तैयार नहीं है। उसके बारे में वे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा अपने आई0पी0एम0 साहब से प्राथ्रना करना चाहता हूं कि वे हाथ पर हाथ रख कर न बैठें बल्कि इसके लिये ठोकस कदम उठाएं। पिछले सै ान में यहां कहा गया था कि कि कस्सी मार कर मुख्य मंत्री महोदय नहर की खुदाई का उद्घाटन करेंगे लेकिन वह आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत हरियाणा के हिस्से में 1 नहर की खुदाई पर 100 करोड़ रुपया खच्र हो चुका है। इसमें जा काम हो रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। जनसुई हैड के पास, रावी व्यास के पानी के लिये जो फाल बन रहा है, उसके बारे में वहां के एक मुलाजिम ने मुझे और भाम ेर सिंह जी को बताया था कि चौधरी साहब, वहां जो दीवार बन रही है अगर आप उसका मुलाहिजा फरमायेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह दीवार बनने से पहलें ही गिर रही है क्योंकि पूरा मसाला वहां नहीं लग रहा है। इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। मेरा तो सुझाव है कि हरियाणा में खुदाई बंद करके पंजाब की जमीन में खुदाई भाुरू करनी चाहिये। हमें खु ाी है कि हरियाणा की पंजाब से दोस्ती है लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब को यह बता देना चाहता हूं कि मेरी दोस्ती पंजाब के साथ इनसे ज्यादा है। इनको पता होना चाहिए कि कैथल में जब पुलिस मुकाबला हुआ था मैं पंजाब वालों के गुरूद्वारा में ही गया था, लेकिन दोस्ती का मतलब नहीं कि हम दोस्त सै अपने हम भी न मांगे। अपने हक के लिये

तो भाई भाई में भी लड़ाई होती है। जायदाद के बंटवारे के लिये तो कई बार कत्ल भी हो जाते हैं। चौधरी रिजक राम जी ने कहा था कि इसका फैसला टाईम मुकर्रर करके राउन्ड टेबल पर हो जाए और रावी व्यास के पानी का हिस्सा हमें मिल जाएं, चंडीगढ़ हमें मिल जाए और जितने हिन्दी बोलने वाले इलाके पंजाब में हैं वे भी हमें मिल जाएं या कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए। अफसोस से कहना पड़ता है कि हालांकि पंजाब का चंडीगढ़ में कोई हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कब्जा जमाने के लिये 1300 मकान यहां बनाने का फैसला कर लिया है। सरकारी बैंच तो सरकार के साथ हैं ही लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस मामले में जनता भी इनके साथ है। इसलिये इनको चाहिए कि इसके लिये ये कोई दिन मुकर्रर कर दें ताकि इतने दिन के अंदर अंदर हमें हमारा हक मिल जाना चाहिये। दोस्ती की बात भी आप देख लें। रावी व्यास का पानी पाकिस्तान को जा रहा है। पंजाब वाले पाकिस्तान को तो पानी दे रहें हैं, लेकिन हरियाणा को नहीं दे रहे हैं इसलिये चेयरमैन साहब, मैं चौधरी साहब को कहना चाहता हूं कि ज्यादा दब कर काम नहीं चलेगा। आज हरियाणा का बच्चा बच्चा कहता है कि हरियाणा सरकार पंजाब से बहुत दब चुकी है। यही नहीं, पंजाब ने तो यह भी दबाव डाला है कि पंजाबी को हरियाणा में लागू किया जाए। हम पंजाबी के खिलाफ नहीं है लेकिन जब तक हिन्दी बोलने वाले इलाके, जैसे खनौरी के पास 30–32 गांव हैं, डेरा बसी है, खरड़ तहसील है, लालडू है, ये सभी ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक यहां

पंजाबी लागू न की जाए। हर झगड़े का जल्दी से इलाज किया जाए ताकि दोनों सूबे मिल कर रह सकें। (विघ्न) तो मैं ज्यादा न कहता हुआ सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस रैजोल्यू ान को युनानिमसली पास किया जाना चाहिये और पंजाब के सामने बिल्कुल घुटने नहीं टेकने चाहिएं।

श्री इन्द्रजीत सिंह (जाटुसाना): चेयरमैन साहब, जब भी हम सै ान में आते हैं, हर बार यह सवाल आता है और हर बार हमें यह जवाब मिलता है, गवर्नमैंट की तरफ से कि हम रावी व्यास के पानी को लेंगे और यह जो पहले डिसीजन हुआ था, इसको इम्पलीमैंट कराया जाएगा। आखिकर कब तक हम इंतजाचर करेंगे। दो साल जनता पार्टी की सरकार को बने हो गये हैं इस अर्सा में सिर्फ बातें ही बातें हुई हैं, कोई कंकरीट स्टैप्स नहीं लिए गए हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि वैसे तो यह अफसोस की बात है कि यह सरकार दो साल तक इस छोटे से मसले को हम करने में असफल रही है और हरियाणा प्रान्त के लोगों को उनका वाजिब हक नहीं दिला सकी है। फिर भी इस सै ान में जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है, कुछ कंकरीट स्टैप्स लिए जांए और उनको जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट किया जाए। मुझे आ ाा है कि मिनिस्टर साहब इसके बारे में अव य कुछ कहेंगे। इन भाबदों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

18.00 बजे।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): चेयरमैन साहब, बात यह है कि हरियाणा को पानी की आव यकता है परन्तु मेरी समझ में तो यह बात नहीं आ रही है कि पानी के पीछे हमारे अपोजि ान के साथी या दूसरे साथी गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं। मुझे तो इसमें सरकार का कोई कसूर नजर नहीं आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि यह बहुत पुरानी बीमारी है। एकदम से नहीं जा सकती है लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि इस विशय में हमारे मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार से तथा पंजाब सरकार से बात की है। वे दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं। वे दिल्ली में दिन रात इस बारे में भागदौड कर रहे हैं। पंजाब सरकार से भी विचार विम र्श करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्री भाम ेर सिंह जी मुझे इस बारे में कोई कमी नजर नहीं आती है अगर कमी है तो वे बतायें, हम भी उनके साथ हैं। हम किसी बात में उनसे पीछे नहीं हैं। अगर सगे भाइयों में भी जमीन जायदाद पर झगड़ा हो जाता है तो उसका समझौता करने में भी टाईम लग जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि इस सरकार पर गुस्सा निकालनने की अपेक्षा पंजाब सरकार से मिलें। यह गड़बड़ तो पिछली सरकार करके चली गई है। उनको पहले ही जल्दी से जल्दी इसका प्रबंध करना चाहिये था। हमारे सिंचाई एवं मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी छोड़ी हो तो वे बतायें। पंजाब के बार्डर पर जलसा था तो वहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जितने भी यहां पर भाई बैठे हैं वे हमारी इस काम के लिये मदद करें। यहां असैम्बली में रौला मचाने का मुझे कोई लाभ प्रतीत नहीं हो

रहा है। वे हमारे पड़ौसी भाई हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए और अपना हक मांगना चाहिये। हम भी उनसे बात करने के लिए तैयार हैं और आप लोग भी साथ चलें। प्रेम से यह बात हली हो सकती है। लेकिन यहां हाउस में गलत बात कहना ठीक नहीं । हम गलत बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तरफ यहां एम0एल0ए0 आकर मिनिस्टरों से कहते हैं कि आप मेरे हलके में चलें और कुछ वहां पर काम करवायें, दूसरी ओर यहां हाउस में बैठ कर टूर के बारे में, पैट्रोल के बारे में चर्चा करते हैं कि वे वहां पर क्यों जाते हैं ?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चौधरी लाल सिंह इररैलवेंट बोल रहे हैं उन्हें हीस सबजैक्ट पर ही बोलना चाहिए।

चौधरी लाल सिंहः चेयरमैन साहब, पहले वाली सरकार इस झगड़े को बीच में ही छोड़ कर चली गई थी लेकिन अब हमारी सरकार दिन रात इस झगड़े को हल करने पर लगी हुई है। मुझे तो सरकार की ओर से कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। हमारे सिंचाई मंत्री जी दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं। अगर हमारे सिंचाई मंत्री जी को अपने ही खेत में पानी लगवाना होता तो भी वे इतना प्रयत्न न करते जिता प्रयत्न आज हरियाणा के हिस्से को लेने के लिये कर रहे हैं। यह सारी चीजें मैंने अपनी आंखों देखी है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पिछली सरकार के मंत्रियों का बिजली का बिल, साठ साठ हजार रुपये का देखा है। आज हम इनके टूअर्ज को बंद करेंगे तो काम कैसे चलेगा मेरे पास पिछली मिनिस्टरी के आंकड़े हैं। इसलिये किसी बात की नुक्ताचीनी करें तो उसमें वजन होना चाहिए। आज अगर हम अपने मिनिस्टर्ज के टुअर्ज बंद करेंगे तो हरियाणा के लोगों के काम किस प्रकार से होंगे ? इसलिये चौधरी भाम ोर सिंह जी ने जो लिखा है, इसमें हमारी सरकार का दोश तो मुझे नजर ही नहीं आता। आप कोई कमी देखते हैं तो उसकी नुक्ताचीनी अव य करें लेकिन उसमें वजन होना चाहिए। मैं तो फिर यही निवेदन करूंगा कि हमें पंजाब के भाइयों से इस विशय पर बातचीत करनी चाहिये। यह कहना गलत है कि जब हम लड़ाई लड़ेगें तभी पानी मिलेगा। (विघ्न)

श्री सभापतिः चौधरी पोहलू जी आप इन्टरफियर न करें।

चौधरी लाल सिंहः चेयरमैन साहब, इन सभी भाइयों को पता है कि जो काम पिछली सरकार ने तीस साल में नहीं किया था वह इस सरकार ने थोड़े ही दिनों में कर दिया है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः चेयरमैन साहब, ये तो पहली सरकार में भी भागिल थे।

चौधरी लाल सिंहः मैं कहां था। मैं उस सरकार में मिनिस्टर नहीं था, आप ही मिनिस्टर थे। चेयरमैन साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि चौधरी भाम ेर सिंह जी को कोई एतराज है तो वे उनसे मिलकर बात करें लेकिन सरकार पर गुस्साच निकालने की कोई बात नहीं है। हम पंजाब सरकार से बात करें। वे सैंटर में अपना रसूख इस्तेमाल करके इस समस्या को हल करवायें। हम भी चाहते हैं और अपोजी ान के भाई भी चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। यहां पर यह कहा गया कि डिफैंस मिनिस्टर ने दबाव से पानी का फैसला करवाया था।

श्री भाम ेर सिंहः मैंने यह कभी नहीं कहा कि डिफैंस मिनिस्टर ने दबाव से यह फैसला करवाया था। यह बिलकुल गलत बात है।

चौधरी लाल सिंहः मैं यह नहीं कहता कि आप ने यह कहा है कि डिफैंस मिनिस्टर साहब के दबाव से यह फैसला हुआ था। मैं तो यह कह रहा हूं कि पंजाब वाले कहते हैं कि डिफैंस मिनिस्टर ने पहली प्रधान मंत्री से यह फैसला करवाया था।

स्वामी जी ने यहां पर एक बात कही कि नौजवानों को बेरोजगारी का पचास रुपये महीना भत्ता दिया जाये। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि अभी हमारी सरकार की ओर से 15 तारीख को एक बहुत बड़ी स्कीम निकाली जा रही है जिससे बेरोजगार लोगों का बहुत भला होनी की संभावना है। इसलिये

स्वामी जी को अपने हलके में जा कर यह स्कीम लागू करवानी चाहिये।

स्वामी आदित्यवे I: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि सतलुज यमुना लिंक के विशय पर ही बोलें तो अच्छा रहेगा। उनको किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहिए।

चौधरी लाल सिंहः बस जी, मैंने तो यही अर्ज करनी थी। चेयरमैन साहब, सच्चाई हमे ाा होनी चाहिए। अगर कोई गलत बात होती हो तो हम वह भी कहने के लिये तैयार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार की ओर से इस बारे में कोई कसर नहीं है। धन्यवादं

कंवर राम पाल सिंह (घरौंड़ा): चेयरमैन साहब, एस0वाई0एल0 का मसला आज रैजोल्यू ान के जरिये से इस हाउस में सिर्फ पहली बार नहीं उठ रहा है, पिछले सै ान में भी यह मसला उठा चुका है। इस पर उस समय बहस भी हुई थी ? उस समय भी सरकार ने इस सदन को यह वि वास दिलाया था कि हमारा जो हिस्सा है जो सैंट्रल गवर्नमैंट ने अवार्ड दिया है, उसके ऊपर कायम है। यही नहीं, हमें यह भी वि वास दिलाया गया था कि पंजाब के एरिया मके अंदर बहुत जल्दी ही यह लिंक चैनल की खुदाई का काम भाुरू होने वाला है। इस विशय में एक नोटिसफिके ान भी यहां हाउस के अंदर पढ़ कर सुनाया गया था

कि जमीन एक्वायर कर ली गयी है और तिथि बताई गयी थी कि इस दिन दोनों मुख्य मंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। दोबारा यह मसला इस हाउस के अंदर इसलिये लाने की आव यकता महसूस हुई कि हरियाणा के विधायक ही नहीं, बल्कि तमाम हरियाणा की जनता आखें फाड़ फाड़ कर देख रही है कि कब एस0वाई0एल0 का काम भुरू होता है। कब एस0वाई0एल0 नहर का पानी हरियाणा की भूमि पर मिलता है। इससे हरियाणा के लोगों को फाइनैंि ायल लास भी हो रहा है। वह कब पूरा होता है ? इन सब बातों को देखते हुए, यहां पर बार बार ए योरैंस मिलने क बावजूद भी कोई कार्य भुरू नहीं हुआ तो लोगों को दोबारा अपनी आवाज उठानी पड़ी जिसकी वजह से आज रैजोल्यू ान फिर यह हाउस के अंदर लोने की आव यकता महसूस की गयी। ठीक है, मैं मानता हूं कि सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है, कई एक मीटिंग भी हुई हैं। अखबरों में हमारे सिंचाई मंत्री जी का एक ब्यान जो उन्होंने पिछले दिनों दिया था छपा था लेकिन हमें बार बार सं ाय इसलिये हो रहा है कि इस दि ाा में अभी तक कोई प्रोग्रैस नहीं हुई है जबकि जमीन एक्वायर करने के लिये हरियाणा सरकार ने पैसे जमा करा दिये। खेद का विशय है कि अभी तक भी वह जमीन एक्वायर नहीं हुई। जमीन एक्वायर न होने के कारण हमारी समझ में नहीं आया। इससे एक बात साफ नजर आती है कि हमारा पड़ोसी भाई हमारे इस कार्य को आगे चलता हुआ देखना नहीं चाहतां वह दिन व दिन कोई न कोई नया मसला उठाकर, कोई न कोई बहाना निका लकर सैंट्रल गवर्नमैंट के पास

चला जाता है। उसके बाद हम मीटिंगों के चक्कर में उलझ जाते हैं। मैं तो अपनी सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि यह मीटिंगें बहुत दिनों तक नही चलनी चाहिए और लोगों को जो वि वास है कि हमारी सरकार बड़ी मेहनत के साथ बड़े हौसल के साथ अपने हक को लोने के लिये जद्दोजहद कर रही है, वह पूरा होना चाहिए। हरियाणा की सरकार पंजाबी की टैरीटरी के अंदर जल्दी से जल्दी काम कराये। हरियाणा को जो फाइनैंि ारूल लास हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जैसे मैंने जिक्र किया है, इस सदन से मैं आ ाा करता हूं कि सदन सरकार को यह कहेगी कि सैंट्रल गवर्नमैंट से यह कहे कि वह अपने उस आदे ा का सख्ती से पालन करवाये। नोटिफिके ान करने से या अखबारों में ब्यान आ जाने से यह मसला हल होने वाला नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि हमारी सरकार सैंट्रल गवर्नमैंट से जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, इसको इम्पलीमैंट करने के लिये फैसला करवाये। जितना जल्दी ये ऐसा फैसला करवायेगी, उतना ही जल्दी यह सरकार लोगों का वि वास प्राप्त कर सकेगी। इससे लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति वि वास ही नहीं पैदा होगा बल्कि यह लोगों के प्रति एक बड़ी भारी सर्विस होगी। मैं यह आ ाा करता हूं कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके, सुलझाने का प्रयत्न करे। हमारी सरकार, पंजाब सरकार के साथ अगर नेगो ीिये ान कर के फैसला करने के लिये तैयारनही है तो सैंट्रल गवर्नमैंट से यह प्रार्थना करे कि जैसे हैडवर्कस के बारे में उन्होंने फैसला किया था कि वहां पर कुछ कामों को डिवाईड कर दिया जाये या

दोनों का कंट्रोल वहां पर होना चाहिए। थीं डैम का मसला भी नहीं सुलझा पाये हैं। इधर एस0वाई0एल0 का मसला ज्यों का त्यों खड़ा है। वे इस कलसे को न सुलझाने के लिये दो तीन मसले और खड़े कर देते हैं। इसयि मैं यह चाहूंगा कि हमारी सरकार सैंट्रल गवर्नमैंट से जल्दी से जल्दी इस अवार्ड को इम्पलीमैंट कराने के लिये प्रयत्न करे। अगर पंजाब वाले नैगोि ाये ान से कोई बात नहीं मानते तो सरकार के पास दूसरे कई तरीके हैं, उन तरीको ंसे इम्पलीमैंट करवावने के लिये कहें। मैंने जो सुझाव दिये हैं, उनको माानने के लिये सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिये हरियाणा के इन्ट्रैस्ट को सामने रखते हुए सैंट्रल गवर्नमैंट से यह प्रार्थना की जाये कि हाउ की यह फीलिंग्ज हैं। हम इस रैजोल्यू ान को पास करके उसके पास भी भेंजे और कहें कि हाउस में यह मसला बार बार उठता है। हसलिये इसके बारे में कोई न कोई फैसला जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट कराया जाये ताकि हरियाणा के लोगों को जो बेचैनी है, हरियाणा के लोगों के मन में जो भाको Iुबह है, वह दूर हा सकें और वे भाान्तिपूवर्क रह सकें। अगर ऐसा नहीं होता है तो एस0वाई0एल0 स्कीम के लिये हरियाणा सरकार ने जो करोड़ों रुपया खर्च किया है, और भी खर्च कर रही है वह सारे काच सारा बेकार हो जायेगा। जो काम हो चुका है अगर उसमें चूहों ने अपनी खुडडें बना लीं तो उनकी रिपेयर करने के लिये ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 प्रति ात रुपया लगेगा। जितना रुपया इसके बनाने पर खर्च आयाहै, उनता ही रिपेयर करने पर लग जायेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है

कि इन सारी बातों को देखते हुए सरकार पंजाब की टैरीटरी के अंदर जमीन एक्वायर कने के बाद सैंट्रल गवर्नमैंट से यह फैसला कराकर लाये कि हमारे इंजीनियर्ज ही वहां पर जाकर पंजाब की टैरीटरी के अंदर नहर की खुदाई का काम करवायेंगे क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्ज होंगे, उनको लग्न होगी, वे हरियाणा की इन्ट्रैस्ट को ज्यादा अच्छी तरह से वाच कर सकेंगे। दिन रात लगाकर इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोि ा ा करेंगे। फिर वह बात न हो सकेगी जो पंजाब वालों ने अब की है कि लैंड एक्वायर करके दिन ब दिन देर करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वहां पर हम यह काम पंजाब के इंजिनियर्ज को दे देंगे तो हो सकता है वह इसको पूरा करने में 10 साल लगा दें। इसलिये सैंट्रल गवनमैंट से यह भी कहा जाये कि हमारे इंजीनियर्ज ही वहां पर इसे बनायेंगे, तभी हमें कुछ लाभ हो सकता है। इन भाब्दों के साथ मैं अपनी सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि वह सैंट्रल गवर्नमैंट से कहे कि वइ इस अवार्ड को जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट कराने के लिये कोई डायरैक ान दे ताकि हमारे इंजीनियर्ज ही इस नहर को बनाये। धन्यवाद।

स्वामी अग्निवे ा(पुंडरी): आदरणीय सभापति महोदय, सतलुज यमुना लिंक के ऊपर आज जो प्रस्ताव आया हे, उसके ऊपर हरियाणा विधान सभा में बहस एक रस्मी सी हो गई है कि जब भी हम सदन में इकट्ठे हों, इस सम्बंध में कुछ बातें कहें जिससेयह पता लगे कि हरियाणा वाले कुछ भाोर मचा रहे हैं। मैं

यह कहना चाहता हूं कि जिनके मुकावले में हम भाोर मचा रहे हैं। वह इस भाशा का समझने वाले नहीं हैं और जो भाशा वह चाहते हैं वह भाशा हम बोल नहीं सकते। सतलुज व्यास का प्र न हरियाणा की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी गम्भीरता को देखते हुए हमारी चीफ मिनिस्टर महोदय ने इसी हाउस में यह घोशण की थी कि अगर मैं हरियाणा को रावी व्यास का पानी नहीं दिला सकता तो मैं मुख्य मंत्री पद से अस्तीफा दे दूंगा। मैं यह कहूंगा कि यह उनकी अकेले की घोशणा नहीं थी बल्कि इसमें प्रत्येक विधायक का इस्तीफा भाामिल था। सभापति महादेय, जब यह मामला इतना गम्भीर है जिसके लिये हरेक व्यक्ति एक स्वर से लड़ने मरने के लिये तैयार है और उसके बावजूद भी हम अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जो तरीका है, जो हमने स्वीकार किया हुआ है, उमसें कहीं कोई खामी अव य है। हर बार हम यह कहते हैं कि पंजाब वाले हमारा अधिकार नहीं दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब वाले यह अधिकार नहीं देंगें और इस बात को वह पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने प्रस्ताव पास भी कर दिया है कि हम नहीं देंगे। अब हमारी किस्मत है कि हम उनसे ले सकते हैं या नहीं। इस बारे में अवार्ड केन्द्र का का है और वह लागू क्यों नहीं हो रहा है ? सभापति महोदय, अगर वह लागू नहीं करते तो मेरी बात कठोर जरूर हो सकती है और सदन इसके लिए मुझे क्षमा करेगा कि केन्द्रीय सरकार रहने लायक नहीं हैं ऐसी कौन सी बात है कि हमारी सरकार है और हमें हमारा हक नहीं दिला सकती ? मैं यह

निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई मंत्री यहों बैठे हैं, मुख्य मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं, और दूसरे मंत्री भी हैं। इस बारे में कैबिनिट की एक आपातकाली बैठक बुलाएं जिसमें अपोजि ान के सदस्य भी हों। यानी सदन के 90 के 90 सदस्य भाामिल हों और उस बैठक में यह फैसला किया जाए कि आने वाले पन्द्रह बीस दिन के अंदर जब तक कि इस सदन की बैठक चले, केन्द्र कोई इंस्ट्रक ांज जारी करके हमें हमारे अधिकार दिलाए। केन्द्रीय सरकार जब तक अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करके पंजाब को मजबूर नहीं करेगा, तक तक कुछ नहीं होगा। अगर केन्द्र ऐसा नहीं करता तो हम सारे के सारे 90 सदस्य दिल्ली जाकर प्रधान मंत्री के दरवाजे पर भूख हड़ताल कर देंगे। मैं समझता हूं कि अपने पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग अगर ऐसा करने के लिये तैयार होंगे तो हरियाणा का बच्चा बच्चा वहां पर जाकर भूख हड़ताल करने के लिये तैयार है। मैं समझता हूं कि जिस दिन यह सदन इस प्रकार का फैसला कर लेगा, केन्द्र आपको अपना अधिकार दे देगा। अगर आप यह सोचते हैं कि हर बार यहां आकर इस बारे में रस्मी कार्यवाही पूरी कर लें और थोड़ी बहुत बात कर लें तो कुछ होने वाला नहीं हदै। इस विधान सभा की इतनी बड़ी भावना की कोई परवाह नहीं की जा रही है और हमारा हिस्सा हमें नहीं दिया जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है जैसे हम भिखारी बने बैठे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमें धक्का दिया जा रहा है और दूसरी कई चीजों के अंदर हमें धक्का दिया जा रहा है। अगर वाकई हमारा उद्देश्य है कि हमने पानी लेना है और

इस मामले में वाकई अगर हम सीरियस हैं तो यह तरीका होना चाहिये कि हम सत्याग्रह का फैसला करें। ऐसा करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें केन्द्रीय सरकार को कह देना चाहिए कि या तो वह हमारे अधिकार दिलाए, नहीं तो हम हड़ताल पर बैठते हैं और सभापति महोदय, मैं अपने आपको इस कार्य के लिए प्रस्तुत करता हूं। जिस समय आप चाहेंगे कि मैं हड़ताल, भूख हड़ताल, धरना आदि पर बैठूं तो मैं उसके लिये तैयार हूं। (व्यवधान) लेकिन इसके लिये सदन की पूरी राय होनी चाहिये (व्यवधान) मेरा कहना यही है कि आप इस मसले का गंभीरता से लें। यह मसला हरियाणा के एक करोड़ बीस लाख लोगों की जिन्दगी का मसला है। सभापति जी, आप देख रहे हैं कि इतने बड़े मसले पर बहस हो हरी है लेकिन मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे कई साथी इस सदन में नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हम लोग किस बात के लिये भत्ता ले रहे हैं ? अब हरियाणा का सबसे बड़ा सवाल आया है तो यहां पर बैंचिज खाली पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार अपने हिस्से को लेना नहीं चाहती है और अगर लेना चाहती है तो वह सीरियस नहीं है। इसलिए मैं आदरणीय वीरेन्द्र सिंह जी से यह अनुरोध करूंगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से वह तारीख मुकर्रर होनी चाहिए कि किस तारीख तक वह केन्द्र से यह उम्मीद रखती है। अगर उस तारीख तक हमारा फैसला नहीं हो पाता, हमारी नहर खुदनी भाुरू नहीं हो जाती हैं, हमारा काम भाुरू नहीं

हो जाता तो हम सारे के सारे सदस्य इस्तीफा दे देंगे। इस बात की घोशणा हमारे सिंचाई मंत्री की ओर से होनी चाहिये।

श्री भाम ोर सिंह: चेयरमैन साहब, इस रैजोल्यू ान के लियें साढ़े छः बजे तक का टाईम दिया था और वह टाईम हो गया है या तो आप हाउस का टाईम ऐक्सटेंड करें या रैजोल्यू ान को वोट के लिये पे ा करें। हमने आरम्भ में ही जब इस रैजोल्यू ान को पे ा किया था यह कहा था कि कम से कम इस रैजोल्यू ान के पीछे जो भावना हे, जो स्पिरिट है उसका ध्यान रखा जाए और उसको पोलीटीक्लाइज न किया जाए। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि टाईम ऐक्सटैंड करके मिनिस्टर महोदय से इसका जवाब दिलवाया जाये।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिह): अगर सदस्य बोलना चाहते हैं तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूं यह बड़ा इम्पोरटैंट मसला है इसलिये सदस्यों को बोलने देना चाहिये।

स्वामी अग्निवे ा: सभापति महोदय, दोपहर को इस बारे में बात भी हुई थी और आपने कहा था कि पौने सात बजे तक इसको रखा जाए। सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब पंजाब वाले जमीन एक्वायर नहीं होने दे रहे हैं और उन्हौंने अभी तक एक इंच भी बनाना भाुरू नहीं किया है तो आप हरियाणा के अंदर लगातार पैसा क्यों लगाते चले जा रहे हैं ? यह बात राज्यपाल के अभिभाशण में भी कही गई है कि

27 से 37 करोड़ रुपया सरकार इस साल इस काम पर खर्च करने जा रही है। कम से कम यह पैसा तो हम बचाएं। मेरा नम्र अनुरोध है कि एस0वाई0एल0 पर अब पैसा खर्च करना बंद कर दें मैं समझता हूं कि हम सब विधायक इस बात से सहमत होंगे कि सत्याग्रह करने के लिये भी तारीख आज ही मुकर्रर हो जानी चाहिये।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

स्वामी आदित्यवे ा(हथिन): अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विपक्ष के साथी श्री सुरजेवाला ने जो प्रस्ताव रखा है, यह बड़ा गम्भीर और आव यक प्रस्ताव है। इस पर कोई पहली बार विचार नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत बार इस तरह के रैजोल्यू ान पर विचार किया जा चुका है। पिछले सै ान में इस संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव आया था जिस पर काफी डिस्क ान हुआ था और उसके प चात भी इस समस्या पर काफी चर्चा होती रही है। लेकिन जैसा कि मेरे माननीय साथी स्वामी अग्निवे ा ने कहा कि जब तक हम कुछ कठोरता का रूख नहीं अपनाएंगे तब तक एस0वाई0एल0 लिंक की बात करना निरर्थक है और उससे एक टपका पानी मिलने की भी उम्मीद नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि आज हमें सबको मिलकर एक प्रस्ताव बड़ी जिम्मेवारी के साथ केन्द्र सरकार को भेजना चाहिये कि यदि इस नि चित तिथि तक, इस सै ान की समाप्ति तक हमारी मांग पूरी

न की गई तो हम नि चत रूप से, जैसा कि हमारे प्रजातन्त्र में हमें अधिकार हैं, हम आन्दोलन का रूप अपनायेंगे।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, टाईम हो गया है .....

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मसला है ..... हमें इस पर बोलने के लिये समय मिलना चाहिये .....

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, टाईम हो गया है, मैं आप से रिक्वैस्ट करूंगा कि आप समाप्त करें। (ाोर)

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, यह तो हाउस की सैंस पर निर्भर करता है कि टाईम बढ़ाना चाहिए या नहीं या 8 तारीख को इसी प्रस्ताव को कंटीन्यू रखें। इस पर अभी बहुत सारे मैम्बर साहिबान बोलना चाहते हैं और फिर मिनिस्टर महोदय भी जवाब देना चाहेंगे।

स्वामी आदित्यवे ाः स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि ..... (ाोर)

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, आप त ारीफ रखिये, आप दूसरों को भी कुछ कहने का मौका दें।

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मसला है, इस मसले को बे ान मुलतबी करके आठ तारीख पर रख लीजिये। हम इसका पूरा जवाब देना चाहते है।

श्री अध्यक्षः अगर हाउस की यह सैंस हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः 8 तारीख को चार प्रस्ताव और भी होंगे, उन में इसको भी फिट इन कर देंगे और अगर जरूरत महसूस हुई तो उस दिन समय बढ़ा देंगे।

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि 8 तारीख को यह प्रस्ताव पहले नम्बर पर आना चाहिये।

श्री अध्यक्षः ठीक है 8 तारीख को यह प्रस्ताव पहले नम्बर पर आयेगा।

Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 2nd March, 1979.

***18.30 hours**

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Friday, the 2nd March, 1979)